



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1999/चैत्र 6, 1921

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1999/CHAITRA 6, 1921

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांख्यिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministry of the Government of India  
(Other than the Ministries of Defence)

कार्मिक लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक, और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1999

का.धा. 824 :—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस  
स्थापना अधिनियम 1946 (1946 का अधिनियम  
सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा  
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक  
22 जनवरी, 1999 के गृह सचिव के सहमति पत्र गृह  
(पुलिस) अनुभाग-II संख्या 311-टी/6-11/99-557/एम/97-  
लखनऊ द्वारा प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सह-  
मति से पुलिस स्टेशन केन्द्रीकृत इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश  
में दर्ज किए गए अपराध सं. 489/98 के मामले में  
संबंधित भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का अधिनियम  
सं. 45) की धारा 420, 467, 468, 352, 504, 506  
तथा 120-बी के अन्तर्गत दंडनीय अपराधों और ऊपर वर्णित  
अपराधों के संबंध में या उनसे संभवतः प्रयत्न, दुष्प्रेरण और

षड्यंत्र तथा वैसे ही संभवहार के अनुक्रम में अथवा उन्हीं  
तथ्यों से उद्भूत किया गया या किए गए किसी अन्य अप-  
राध प्रथवा अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली  
विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधि-  
कारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में  
करती है।

[सं. 228/3/99-ए.बी.डी.-II)]

हरि सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 9th March, 1999

S.O. 824.—In exercise of the powers conferred by sub-  
section (1) of Section 5 read with Section 3 of the Delhi  
Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946),  
the Central Government with the consent of the State Gov-  
ernment of Uttar Pradesh vide Home (Police) Section II,  
Notification No. 311-T/6-11/99-557 M/97 dated 22-1-1999,  
hereby extends the powers and jurisdiction of the members  
of the Delhi Special Police Establishment to the whole of

the State of Uttar Pradesh for the investigation of offences punishable under Sections 420, 467, 468, 352, 504, 505 and 120-B of the Indian Penal Code, 1860 of case Crime No. 489/98 of Police Station Cantt., Allahabad, Uttar Pradesh and attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with the offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/3/99-AVD-II]  
HARI SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1999

का.आ. 825:—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिट याचिका सं. 15070 (डब्ल्यू)/98 पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के तारीख 27-10-1998 के आदेश के अनुसार, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363 के अधीन दंडनीय अपराध के और उपरोक्त लिखित किए गए अपराध के और कलकत्ता के बाउवबाजार पुलिस थाना के केस एक आईआर सं. 150/98 तारीख 6-6-1998 के, जो श्री अनूप भट्टाचार्य की पत्नी श्रीमती केया भट्टाचार्य के नवजात पुत्र की, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कलकत्ता में 27-5-1998 से 4-6-1998 की अवधि के दौरान नवजात बालिका शिशु के साथ बदले जाने के अभिकथन से संबंधित है, अपराध के तथ्यों से उद्भूत होने वाले या वैसे ही संभवहार के संबंध में या उनसे संसक्त प्रत्यन, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण पश्चिमी बंगाल राज्य पर करती है।

[सं. 228/12/99-ए.वी.डी.-II]

हरि सिंह, अवसर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1999

S.O. 825.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government as per the directions of the Hon'ble High Court of Calcutta at Calcutta dated 27-10-1998 in Writ Petition No. 15070(W)/98, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of the West Bengal for the investigation of offence punishable under section 363 of the Indian Penal Code, 1860 and attempt, abetment and conspiracy in relation to or in connection with the offence or offences committed in the course of same transaction or arising out of the same facts of case FIR No. 150/98 dated 6-6-1998 of Police Station Bowbazar, Calcutta relating to the allegation of change of a male baby with a female baby of

Smt. Keya Bhattacharjee wife of Shri Anup Bhattacharjee in the Medical College Hospital, Calcutta during the period from 27-5-1998 to 4-6-1998.

[No. 228/12/99-AVD. II]  
HARI SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1999

का.आ. 826.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक आदेशों के अनुसरण में पारित भारत के उच्चतम न्यायालय के अपर रजिस्ट्रार के दिनांक 12-5-1998 और 21-7-98 के आदेश सं. एक ओ/एससीआई/98 के अनुसार अधीक्षण अभियंता, उप्पड़ बाड़ी दोआब कनाल सर्कल, अमृतसर के कार्यालय के अंश IV के कर्मचारियों की सेवाएं संपादन करने के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रतीत होने वाले 25 फर्जी जाली स्थापन आदेशों तथा डब्ल्यू पी (सी) सं. 753-ए/98 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रतीत होने वाले एक फर्जी और जल्दी स्थापन आदेश से संबंधित अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण पंजाब राज्य पर करती है।

[सं. 228/13/99-ए.वी.डी.-II]

हरि सिंह, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th March, 1999

S.O. 826.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government as per the Order Nos. FO/SCI/98 dated 12-5-1998 and 21-7-1998 of the Additional Registrar, Supreme Court of India passed in pursuance of the administrative orders of Hon'ble Supreme Court, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Punjab for the investigation of offences relating to 25 fake and forged stay orders purported to be issued by the Hon'ble Supreme Court against the termination of services of class IV employees of the Office of Superintending Engineer, Uppar Bari Doab Canal Circle, Amritsar and one fake and forged stay order purported to be issued by the Hon'ble Supreme Court in WP(C) No. 753-A/98.

[No. 228/13/99-AVD. II]

HARI SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 9 नवम्बर, 1998

आयकर

का. आ. 827:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संघर्ष के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई शर्तों को पूर्ण किया गया संवर्धित छूट के तहत में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्च फाउण्डेशन  
(एसआई आई आर एफ) सरोश भवन,  
16-बी/1, डा. अम्बेडकर रोड,  
पूना-411001।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संघर्ष के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को

नीचे प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में कि, आवेदन-पत्र को विभाग को प्रेषित करना है। उक्त आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए मोश्रा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजनी है।

[संख्या : 1866/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट) / एम.-41/35(1)(ii) / 90-91]

मुकेश कुमार, अपर महानिदेशक आयकर (छूट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF INCOME TAX (EXEMPTIONS)

Calcutta, the 9th November, 1998

INCOME TAX

S.O. 827.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Serum Institute of India Research Foundation  
(SIIRF) Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr.  
Ambedkar Road, Pune-411001.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax (Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1866 F. No. DG/IT(E)/M-41/35(1)(ii)/90-91]  
MUKESH KUMAR, Addl Director of  
Income-Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 13 नवम्बर, 1998

आयकर

का. आ. 828:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संघर्ष के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एस. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन

3 रा क्रोस रोड, तारामनी इंस्टीट्यूट एरिया,  
चेन्नई-600113

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संघर्ष के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को मुद्दाव दिया जाता है कि अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1867/एफ. सं. म. नि. /आ. क. (छूट) / टी.  
एन.-5 कल./35 (1) (ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक, आयकर (छूट)

Calcutta, the 13th November, 1998

#### INCOME TAX

S.O. 828.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax (Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

M. S. Swaminathan Research Foundation, 3rd Cross Road, Taramani Institutional Area, Chennai-600113.



This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Note : 1. Condition (1) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1867/F. No. DG|IT(E)|TN-5|CAL|35(1)(ii)|  
90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of  
Income-Tax (Exemptions)

आयकर

कलकत्ता, 16 नवम्बर, 1998

का. आ. 829.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (II) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, “प्रौद्योगिक भवन” न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

हाफकिन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड टेस्टिंग,  
आचार्य डोन्डे मार्ग, पारेल, मुम्बई-400012।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) “संव” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र की छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1868/एफ.सं. म.नि./आ. क. (छूट)/एम. 119/  
कल./35 (1) (II)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर, (छूट)

INCOME TAX

Calcutta, the 16th November, 1998

S.O. 829.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan” New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Haffkine Institute for Training Research and Testing, Acharya Donde Marg, Parel Mumbai-400012.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-1999.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1868/F. No. DG/IT(E)/M-119/CAL/35(1)(ii)-90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax (Exemptions)

आयकर

कलकत्ता, 16 नवम्बर, 1998

का. आ. 830:—सर्वसाधारण को एनद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संग्रह के अधीन अनुमोदन किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सन्धता मेडिकल रिसर्च सोसाइटी,  
एक्सटेंशन एरिया, मिराज—416410।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जमासंग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन का सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उक्त आवेदन पत्र की छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीवा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1869 एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/एम.-44/कल./35(1)(ii)/90-91]

सुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर, (छूट)

## INCOME TAX

Calcutta, the 16th November, 1998.

S.O. 830.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sandhata Medical Research Society. Extension Area, Miraj-416 410.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1869 F. No. DG/IT(E)|M-44|CAL/35(1)(ii)|90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 16 नवम्बर, 1998

#### आयकर

का.आ. 831.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(i) में रिमूव किये गये कार्यों से संबंधित दो गई छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

इंडियन इंस्टीचूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पवई, मुम्बई-400076

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त जर्न (i) "अब" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन कर, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की प्रति विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजनी है।

[संख्या : 1870/एफ. सं. म.-नि./आ.क. (छूट)/एम.-121 कल./35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 16th November, 1998

#### INCOME TAX

S.O. 831.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Indian Institute of Technology Powai  
Mumbai-400076.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2000.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director

General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1870|F. No. DG|IT(E)|M-121|CAL|35(1)(ii)|90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 20 नवम्बर, 1998

आयकर

का.आ. 832 :—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, “प्रौद्योगिकी भवन,” न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली - 110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा - परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) में रिसर्च किये गए कार्यों से संबंधित दी गई छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ कन्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च (एन.आई.सी.एम.ए.आर.) वालचंद टेरसेस, टारडीओ रोड, मुम्बई-400034

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपयुक्त शर्त (i) “संव” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर

आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की प्रति विभाग को प्रस्तुत करता है। उक्त आवेदन पत्र की छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजता है।

[संख्या : 1871/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/एम.-110 35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 20th November, 1998

### INCOME TAX

S.O. 832.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’ New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

### NAME OF THE ORGANISATION

National Institute of Construction Management and Research (NICMAR) Walchand Terraces; Tardeo Road, Mumbai-400034.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions),

Calcutta through the Commissioner of Income-tax (Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1871/F. No. DG/IT(E)|M-110/35(1)(ii)|90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 20 नवम्बर, 1998

आयकर

का.आ. 833 :—सर्वसाधारण को एतद्वारा सचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया जाता है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए, अलग लेखा ग्रहियां रखेगा ;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग की "प्रौद्योगिकी भवन," न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा ; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिस्कर् किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

नेशनल कौंग्रस आफ साइन्स म्यूजियम, सेक्टर-5, ब्लॉक - जी. एन., विधान नगर, कलकत्ता-700091  
यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर

महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में लिए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है ।

[संख्या 1872/एफ. सं. म. ति./आ. क. (छूट)/डब्ल्यू. बी.-35/कल. /35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 20th November, 1998

INCOME TAX

S.O. 833.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

National Council of Science Museums, Sector-V, Block-GN; Bidhan Nagar, Calcutta-700091.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application

for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1872 F. No. DG/IT(E)/WB-35/CAL/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of  
Income-Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 20 नवम्बर, 1998

आयकर

का.आ. 834:— सर्वसाधारण का एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संघर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहिया रखेगा ;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग "प्रौद्योगिक भवन," न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट); (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

संगठन का नाम

श्री ए. एम. एम. मुरुगप्पा चेनीयर रिसर्च सेंटर,  
टी. आई. ए. एम. हास,  
28, राजाजी सलाई, मद्रास-600001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संघर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों

में आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है । उस आवेदन पत्र छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है ।

[संख्या 1873/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/टी. एन.-4/  
कल./35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 20th November, 1998

### INCOME TAX

S.O. 834.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions .

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

### NAME OF THE ORGANISATION

Shri A.M.M. Murugappa Chettiar Research Centre, TIAH House: 28, Rajaji Salai, Madras-600 001.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Note : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent

directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1873 F. No. DG/IT(E)/TN-4/CAL/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 20 नवम्बर, 1998

आयकर

का. आ. 835.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया, दरबारी सेठ ब्लॉक, ह्यूटेड प्लेस, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को

तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पाम भेजना है।

[संख्या : 1874/एफ. स. म. नि./आ. क. (छूट)/एन. डी.-139/35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक, आयकर (छूट)

Calcutta, the 20th November, 1998

(INCOME TAX)

S.O. 835.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Solar Energy Society of India,  
Darbari Seth Block, Habitat Place,  
Lodhi Road,  
New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-99.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1874/F. No. DG/IT(E)/ND-139/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 20 नवम्बर, 1998

आयकर

का. आ. 836.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर निगम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय व्यय हिमाव को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : ऑयल टेक्नोलॉजीस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एच. बी. टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, नवाब गंज, कानपुर—208002।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता का तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उक्त आवेदन पत्र की छः प्रति अनुमोदन की अवधि

बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1875/एफ. स. म. नि./आ. क. (छूट)/  
यू. पी.-28/35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

(Calcutta, the 20th November, 1998)

(INCOME TAX)

S.O. 836.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Oil Technologist Association of India,  
H. B. Technological Institute,  
Nawab Ganj,  
Kanpur-208002

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1875/F. No. DG/IT(E)/UP-28/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 25 नवम्बर, 1998

आयकर

का. आ. 837.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के



खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाव को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : नगरी आई रिसर्च फाउण्डेशन, सी. एच. नगरी म्यूनिसिपल हास्पिटल एलीम ब्रीज, अहमदाबाद—380006।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1876/एफ. सं. म. नि./आ.क. (छूट)/जी.-46/35(1)(ii)/90—91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta the 25th November, 1998

(INCOME TAX)

S.O. 837.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Nagri Eye Research Foundation,  
CH Nagri Municipal Hospital,  
Elisbridge, Ahmedabad-380006.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2000.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1876/F. No. DG/IT(E)/G-46/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 27 नवम्बर, 1998

आयकर

का. आ. 338.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक

व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिस्कर् किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : नगरजून एप्लीकलचरल रिसर्च एण्ड डेवेलपमेंट इंस्टीच्यूट (एन.ए.आर.डी.आई.), 28, पी.एण्ड टी. कलोनी, सिकन्दराबाद-500009।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "सब" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को मुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उम आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पाम भेजना है।

[संख्या : 1877/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)  
कल./35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 27th November, 1998

(INCOME TAX)

S.O. 838.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Nagarjun Agricultural Research and Development Institute (NARDI),  
28, P & T Colony, Secunderabad-500009.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2000.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1877/E. No. DG/IT(E)/CAL/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 4 दिसम्बर, 1998

आयकर

का.आ. 839.-स-वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त

आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) में दी गई रिमर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

आर. एण्ड डी. सेट्र फॉर केले रॉफिंग टाइल्स, ब्रिक्स एण्ड अदर सेरामिक प्रोडक्ट्स, कर्नाटक रिजिनल इंजीनियरिंग कालेज, सुरत काल पी. ओ. श्री निवास नगर-574157, डी. के. डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट, इंडिया।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संघर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूचित दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1878/एफ. सं. म. नि./आ. क. छूट/के. टी.-47/35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 4th December, 1998

#### (INCOME TAX)

S.O. 839.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research

activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

R & D Centre for Clay Roofing Tiles, Bricks and other Ceramic Products, Karnataka Regional Engineering College, Surathkal, P.O. Srinivasnagar-574157, D. K. District, Karnataka State, India.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

#### Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1878/F. No. DG/IT(E)/KT-47/35(1)(ii)/90-91]

MUKESHI KUMAR, Addl. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 4 दिसम्बर, 1998

#### आयकर

का.आ. 840.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संघर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) में दी गई रिमर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

## Notes :

डा. पटानी साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च,  
पी. एस. आर्ट आर. बिल्डिंग, महाकाली रोड, अंधेरी  
(ई), मुम्बई-400093 (इंडिया)।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक  
की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए  
लागू नहीं होगा।

- 2 संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे  
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर  
आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-  
धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आय-  
कर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता  
को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन  
की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र  
की विभागीय प्रस्तुत करना है। इस आवेदन  
पत्र छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के  
लिए जीआर सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनु-  
संधान विभाग के पास भेजना है।

[नं. 1879/एफ. नं. य. नि./आ.क. (छूट)/एम-14/कल  
/35(1)(ii)/90-91]

मुकेश कुमार अवर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 4th December, 1998

## (INCOME TAX)

SO 840.—It is hereby notified for general information  
that the organisation mentioned below has been approved  
by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax  
Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of  
Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category  
"Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of  
accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific  
research activities to the Secretary, Department of  
Scientific and Industrial Research, 'Technology  
Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016  
for every financial year by 31st May of each year ;  
and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-  
tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Sci-  
entific and Industrial Research, and (c) Commis-  
sioner of Income-tax/Director of Income-tax (Ex-  
emptions), having jurisdiction over the organisation,  
by the 31st October each year, a copy of its audited  
Annual Accounts and also a copy of audited Income  
and Expenditure Account in respect of its research  
activities for which exemption was granted under  
sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act,  
1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Dr. Patani Scientific and Industrial Research,  
PSIR Building, Mahakali Road, Andheri (E),  
Mumbai-400093 (India).

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to  
31-3-2000.

1. Condition (i) above will not apply to organisations  
categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and  
well in advance for further extension of the ap-  
proval, to the Director General of Income-tax (Ex-  
emptions), Calcutta through the Commissioner of  
Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions)  
having jurisdiction over the organisation. Six copies  
of the application for extension of approval should  
be sent directly to the Secretary, Department of  
Scientific and Industrial Research.

[No. 1879/F. No. DG/IT(E)/M-14/CAL/35(1)(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax  
(Exemptions)

कलकत्ता, 8 दिसम्बर, 1998

## आयकर

का.आ. 841.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया  
जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम,  
1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के  
लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधि-  
कारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के  
अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा  
बहियां रखेगा,
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का  
एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए  
प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व  
औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन"  
न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा;  
और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित  
वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक  
(छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक  
अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/  
आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार  
में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम,  
1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया  
संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय  
हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

सेंट्र फोर पोलिसी स्टडीज, 27 राजविक्रम स्ट्रीट,  
मैलापुर, मद्रास-600004।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक  
की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए  
लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे  
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर

आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1880/एफ. स. म. नि./ग्रा. क./ (छूट) टी. एन. - 70/कल. 35/(1) (iii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 8th December, 1998

#### (INCOME TAX)

S.O. 841.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan" New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Centre For Policy Studies,  
27, Rajsekharan Street, Mylapore,  
Madras-600004.

This Notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

#### Notes :

- Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1880/F. No. DG/IT(E)/TN-70/CAL/35(1)(iii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax (Exemptions)

787 G1/99—3.

कलकत्ता, 8 दिसम्बर, 1998

#### आयकर

का.आ. 842.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रौद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली -110016 को भेजेगा, और
- यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिस्कर् किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

इंस्टीट्यूट फॉर फ़ाएनेन्शियल मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च,  
30 कोठारी रोड, नूतनगम्हाकम, चेन्नाई-600034।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्तें (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या 1881 /एफ. स. म. नि. ग्रा. क. (छूट)/टी. एन. - 28/कल./35(1) (iii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 8th December, 1998

## (INCOME TAX)

S.O. 842.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Institute for Financial Management and Research,  
30, Kothari Road,  
Nungambakkam, Chennai-600034.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

## Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Development of Scientific and Industrial Research.

[No. 1881/F. No. DG/IT(E)/TN-28/CAL/35(1)(iii)/90-91]  
MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax  
(Exemptions)

कलकत्ता, 8 दिसम्बर, 1998

## आयकर

का.प्र. 843.—सर्वसाधारण को एसद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए

प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब का भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : स्पास्टीकस सोसाइटी ऑफ कर्नाटक 31, 5वां फ्लोर, प्रोफ 5 वां मैन इन्द्रानगर, 1 ला स्टेज बैंगलोर-560038.

बहु अधिसूचना दिनांक 1-4-1998 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है। उक्त आवेदन पत्र छः प्रति अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1882/एफ.सं. म.नि./अ.क. (छूट) के. टी. 52/  
35/(1)(iii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 8th December, 1998

## (INCOME TAX)

S.O. 843.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Spastics Society of Karnataka,  
31, 5th Cross, Off 5th Main Indiranagar, 1st Stage,  
Bangalore-560038.

This Notification is effective for the period from 1-4-1998 to 31-3-2001.

## Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions). Calcula through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1882/F. No. DG/IT(E)/KT-52/35(1)(iii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax (Exemptions)

कलकत्ता, 8 दिसम्बर, 1998

आयकर

का.आ. 844.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन", न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिमर्स

किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम: सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, राजकोट-360005.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधे सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1883/एफ. सं. म. नि. /आ. क. (छूट)जी -38/कल. 35(1)(iii)/90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 8th December, 1998

## INCOME TAX

S.O. 844.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Saurashtra University, University Road, Rajkot-360005.

This Notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-1999.

## Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The Organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income Tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1883 F. No. DG/IT(E)/G-38/CAL 35(1)(iii) 90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 8 दिसम्बर, 1998

## आयकर

का.आ. 845.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 की भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1963 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : इंदिरा गांधी नेशनल सेन्टर फॉर दी आर्ट्स जनपथ, नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पण : 1. उपर्युक्त शर्त (i) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि ये अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महा-

निदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग, को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र की छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1884 एफ.सं.म. नि.आ.क. (छूट) एन.डी. 22/कल. 35(1) (iii) 90-91]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 8th December, 1998

## INCOME TAX

S.O. 845.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’ New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year : and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions) (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Indira Gandhi National Centre for the Arts Janpath, New Delhi-110001.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2000.

## Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income Tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1884 F. No. DG/IT(E)/ND-22/CAL 35(1)(iii) 90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax (Exemptions)



कलकत्ता, 22 दिसम्बर, 1998

## आयकर

का.आ. 346.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-वहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रोद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।
- (iv) यदि (i) या (ii) या (iii) निर्धारित प्राधिकारी अर्थात् आयकर महानिदेशक (छूट) के समक्ष पेश नहीं होता है तो जारी अनुसंधान क्रियाकलाप के बारे में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा।

संगठन का नाम : श्री औरोविंदो आश्रम ट्रस्ट, पी.ओ. श्री और-विंदो आश्रम, पण्डिचेरी-6005002.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2001 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पण : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगी।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छ : प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास

भेजना है और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव के पास जमा करने की तिथि की सूचना निर्धारित प्राधिकारी अर्थात् आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता, को देगा।

[संख्या 1885/एफ. सं. म.नि./आ.क. (छूट) पांड़ी-3/कल/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 22nd December, 1999

## INCOME TAX

S.O. 846.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of the scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income-Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-Tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income-Tax Act, 1961.
- (iv) If either (i) or (ii) or (iii) are not filed before the Prescribed Authority i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions), adverse conclusion may be drawn as to the genuineness of Research Activities carried on.

Name of the Organisation :

Shri Aurobindo Ashram Trust,  
P.O. Shri Aurobindo Ashram,  
Pondicherry-6005002.

This Notification is effective for the period from 1-4-98 to 31-3-2001.

Notes :

- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the same application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and the date of submission to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research shall be communicated to the Prescribed Authority i.e. Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta.

[No. 1885/F. No. DG|IT(E)|Pond-3|Cal.|35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income Tax (Exemptions)

कलकत्ता, 22 दिसम्बर, 1998

आयकर

का. आ. 847.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संघ” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, “प्रीक्षोगिक भवन” न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा, और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई

रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाव को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

टी रिसर्च एसोशिएशन, 113, पार्क स्ट्रीट,  
(9 वां फ्लोर), कलकत्ता—700016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-98 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है। उस आवेदन पत्र छः प्रतियां अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए सीधा सचिव वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के पास भेजना है।

[संख्या : 1886/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)/डब्ल्यू.  
बी—17/कल./35 (1) (ii)/90-91]

मुकुश कुमार, अपर निदेशक आयकर (छूट)

Calcutta, the 22nd December, 1999

## INCOME TAX

S.O. 847.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Association” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1886/F.No. DG/IT(E)/W.B.-17/Cal.35(1)  
(ii)/90-91]

MUKESH KUMAR, Addl. Director of Income-tax  
(Exemptions)

(iii) It shall submit to the (a) Director General of Income-Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-Tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1999

का. आ. 848.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संस्था/संघ और नीचे दिए गए उसके कार्यक्रम का अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 गणख के प्रयोजनार्थ आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6ककग के अंतर्गत प्राधिकारी होने के कारण भविष्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है।

संस्था/संघ का नाम

मैसर्स बनराय

बिजयनगर, पुणे—400001

कार्यक्रम

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

Name of the Organisation :

Tea Research Association,

113, Park Street, (9th Floor).

Calcutta-700016.

This Notification is effective for the period from 1-4-1998 to 31-3-2000.

Notes :

(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent

2. विहित अधिकारी द्वारा (i) धारा 35 गणख की उपधारा (2) के अंतर्गत संस्था/संघ को और (ii) धारा 35 गणख की उपधारा (i) के अंतर्गत कार्यक्रमों को दिए गए दोषों अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक 1-4-98 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए वैध हैं ;

(i) मैसर्स बनराय, बिजय नगर, पुणे उपर्युक्त अपनी संरक्षण गतिविधियों के लिए प्राप्त दानों का अलग से खाता रखेगा।

(ii) मैसर्स बनराय, बिजय नगर वित्त वर्ष 1998-99 के लिए अपने संरक्षणों के कार्यक्रमों पर किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट हर हफ्ता में विहित अधिकारी को 31-3-1999 तक प्रस्तुत कर देगा।

(iii) यह सोसाइटी विहित प्राधिकारी को कुल आय और देयताओं को दर्शाने हुए वर्ष 1998-99

के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 31-3-99 तक प्रस्तुत कर देगी तथा इन सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि संबंधित आयकर आयुक्त को भेजी जाए।

(iv) मैसर्स वनराय शीघ्र ही हमें 1998-99 की लेखा परीक्षित लेखा रिपोर्ट के साथ-साथ प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

[अधिसूचना सं. 10828/फा. सं. 203/21/97-आयकर नि.—II]

मालती आर. श्रीधरन, अव. सचिव

### CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 15th March, 1999

S.O. 848.—It is notified for general information that the Institution/Association mentioned below and its programme given hereunder have been approved by the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, being the prescribed authority under rule 6AAC of the Income Tax Rules, 1962, for the purposes of Section 35CCB of the Income Tax Act, 1961.

Name of the Institution/Association :

M/s. Vanarai

Vijayanagar, Pune-400001,

Programme :

Conservation of natural resources.

2. Both the approvals accorded by the Prescribed Authority namely (i) to the Institution/Association under sub-section (2) of Section 35CCB and (ii) to the programmes under sub-section (i) of Section 35CCB are valid for the period from 1-4-98 to 31-3-99 with the following conditions :

(i) M/s. Vanarai, Vijayanagar, Pune, shall maintain a separate account of the donations received by it for its conservation activities mentioned above.

(ii) M/s. Vanarai, Vijayanagar, shall furnish progress report of work done on their

conservation programmes to the prescribed authority for the financial year 1998-99 by 31-3-1999 positively.

(iii) The Society shall submit to the prescribed authority by the 31-3-99 annual audited accounts report for the year 1998-99 showing total income and liabilities and a copy of each of these documents be sent to the concerned Commissioner of Income Tax.

(iv) M/s. Vanarai must also submit to us the progress report as well as audited accounts report for the period 1998-99 at the earliest.

[Notification No. 10828/F.No. 203/21/97-ITA.II]

MALATHI R. SRIDHARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1999

का.आ. 849.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा पैरा (3) में नीचे उल्लिखित उद्यम की आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2 (ख) के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23छ) के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1998-99, 1999-2000, और 2000-2001 के लिए अनुमोदित किया गया है :—

2. उक्त अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया है कि :

(i) उद्यम आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ख के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23छ) के उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा ;

(ii) केन्द्र सरकार इस अनुमोदन को वापस ले लेगी यदि उद्यम :—

(क) मूलभूत सुविधा को जारी रखना बंद कर देता है, अथवा

(ख) खाता-बहियों को रखने में और आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ख के

उपनियम (7) द्वारा यथापेक्षित किसी लेखा-कार द्वारा ऐसी बहियों की लेखा-परीक्षा कराने में असफल होता है ; अथवा

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2E के उपनियम (7) द्वारा यथापेक्षित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है ।

3. अनुमोदन प्राप्त उद्यम का नाम निम्नानुसार है :—

कोरवा (पूर्व) जिला- बिलासपुर मध्य प्रदेश स्थित अपने 2 × 235 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना के संबंध में मैसर्स देवू पावर इंडिया लि. नई दिल्ली ।

[अधिसूचना सं. 10826/फा. सं. 205/41/98-आ. क. नि. II]

मालथी आर. श्रीधरन, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March 1999

S. O. 849.—It is notified for general information that enterprise, listed at para (3) below has been approved by the Central Government for the purpose of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962, for the assessment years 1998-99, 1999-2000 and 2000-2001.

2. The approval is subject to the condition that —

(i) the enterprise will conform to and comply with the provisions of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;

(ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise :—

(a) ceases to carry on infrastructure facility; or

(b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or

(c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The enterprise approved is—

M/s. Daewoo Power Ltd., New Delhi in respect of their 2 × 235 MW Thermal Power Project at Korba (East) District, Bilaspur, Madhya Pradesh.

[Notification No. 10826/F.No. 205/41/98/ITA-II]

MALATHI R. SRIDHARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1999

का.आ. 850.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा पैरा (3) में नीचे उल्लिखित उद्यम को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2(ड) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23G) के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए अनुमोदित किया गया है

2. उक्त अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया है कि

(i) उद्यम आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2इ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23छ) के उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा ;

(ii) केन्द्र सरकार इस अनुमोदन को वापस ले लेगी यदि उद्यम :—

(क) मूलभूत सुविधा को जारी रखना बंद कर देना है, अथवा

(ख) खाता बहियों को रखने और आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2इ के उपनियम (7) द्वारा यथापेक्षित किती लेखाकार द्वारा ऐसी बहियों की लेखा परीक्षा कराने में असफल हो जाता है ; अथवा

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2इ के उपनियम (7) द्वारा यथापेक्षित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है ।

3. अनुमोदन प्राप्त उद्यम का नाम निम्नानुसार है—  
अपर कृष्ण सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए मैसर्स कृष्ण भाग्य जल निगम लि., पी. डब्ल्यू. डी. आफिस एनेक्सचर, तीसरी मंजिल, के. आर. सर्कल बंगलूर-560001 ।

[प्रधिसूचना सं. 10827/फा. सं. 205/67/98-आ.क. नि. - II]

मालथी आर. श्रीधरन, अवसर सचिव

New Delhi, the 15th March, 1999

S.O. 850.—It is notified for general information that enterprise, listed at para (3) below has been approved by the Central Government for the

purpose of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962 for the assessment years 1998-1999, 1999-2000 and 2000-2001.

2. The approval is subject to the condition that —

(i) the enterprise will conform to and comply with the provisions of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961 read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;

(ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise :—

(a) ceases to carry on infrastructure facility; or

(b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-Rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or

(c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The enterprise approved is—

Upper Krishna Project of M/s. Krishna Bhagya Jala Nigam Ltd., PWD Offices Annexure, 3rd Floor, K. R. Circle, Bangalore-560001. for executing Upper Krishna Irrigation Project.

[Notification No. 10827/F. No. 205/67/98/ITA-II]

MALATHI R. SRIDHARAN, Under Secy.

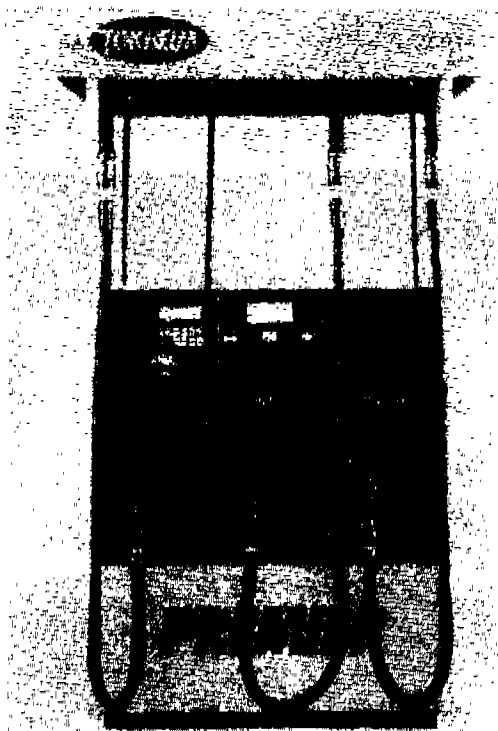
## खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

## ( उपभोक्ता मामले विभाग )

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999

का.आ. 851.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल ( नीचे दी गई आकृति देखें ) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा:

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंकक प्रदर्श सहित डिस्पेंसिंग पंप "प्रीमियर सर्विसेज" (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स टोकेहिम कारपोरेशन, फोर्ट लायने, इंडियना द्वारा किया गया है और भारत में विक्रय मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड, मुम्बई द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/13/98/100 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



यह माडल अंकक प्रदर्श सहित डिस्पेंसिंग पंप का है।

उपकरण का नाम	:	ईंधन डिस्पेंसर
व्यापार का नाम	:	प्रीमियर सर्विसेज
प्रदर्श	:	द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्श
पूर्व निर्धारित युक्ति	:	धनराशि और मात्रा के लिए

[फा.सं. डब्ल्यू. एम. 21(54)/98]

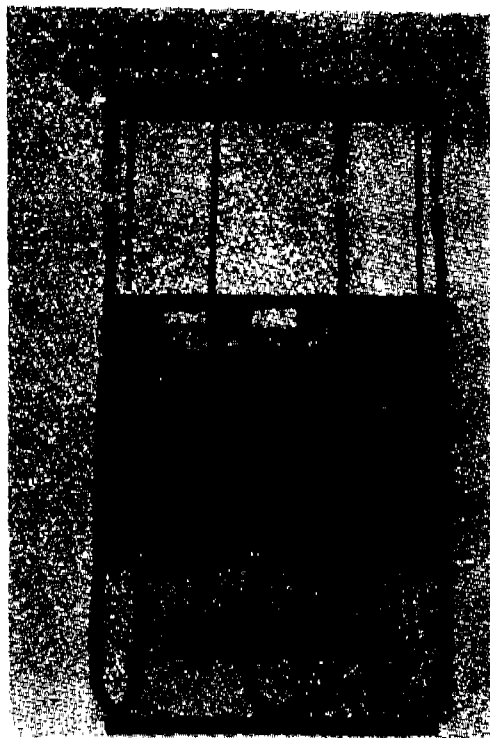
पी.ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

**MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS****(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 11th March, 1999

**S.O. 851.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report ( see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of 'Dispensing pump' with digital display of "Premier Services" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s. Tokheim Corporation, Fort Wayne, Indiana and sold in India by M/s. Larsen & Toubro Limited, Mumbai, and which assigned the approval mark IND/13/98/100;



The said Model is a dispensing pump with digital display.

Name of the instrument	:	Fuel Dispenser
Trade Name	:	Premier Services
Display	:	Liquid Crystal Display
Preset device	:	For Money and Volume

[F. No. WM 21 (54)/98]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology



नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999

क्रा.आ. 852.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "एच 311 ए/एल 111 ए" वाली शृंखला की स्वतः सूचक अस्वचालित, वैश्व मापमान तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "एवरी" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मै. एवरी इंडिया लिमिटेड, प्लॉट सं. 50-54, सेक्टर 25, बल्लभगढ़-121004 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन पत्र आई.एन.डी. 09/98/131 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 30 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही समकोणिक है जिसकी भुजाएं 350 × 350 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसकी अधिकतम क्षमता 20 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक होगी जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 (एन ≤ 10,000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1, 2, 5 शृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(104)/97]

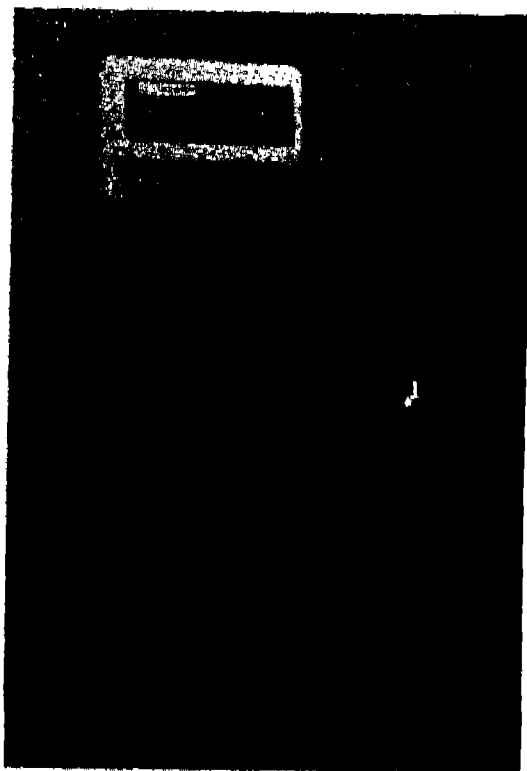
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 11th March, 1999

**S.O. 852.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, bench scale weighing machine of type "H311A/L 111A" series and with brand name "AVERY" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s Avery India Limited, Plot No. 50-54, Sector 25, Ballabgarh-121004 and which is assigned the approval mark [ND/09/98/13];

The said model is a medium accuracy (accuracy class II) bench scale machine with a maximum capacity of 30kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 350 × 350 millimetre. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply;



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section, 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' of 1, 2, 5, series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principal, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (104)/97]

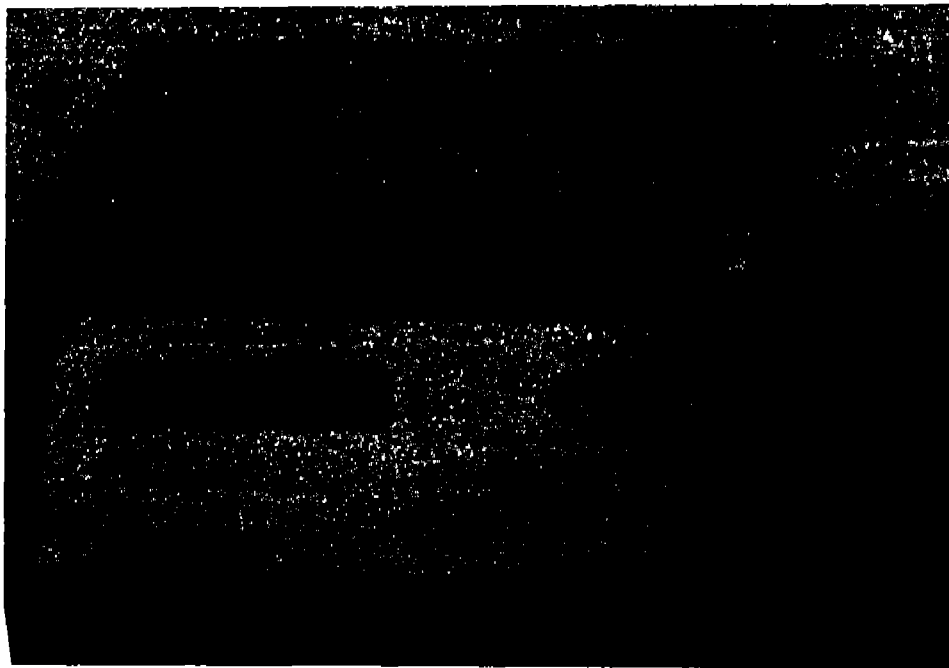
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

का.आ. 853. — केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “एस आई टी” श्रृंखला की, म्यतःसूचक, अस्थायित्वित मेजतल तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का, नाम “स्यासकान” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स म्यासकान इन्स्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. 66, इलेक्ट्रानिक सिटी होसर रोड, बंगलौर-561229 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/129 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का मेजतल मशीन है, जिसकी अधिकतम क्षमता 20 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। स्थापन मापमान अन्तराल (ई) 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 250 × 300 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके स्थापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10000 (एन ≤ 1,0000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका “ई” मान 1,2,5, श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(15)/98]

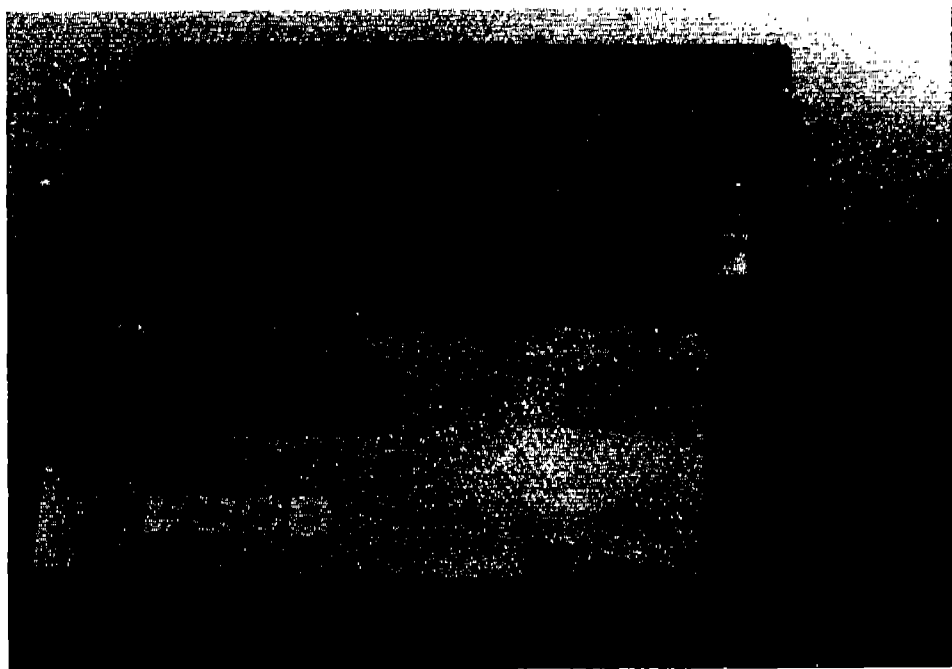
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 853.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, table top weighing machine of type "SIT" series and with brand name "SYSCON" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s. Syscon Instruments Private Limited, Plot No. 66, Electronic City, Hosur Road, Bangalore-561229, and which is assigned the approval mark IND/09/98/129;

The said model is a medium accuracy ( accuracy class III) table top machine with a maximum capacity of 20kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 250 × 300 millimetre. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value of 1, 2, 5 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (15)/98]

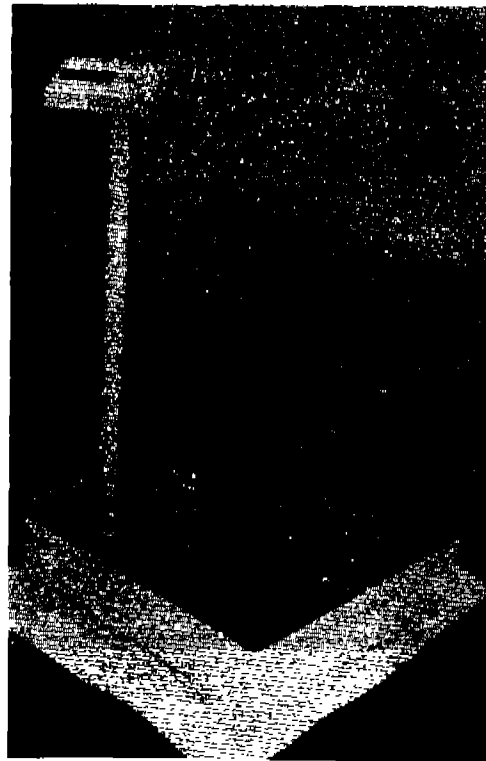
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 854.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "एस आई पी" वाली श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वच्छालित प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "स्यासकान" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स स्यासकान इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. 66, इलेक्ट्रानिक सिटी होसर रोड, बंगलौर-561229 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/130 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का प्लेटफार्म मशीन है, जिसकी अधिकतम क्षमता 100 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 20 ग्रा. है। इसमें एक आद्येतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आद्येतुलन प्रभाव है। भारग्राही वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 400 × 400 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10000 (एन ≤ 1,0000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1,2,5, श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(15)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 854.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions .

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, platform weighing machine of type "SIP" series and with brand name "SYSCON" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s. Syscon Instruments Private Limited, Plot No. 66, Electronic City, Hosur Road, Bangalore-561229, and which is assigned the approval mark IND/09/98/130;

The said model is a medium accuracy ( accuracy class III) platform machine with a maximum capacity of 100kg and minimum capacity of 400g. The verification scale interval (e) is 20 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular cross section of sides 400 × 400 millimeter. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value of 1, 2, 5 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (15)/98]

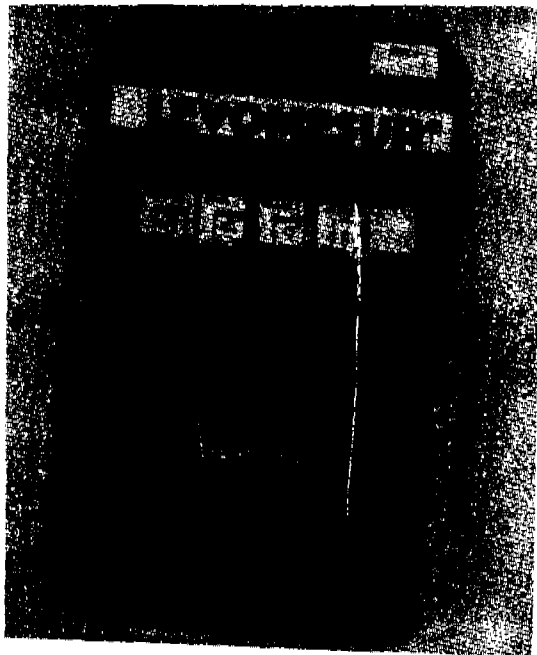
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 855.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्टील टेग तल के माडल जिसके ब्रांड का, नाम "सेनोमेजर-एल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स प्रीमैक्स मैसर्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 787 लुधियाना -141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/153 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल यथार्थता वर्ग II स्टील टेग तल का है, जिसकी लम्बाई 5 मीटर और अंशकान प्रत्येक मिलीमीटर पर है।



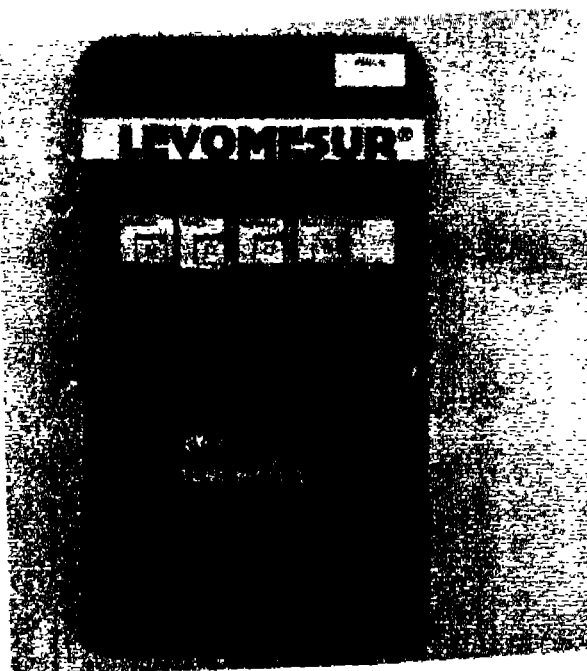
[ फा. सं. डब्ल्यू एम-21(53)/97 ]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 855.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model Steel tape Rule of "Levomsur-LM" series (hereinafter referred to as the model) of accuracy class II manufactured by M/s. Freemans Measures Limited, Post Box No. 787, Ludhiana-141 003 and which is assigned the approval mark IND/09/98/153:



The model is a Steel tape Rule of accuracy class II with length of 5 metre and graduated at every millimetre.

[F. No. WM 21(53)/97]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

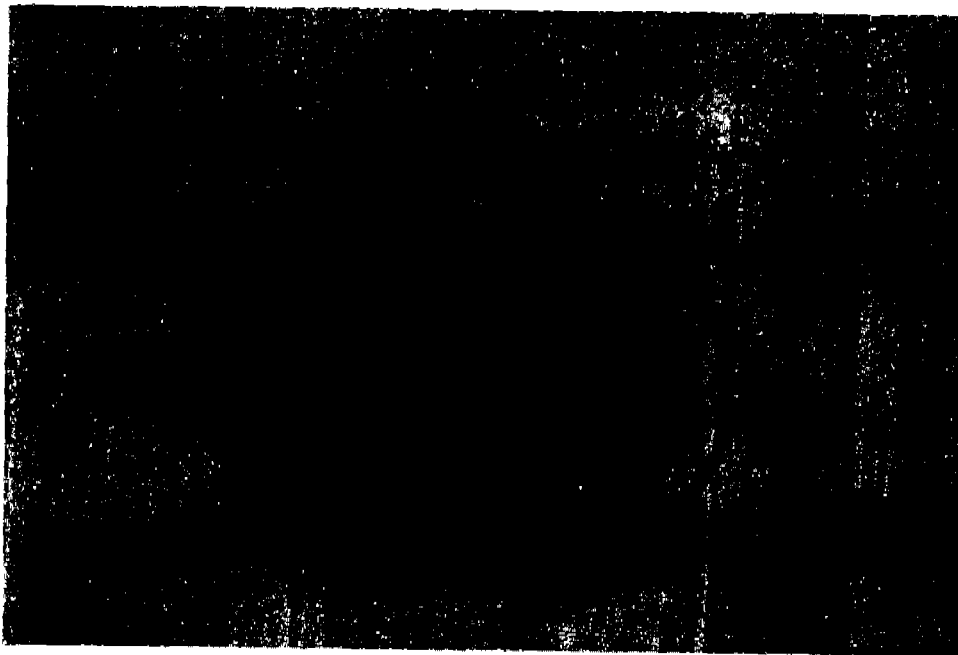


नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 856.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग III यथार्थता वाली फाइबर, कांच फीता मापक के माडल का प्लाटिका-696 श्रृंखला का है जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है और जिसका विनिर्माण मैसर्स फ्रीमैन्स मेजरा लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 787 लुधियाना-141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन विह्न आई एन डी/09/98/152 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल फाइबर कांच फीता मापन यथार्थता वर्ग III का है, जिसकी अधिकतम क्षमता 5 मीटर है और प्रत्येक सेंटीमीटर पर आंशकित है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, प्लास्टिका श्रृंखला के समान यथार्थता वर्ग के फीता माप आते हैं और जिनकी लम्बाई 40 मीटर तक हो, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(53)/97]

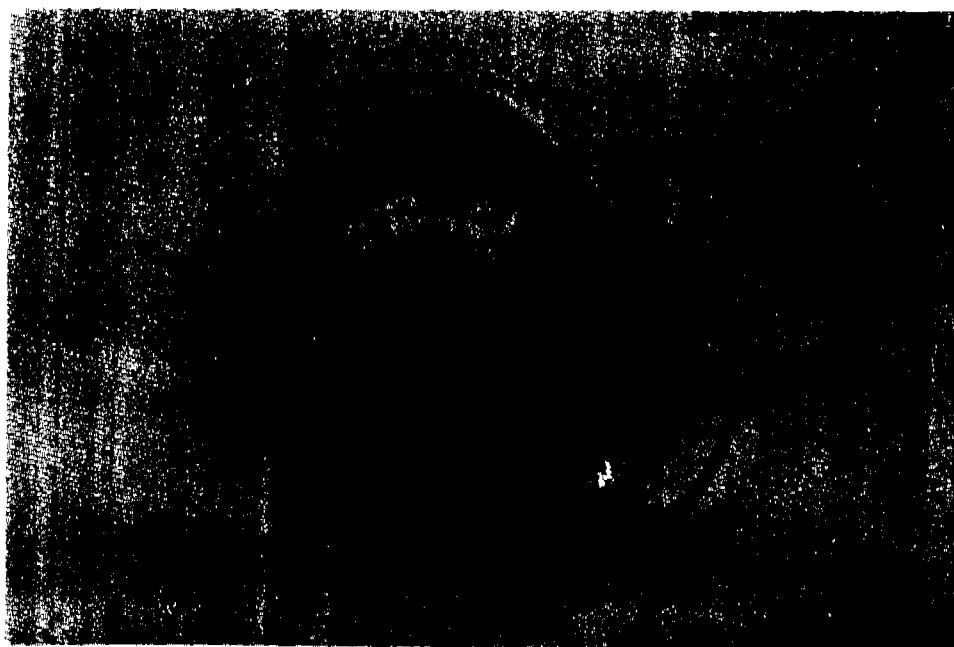
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 856.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model Fiberglass tapes of "Plastica-696" series (hereinafter referred to as the model) of accuracy class III manufactured by M/s. Freemans Measures Limited, Post Box No. 787, Ludhiana-141 003 and which is assigned the approval mark IND/09/98/152.

The model is a Fiberglass measuring tape of accuracy class III with length of 5 metre and graduated at every centimeter.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover tape measures of "Plastica" series and of length upto 50 metre, belonging to same accuracy class manufactured by the same manufacturer in with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (53)/97]

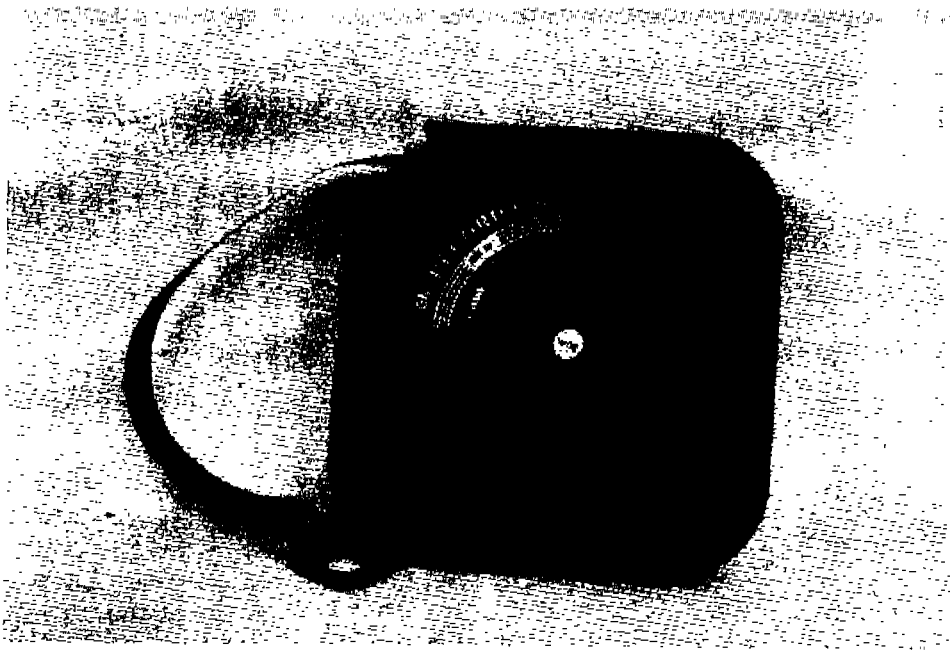
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 857.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग III यथार्थता वाली धातु तार का फीता के माडल का "रिकार्ड-676" श्रृंखला का है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स फ्रीमेंन्स मेजर्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 787 लुधियाना -141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/98/151 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल धातु तार का फीता यथार्थता III का है, जिसकी लम्बाई 10 मीटर और प्रत्येक सेंटीमीटर पर अंशांकित है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत "रिकार्ड आर सी" श्रृंखला के समान यथार्थता वर्ग के फीता माप आते हैं और जिनकी लम्बाई 50 मीटर तक हो, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[ फा. सं. डब्ल्यू एम-21(53)/97 ]

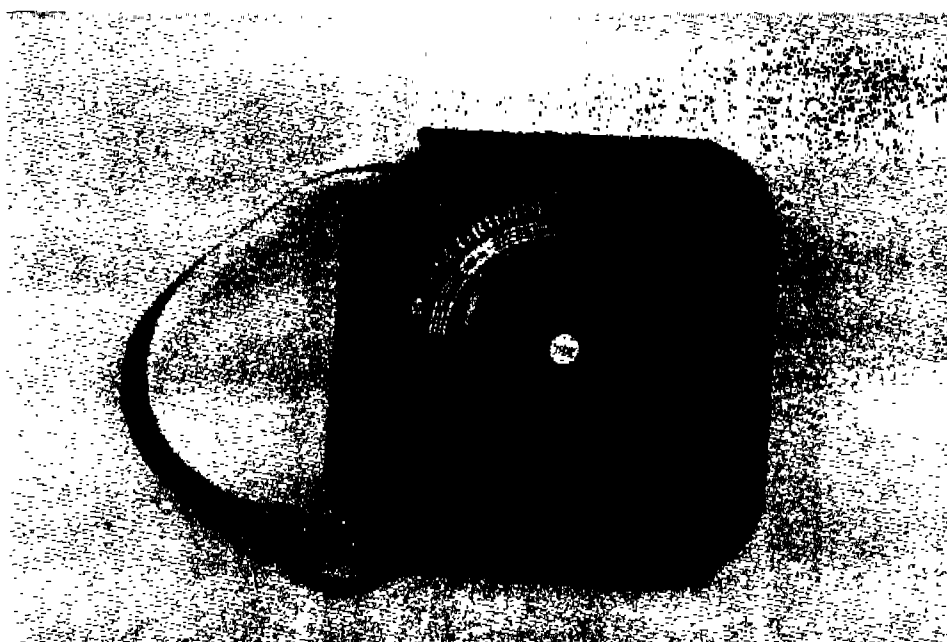
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 857.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Metal wire tapes of "Record -676" series (hereinafter referred to as the model) of accuracy class III manufactured by M/s. Freemans Measures Limited, Post Box No. 787, Ludhiana-141 003 and which is assigned the approval mark JND/09/98/151.

The model is a Metal wire tape of accuracy class III with length of 10 metre and graduated at every centimetre.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover tape measures of "Record RC" series and of length upto 50 metre, belonging to same accuracy class manufactured by the same manufacturer with the same design and materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (53)/97]

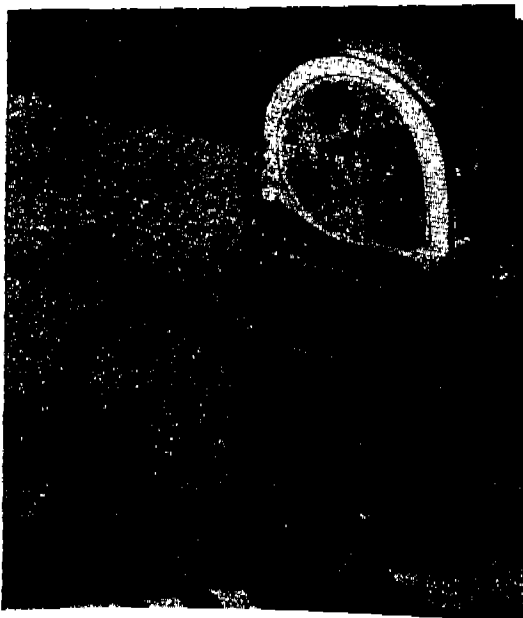
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 858.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) याट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II यथार्थता वाली स्टील फीता माप के माडल का "जम्बो जे एम ई-89" श्रृंखला का है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स फ्रीमैन्स मेजर्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 787 लुधियाना -141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/150 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल स्टील फीता माप (यथार्थता वर्ग II) का तोलन उपकरण है, जिसकी लम्बाई 2 मीटर है और प्रत्येक मिलीमीटर पर अंशांकित है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, "टाप लोक-टी एल" और "फलेक्सी में जर एफ-एम" श्रृंखला के समान यथार्थता वर्ग के फीता माप आते हैं और जिनकी लम्बाई 8 मीटर तक हो, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(53)/97]

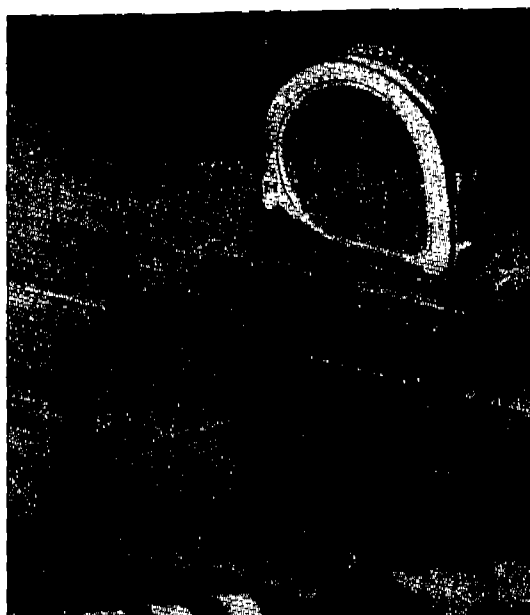
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 858.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Steel Measuring tapes of "Jambo JME-89" series (hereinafter referred to as the model) of accuracy class II manufactured by M/s. Freemans Measures Limited, Post Box No. 787, Ludhiana-141 003 and which is assigned the approval mark IND/09/98/150.

The model is a Steel measuring tape of accuracy class II with length of 2 metre and graduated at every millimetre.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover tape measures of "Toplok-TL and Fleximeasure-FM" series, belonging to same accuracy class and with length upto 8 metre, manufactured by the same manufacturer with the same design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (53)/97]

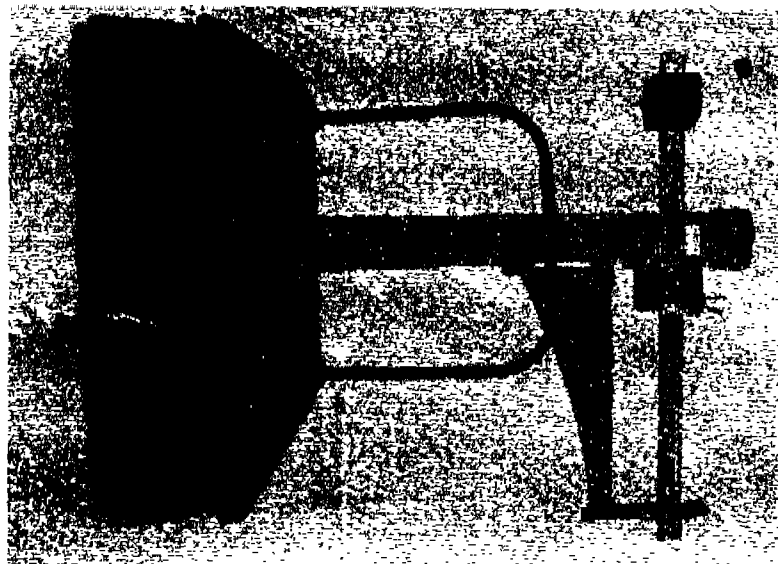
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**क्रा. आ. 859.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते वर्ग III यथार्थता (मध्यम यथार्थता) वाली “डब्ल्यू एम-पी एस” वाली श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अम्वधालित, यांत्रिक स्टील यार्ड प्रकार की प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम “वी टेक्स” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स वी टेक इंडिया लिमिटेड, एल-3-176/35/22/26, भाग्यलक्ष्मी नगर, कारागुडा, हैदराबाद-500080 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन टी/09/98/144 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल (आकृति देखें) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 300 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 2 किलोग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 100 ग्राम है। भारग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 635×560 मिलीमीटर हैं।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10000 (एन ≤ 1,0000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका “ई” मान 1, 2, 5, श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(62)/96]

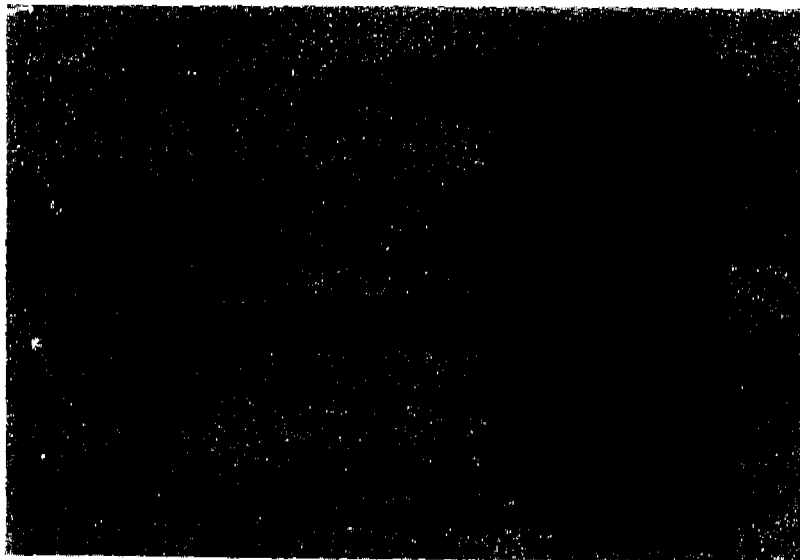
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S. O. 859.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, mechanical Steel yard type platform weighing machine of type "WM-PS" series of class III accuracy (Medium accuracy) and with brand name "WEITEX" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s. Weitex India Limited, 1-3-176/35/22/26 Bhagyalaxminagar, Karadiguda, Hyderabad-500080, and which is assigned the approval mark IND/09/98/144.

The model (see the figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 300 kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. The load receptor is of rectangular section of side 635×560 millimeter.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value to 1, 2, 5 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (62)/96]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

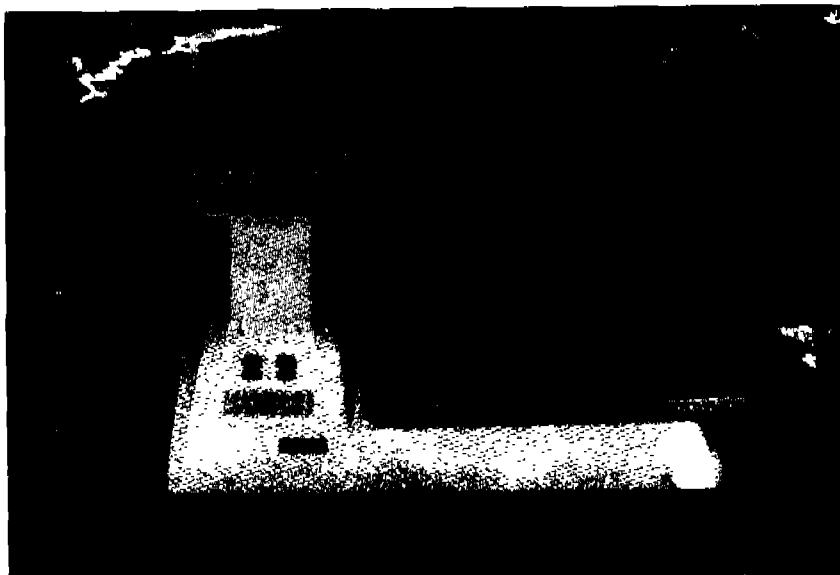


नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

का. आ. 860.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग III यथार्थता (मध्यम यथार्थता) वाली "एस-एल-96-सी एस" वाली श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वचालित, इलेक्ट्रॉनिक बेंच प्रकार की तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "बी टेक" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मेसर्स बी टेक इंडिया लिमिटेड, एल-3-176/35/22/26, भाग्यलक्ष्मी नगर, कारागुडा, हैदराबाद-500080 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/143 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल (आकृति देखें) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 2 ग्राम है। भारग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 280×300 मिलीमी. पर हैं।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला का ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10000 (एन ≤ 1,0000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1, 2, 5, श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(62)/96]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S. O. 860.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic bench type weighing machine of type "SL-96-CS" series of class III accuracy (Medium accuracy) and with brand name "WEITEX" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s. Weitex India Limited, 1-3-176/35/22/26 Bhagyalaxminagar, Karadiguda, Hyderabad-500080, and which is assigned the approval mark IND/09/98/143.

The model (see the figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 10 kg. and minimum capacity of 40g. The verification scale interval (e) is 2g. The load receptor is of rectangular section of side 280×300 millimeter.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value to 1, 2, 5 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (62)/96]

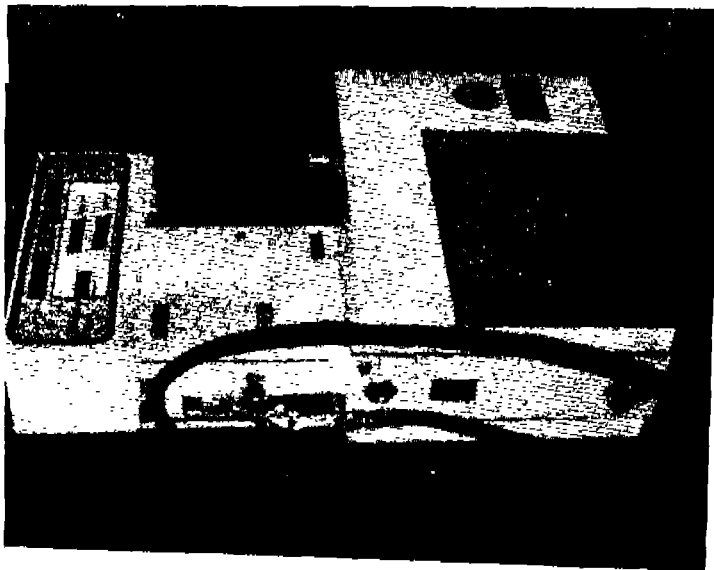
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 861.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और वाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथावत् बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहु उत्पाद डिस्पेंसिंग पंप के माडल का, जिसके ट्रेड का नाम "एडवांटेज" है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स गिलवाक्रो इनकापॉरेटेड, 7300 वेस्ट फ्रेंडली एवेन्यू ग्रींसबरो, एन सी 27420-2087 यू एस ए और भारत में मैसर्स एवरी इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नं. 50-59, सेक्टर 25, बल्लभगढ़-121004 हरियाणा द्वारा विक्रीत किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह नं. आई एल डी-13/98/9 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल बहु उत्पाद पंप और आद्र हौज प्रणाली के डिजिटल प्रदर्श सहित डिस्पेंसर जो कि द्रवित ईंधन उदाहरण डीजल, सीसारहित पेट्रोल, डीजल और डिस्पेंसिंग के लिए है। जिसमें चार पिस्टन धनात्मक विस्थापन प्रकार की मापन प्रणाली है। इसमें मात्रा, संदेय रकम और इकाई मूल्य आदि के प्रदर्श की व्यवस्था है। उपकरण 220/230/240 वोल्ट और 50 हर्टज व आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है। अधिकतम प्रवाह दर 40 लीटर प्रति मिनट प्रति होज है। मापमान अन्तराल 10 मिलीलीटर है।



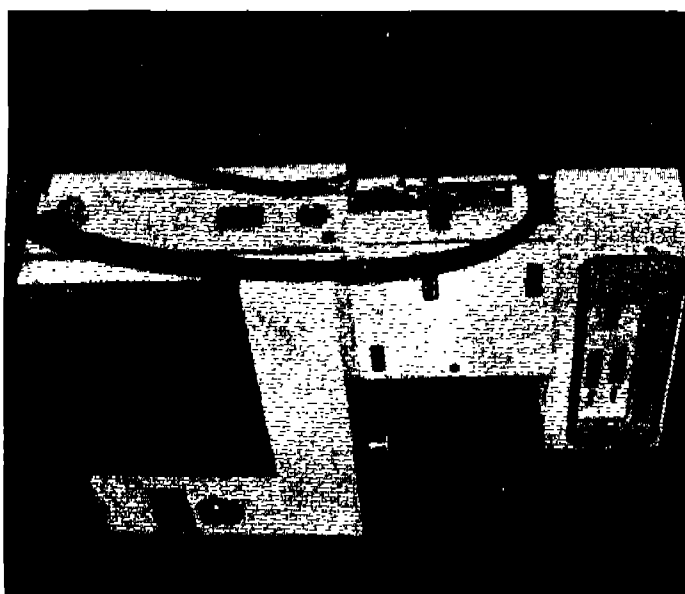
[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(63)/97]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 861.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Multi product Dispensing Pump with Trade "Advantage" manufactured by M/s. Gilbarco, Incorporated 7300 West Friendly Avenue Greensboro, NC 27420-2087 USA, and sold in India by M/s. Avery India Limited, Plot Nos. 50-59 Sector 25, Ballabgarh-121004 (Haryana) and which is assigned the approval mark IND/13/98/9 .



The said model of Multi product pumps and dispensers with digital indication are of 'Wet hose' system for dispensing liquid fuel like Diesel, unleaded petrol, diesel etc. The measuring system is four piston positive displacement type. The display is of Liquid Crystal Diode type. It has provision for display of 'Quantity', 'amount to pay' and 'unit price' etc., The instrument operates on 220/230/240 Volt, 50 Hertz alternate current power supply, maximum flow rate is 40 litre per minute per hose. The scale interval is of 10 millimetre.

[F. No. WM 21 (63)/97]

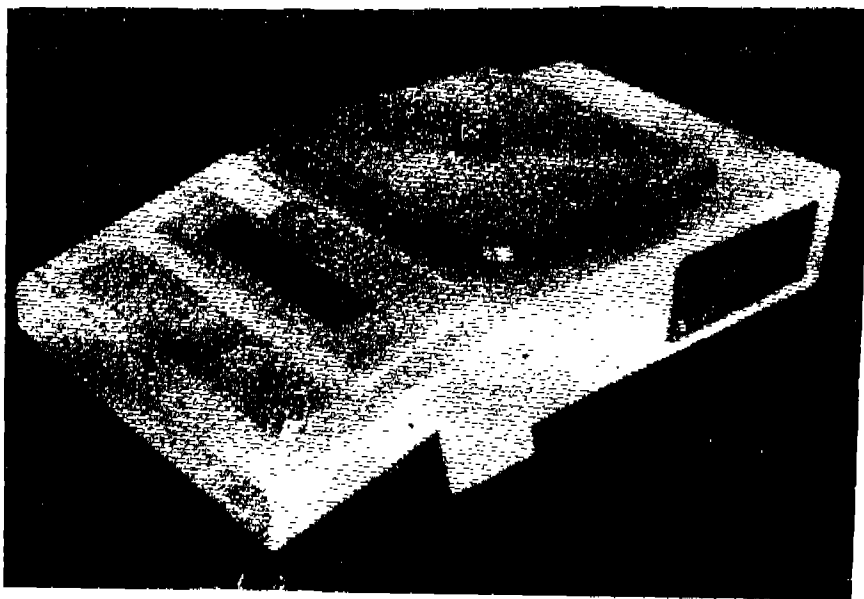
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 862.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और वाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग I यथार्थता (विशेष यथार्थता) वाली "डी सी-170" श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वचालित, इलेक्ट्रॉनिक मेजतल तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "ईसी-डीगी" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स ई सी टेरोका प्राइवेट लिमिटेड, 27, 9वीं क्रॉस, विलसन गार्डन, बंगलौर-224165 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/97/99 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल विशेष यथार्थता (यथार्थता वर्ग I) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 2 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 1 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 10 मिलिग्राम है। इसमें एक आद्येयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यलकलनात्मक धारित आद्येयतुलन प्रभाव है। भारग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 152×165 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला अधिकतम क्षमता 200 ग्राम/1 मिलीग्राम का ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(70)/95]

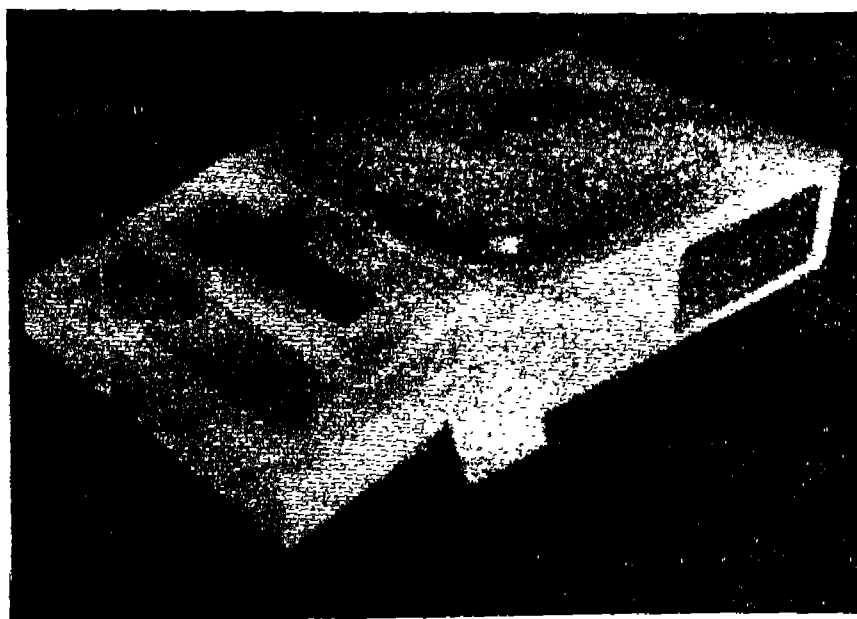
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 862.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic table top weighing machine of type "DC-170" series of class I accuracy (special accuracy) and with brand name, "ESSAE-DIGI" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Essae Teraoka Private Limited, 27, 9th Cross, Wilson Garden, Bangalore-224165, and which is assigned the approval mark IND/09/97/99.

The said Model is a special accuracy (accuracy class I) weighing instrument with a maximum capacity of 2kg and minimum capacity of 1g. The verification scale interval (e) is 10mg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 152×165 millimetre. The liquid crystal display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 200g/1mg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (70)/95]

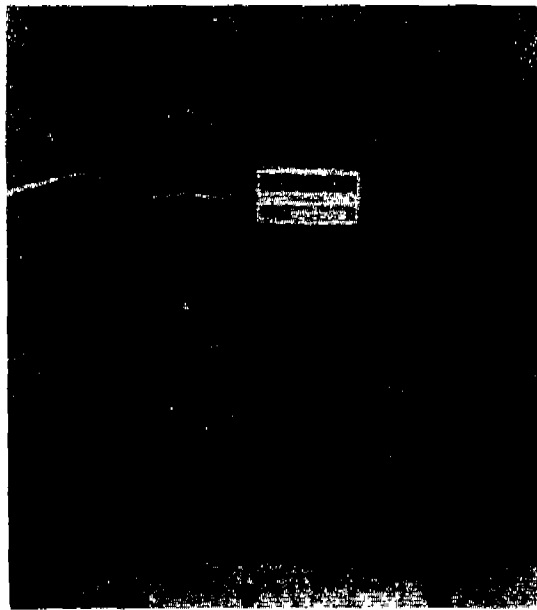
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 863.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए III यथार्थता (मध्यम यथार्थता) वाली "ई डब्ल्यू बी श्रृंखला" की, स्वतःसूचक, अस्वच्छालित, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म तोलन और बोराबस्त मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड नाम "एरको" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मै. एटको इंडस्ट्रीज लि., 6ए, लालबानी इंडस्ट्रियल स्टेड्स, 14, जी.टी. अम्बेडकर रोड, बडाला, मुम्बई-400031 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी. 09/98/40 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 60 टन है और न्यूनतम क्षमता 200 किलोग्राम है। स्थापन मापमान अन्तराल (ई) 10 किलोग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्त है जिसका शत प्रतिशत व्यलकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही वर्गाकार है जिसकी भुजाएं 16×3 मीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी मिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके स्थापन मापमान का अन्तराल (एल) की अधिकतम संख्या 10000 (एल ≤ 10000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1,2,5 श्रृंखला का है। माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एस-21(85)/95]

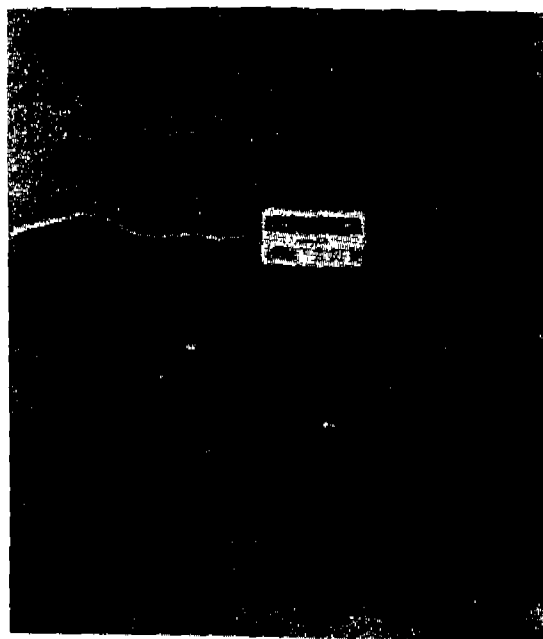
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 863.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic platform weighing machine of type "EWB" series of class III accuracy (medium accuracy) and with brand name, "ATCO" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. ATCO Industries Ltd., 6A Lalwani Industrial States 14, G.D. Ambedkar Road, Wadala Mumbai-400031, and which is assigned the approval mark IND/09/98/40.

The said model is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 60 tonne and minimum capacity of 200 kg. The verification scale interval (e) is 10kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of square section of side 16×3 metre. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification Scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value of 1,2,5 series, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (85)/95]

P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

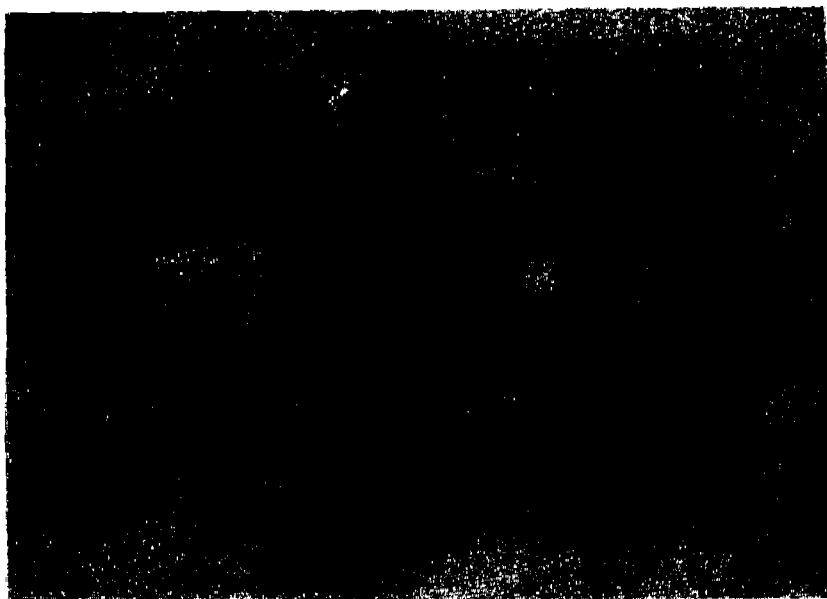


नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

का.आ. 864.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथावत बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग III यथार्थता वाली स्वतःसूचक, अस्वचालित, स्टील फीता रूल के माडल का जिसके "प्लास्टिक ओपन रील" श्रृंखला का है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स प्रीमेन्स मैजर्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 787, लुधियाना-141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी. 09/98/160 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल वर्ग III का स्टील फीता रूल है, जिसकी लम्बाई 30 मीटर और प्रत्येक सेंटीमीटर पर अंशांकित है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषित करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला और यथार्थता वर्ग के फीता माप भी होंगे, जिनकी लम्बाई 100 मीटर तक होगी। जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(118)/97]

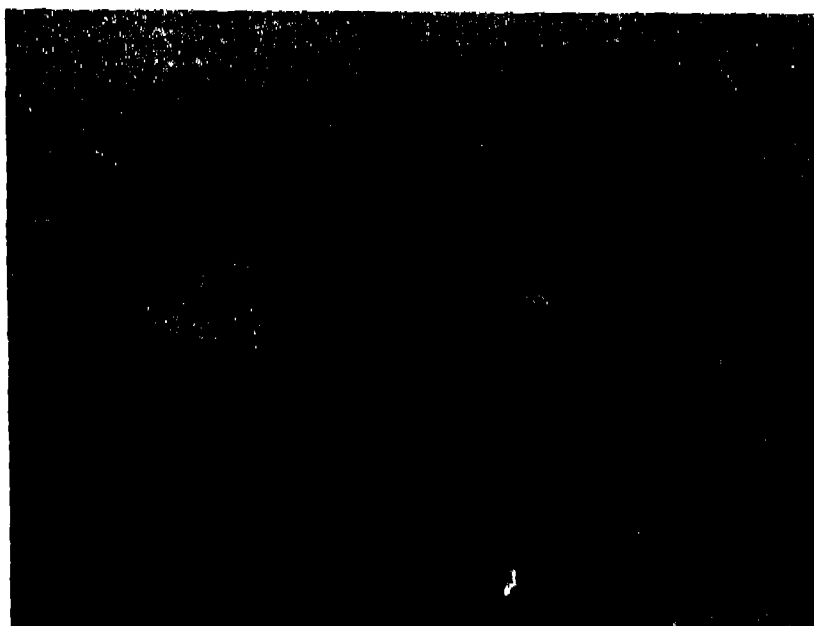
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 864.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Steel Tape Rules of "Plastica Open Reel" series (hereinafter referred to as the Model) of accuracy class III manufactured by M/s. Freemans Measures Limited, Post Box No. 787, Ludhiana-141 003 and which is assigned the approval mark IND/09/98/160.

The model is a Steel Tape Rule of accuracy class III with length of 30 meter and graduated at every centimeter.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover tape measures of same series and accuracy class of length upto 100 meter, manufactured by the same manufacturer with the same design and materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (118)/97]

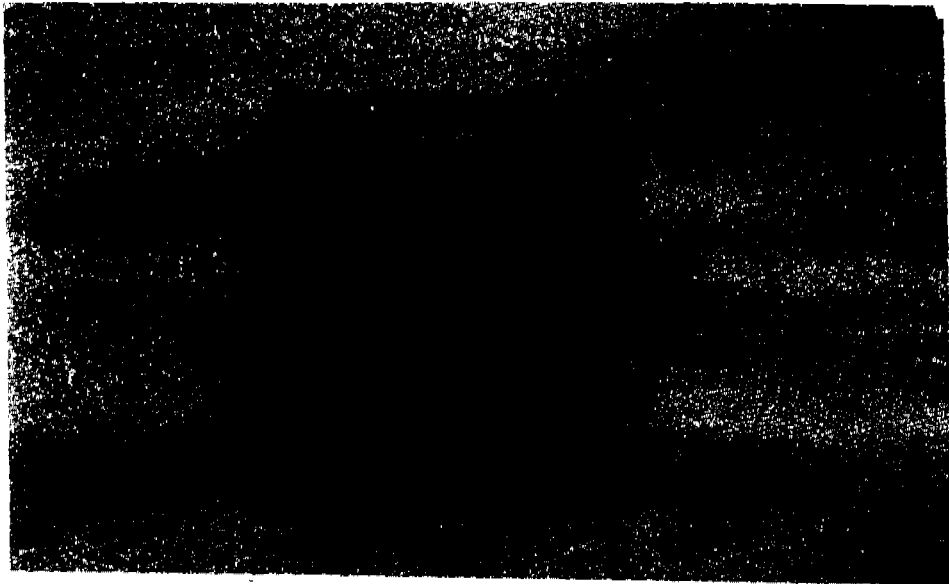
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

का.आ. 865.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II यथार्थता वाली पी वी सी घिलेपित फाइबर फ्रांच के फीता माप के माडल का "कॉन्फेक्स और सेंटोफुलेक्स" श्रृंखला का है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैमर्स प्रीमेन्स मेजर्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं. 787, लुधियाना-141003 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी. 09/98/159 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल यथार्थता वर्ग II का स्टील फीता मापन है, जिसकी अधिकतम लम्बाई 3 मीटर है और प्रत्येक मिलीमीटर पर अंशांकित है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला और यथार्थता वर्ग के फीता माप भी होंगे जिनकी लम्बाई 1 मीटर और 2 मीटर की होगी। जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(118)/97]

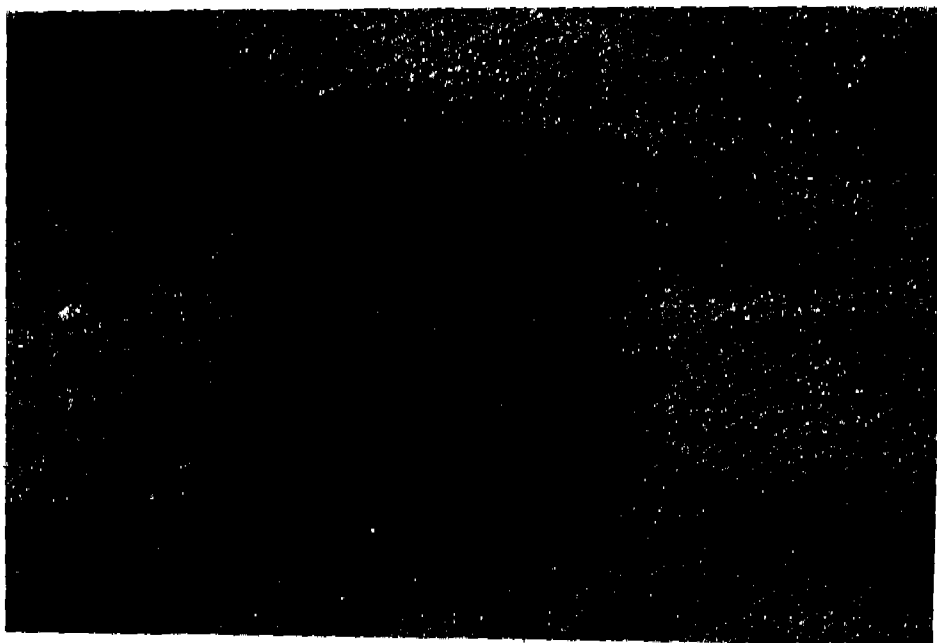
पी. एं. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 865.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of PVC coated Fiberglass tape measure of 'Conflex' and 'Centiflex' series (hereinafter referred to as the Model) of accuracy class II manufactured by M/s. Freemans Measures Limited, Post Box No. 787, Ludhiana-141 003 and which is assigned the approval mark IND/09/98/159.

The model is a Steel measuring tape of accuracy class II with length of 3 meter and graduated at every millimeter.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover tape measures of same series and accuracy class and with length of 1 and 2 meter, manufactured by the same manufacturer with the same design and with the same materials with which the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (118)/97]

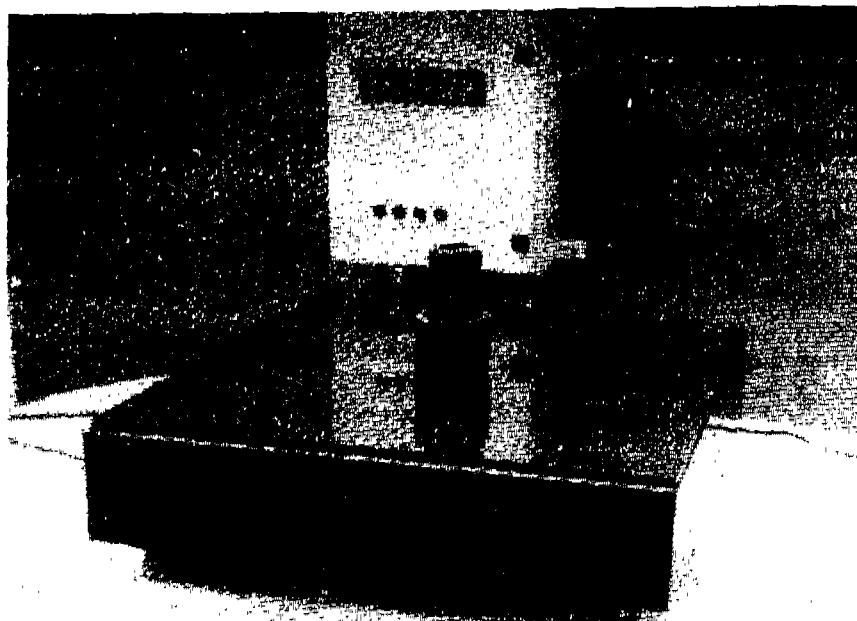
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

**का.आ. 866.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग III यथार्थता (मध्यम यथार्थता) वाली "के पी एस" श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वच्छालित, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "कोमल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मेसर्स कोमल प्रोसेस कंट्रोल्ल्स, ए 32, मनीप काम्प्लेक्स, सं. 10, कार्वेट रोड, बंगलौर-560025 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/98/103 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 300 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 2 किलो ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 100 ग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत घ्यलकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारग्राही समकोणिक है जिसकी भुजाएं 600×600 मिलीमीटर है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 (एन < 10,000) से कम या उसके बराबर है जिसका "ई" मान 1,2,5 श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम-21(125)/97]

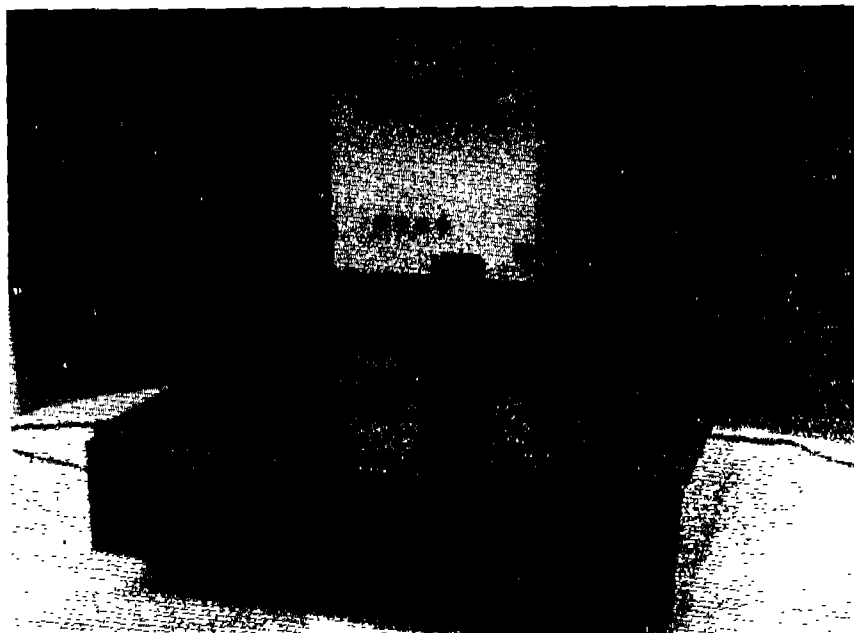
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 866.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report (see the Figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic platform weighing machine of type "KPS" series of class III accuracy (medium accuracy) and with brand name, "KOMAL" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Komal Process Controls , A 32, Manish Complex, No 10, Convent Road, Bangalore--560025, and which is assigned the approval mark IND/09/98/103.

The said model is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 300 kg and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of square section of sides 600×600 millimetre. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value of 1, 2, 5 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (125)/97]

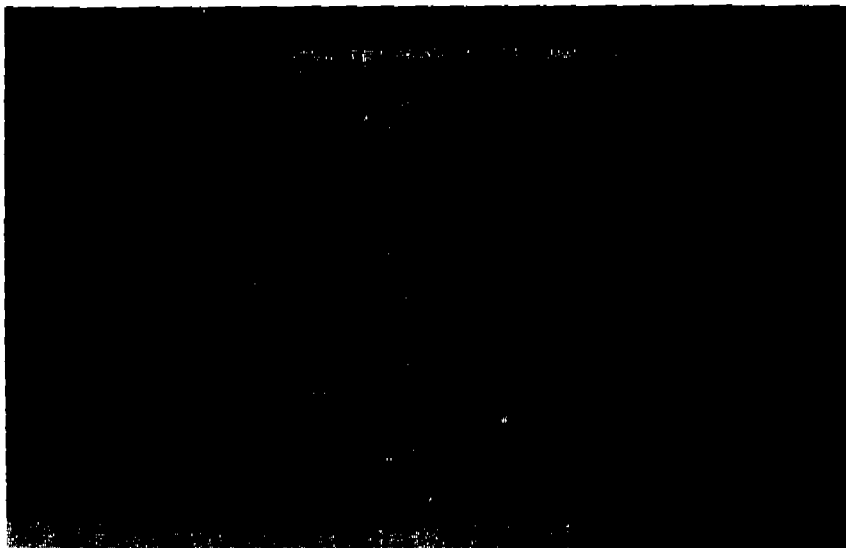
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

का.आ. 867.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते वर्ग II यथार्थता (मध्यम यथार्थता) वाली "के डब्ल्यू बी" वाली श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वचालित, इलेक्ट्रानिक तुला यौकी के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "कोमल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मेसर्स कोमल प्रोसेस कंट्रोल्ल्स, ए-32, मनीष काम्प्लेक्स, सं. 10, कॉम्पेंट रोड, बंगलौर-560025 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/104 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल (आकृति देखें) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 40000 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 किलो ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 10 किलो ग्राम है। इसमें एक आघेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आघेयतुलन प्रभाव है। भार ग्राही चर्गाकार है जिसकी भुजाएं 9×3 मिलीमीटर है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त उपधारा की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 (एन < 10,000) से कम या उसके बराबर है जिसका तथा "ई" मान 1, 2, 5 श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(125)/97]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 12th March, 1999

**S.O. 867.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic weightbridge of type “KWB” series of class III accuracy (medium accuracy) and with brand name, “KOMAL” (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Komal Process Controls, A 32, Manish Complex, No 10, Convent Road, Bangalore--560025, and which is assigned the approval mark IND/09/98/104.

The said model is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 40000 kg and minimum capacity of 200 kg. The verification scale interval (e) is 10 kg. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 9×3 metre. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification Scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value of 1, 2, 5 series, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (125)/97]

P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

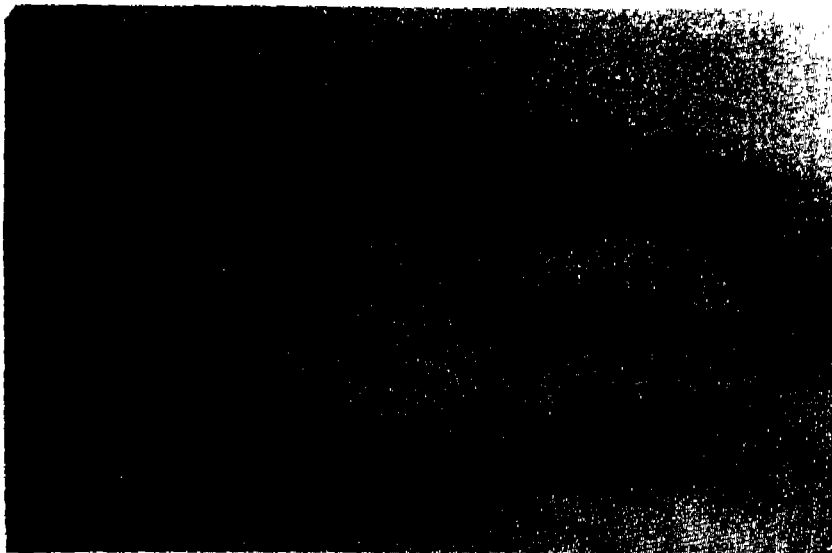


नई दिल्ली, 13 मार्च, 1999

का.आ. 868.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग III यथार्थता (मध्यम यथार्थता) वाली "वाई एस" श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वच्छालित, मेज तल तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "यश वेइंग स्केल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मेसर्स यश वेइंग स्केल, प्लॉट 7/8 ठाकरे दीप सोसायटी, बसंत विहार अपार्टमेंट के निकट यूनिवर्सिटी रोड सूरत गुजरात द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/169 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल (आकृति देखें) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 30 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 5 ग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भार ग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 270×380 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के तोलन उपकरण भी होगा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 (एन < 10,000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1, 2, 5 श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(11)/98]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th March, 1999

**S.O. 868.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, table top type weighing instrument of type "YS" series of class III accuracy (medium accuracy) and with brand name, "YASH WEIGHING SCALE" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Ycash Weighing Scale, Plot 7/8, Thakoredip Soc, Near Vasanth Vihar Apartment, University Road Surat Gujarat, and which is assigned the approval mark IND/09/98/169.

The said model is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 30 kg and minimum Capacity of 100 g. The verification scale interval (e) is 5 g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 270×380 millimetre. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50 Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum number of verification Scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value to 1, 2, 5 series, manufactured by the same manufacturer with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (11)/98]

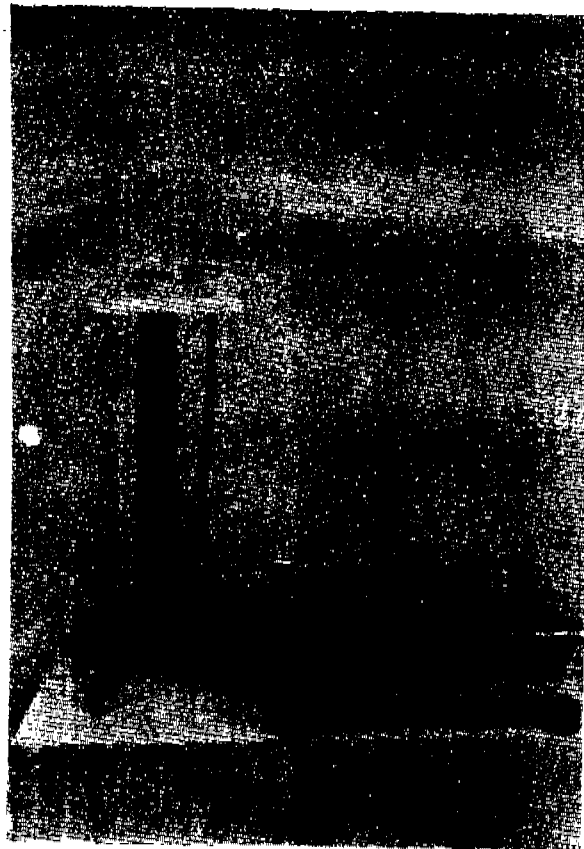
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1999

का.आ. 869.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ग III यथार्थता (मध्यम यथार्थता) वाली "वाई एम" श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वचालित, प्लेटफार्म तोलन मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "यश वेइंग स्केल" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स यश वेइंग स्केल, प्लॉट 7/8 ठाकरे दीप सोसायटी, बसंत विहार अपार्टमेंट के निकट यूनिवर्सिटी रोड सूरत गुजरात द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/168 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल (आकृति देखें) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 10 ग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भार ग्राही आयाताकार है जिसकी भुजाएं 550×650 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के तोलन उपकरण भी होगा। जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 (एन  $\leq$  10,000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1,2,5 श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(11)/98]

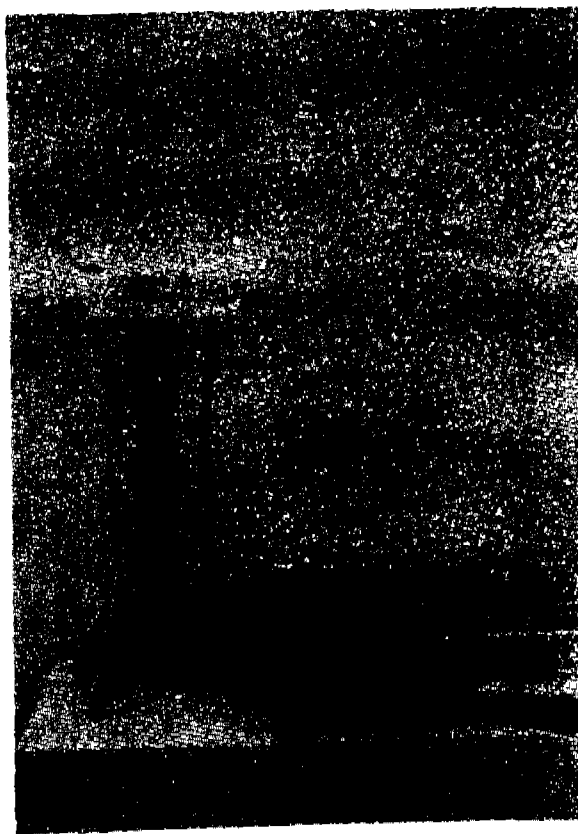
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th March, 1999

**S.O. 869.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, platform type weighing instrument of "YS" series of class III accuracy (medium accuracy) and with brand name, "YASH WEIGHING SCALE" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Yash Weighing Scale, Plot 7/8, Thakoredip Soc, Near Vasanth Vihar Apartment, University Road Surat Gujarat, and which is assigned the approval mark IND/09/98/168.

The model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kg and minimum capacity of 200 g. The verification scale interval (e) is 10 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 550×650 millimetre. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50 Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section, 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $\leq 10,000$ ) and with 'e' value to 1,2,5 series, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (11)/98]

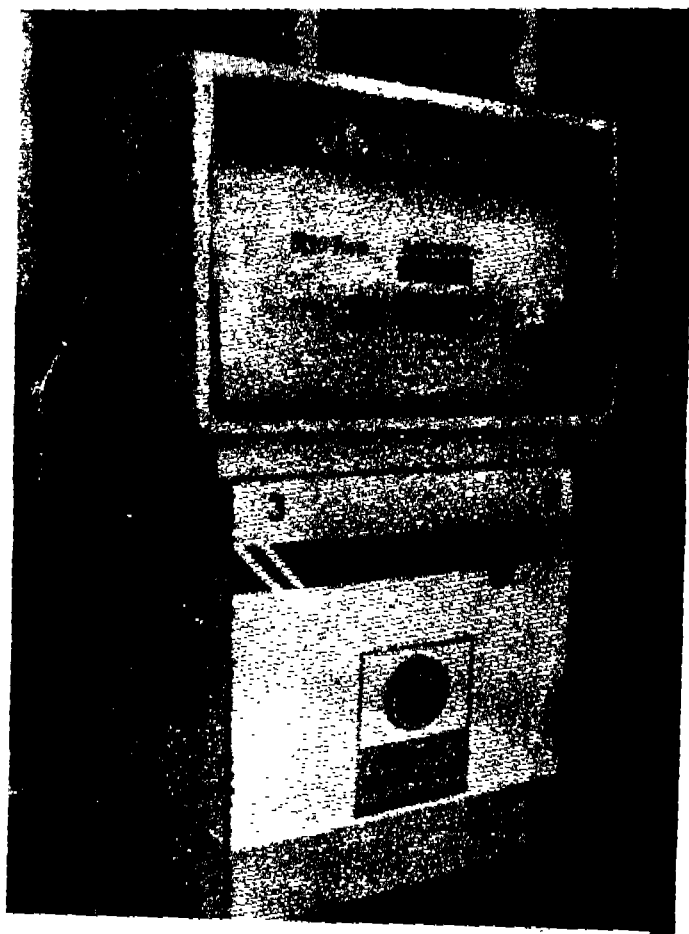
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1999

का.आ. 870.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और वाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथाथता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “एल सी डी 50 एस” श्रृंखला की, यांत्रिक डिसपेंसिंग प्रकार के पम्प द्रव क्रिस्टल प्रदर्श में संपरिवर्तन के लिए किट के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम “सुकाम” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स सुकाम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, 306 कीर्तिदीप, नागल राय बिजिनेस सेंटर, नई दिल्ली-110046 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/133 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल यांत्रिक पेट्रोल पंप को अंकक प्रदर्श मशीन में संपरिवर्तन के लिए संपरिवर्तन किट का है। मात्रा 6 अंकक द्रव क्रिस्टल प्रदर्श द्वारा उपदर्शित की जाती है और संदेय की जाने वाली रकम भी 6 अंकक द्रव क्रिस्टल प्रदर्श द्वारा उपदर्शित की जाती है। सत्यापन मापमान अन्तराल 1 मिलिमीटर है। अधिकतम प्रवाह पर 40 लीटर/मिनट है।



[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(101)/97]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th March, 1999

**S.O. 870.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report ( figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the kit for converting mechanical dispensing pump of type LCD 50S series and with brand name "SUKAM" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Sukam Systems Private Limited, 306, Kirti Deep Nangal Raya Business Centre, New Delhi-110046, and which is assigned the approval mark IND/09/98/133;

The said model is a conversion kit for converting mechanical petrol pumps into machines with digital display. The volume is indicated by 6 digit liquid crystal display and the amount to pay is indicated by a 6 digit liquid crystal display. The scale interval is 1ml . The maximum flow rate is 40 liter/minute.



[F. No. WM 21 (101)/97]

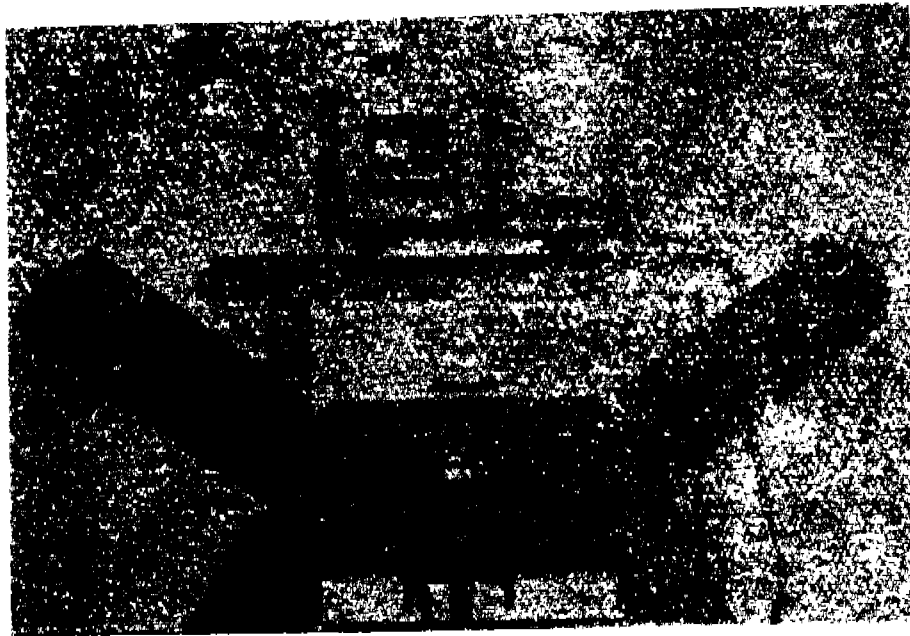
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1979

क्र.सं. 871.—केंद्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) वायु और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 10) और वायु और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवस्था में जो उक्त माडल यथावत बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में समुचित सेवा करता रहेगा,

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "एम सी 1000 सहित 475" श्रृंखला की, एक, व्यवस्थित, वेस्ट तोलन मशीन के माडल का जिसके ब्रांड का नाम "एवरी" है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण रैसर्स एवरी प्रा. लि. मिडिलेड, प्लान नं. 50-54, मेबर 25, बल्लभगढ़-121004 हरियाणा द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन विनं. नं. आई एल डी-13/98/... अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल निरंतर वेस्ट तोलन वेस्ट तोलन की न्यूनतम गति तीन मीटर/सेकंड है मशीन का है, जिसकी अधिकतम मशीन का प्रवाह दर 72 टन/घंटा और न्यूनतम प्रवाह दर 14.4 टन/घंटा है। मापमान अन्तराल ई 1 किलोग्राम और तोल सम्भाव्य 1 मीटर है अधिकतम प्रति यूनिट सम्भाव्य भार 20 किलोग्राम/मीटर है।



और, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अन्तर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा जिसकी अधिकतम प्रवाह दर 1 टन/घंटा से 2000 टन/घंटा हो तथा जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[क्र. सं. डब्ल्यू एम-21(102)/97]

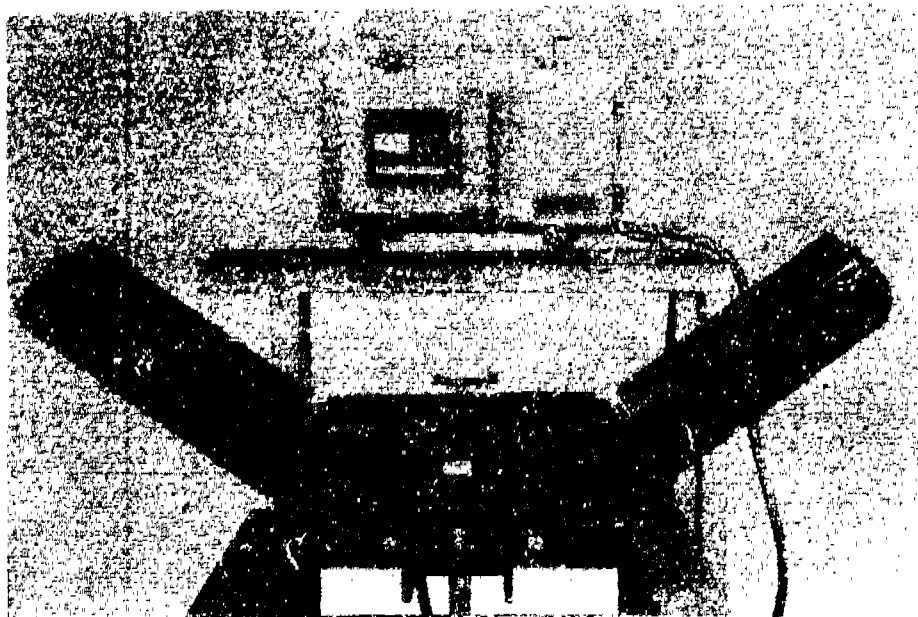
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th March., 1999

**S.O. 871.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, automatic belt weighing machine of type “475” series with MC 1000 controller and with brand name “AVERY” (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s Avery India Limited, Plot No. 50-54, Sector 25, Ballabhgarh-121004, and which is assigned the approval mark IND/09/98/132.

The said model is a continuous belt weighing machine with a maximum flow rate of 12 tonne/hour and minimum flow rate of 14.4 tonne/hour. The nominal speed of the belt weigher is three metre/sec. The scale interval is 1 kg and weigh length is one metre. The maximum load per unit length is 20 kg/metre.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum flow rate of 1 tonne/hour to 2000 tonne/hour, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (102)/97]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology



नई दिल्ली, 13 मार्च, 1999

का.आ. 872.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उस प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथावत बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "के आर पी" श्रृंखला की द्रवित प्रोपेन गैस के लिए डिस्पेंसर के माडल का, (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स क्राउन इंडस्ट्रीज लि., 204, डेस्ट्रीट, विन्नीपाग, मनीटोवा, आर 2सी 1 ए यी, कनाडा द्वारा किया गया है और भारत में मैसर्स जी एण्ड टीएमएचवी इंनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि., नई दिल्ली द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/98/118 समनुदेशित किया है, अनुमोदन, प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



यह माडल (आकृति में दिया गया है) 12 से 50 लीटर प्रति मिनट की प्रवाह दर का द्रवित प्रोपेन गैस के लिए डिस्पेंसर है। इसमें माइक्रान 100 या माइक्रान 200 का रजिस्टर लगा हुआ है।

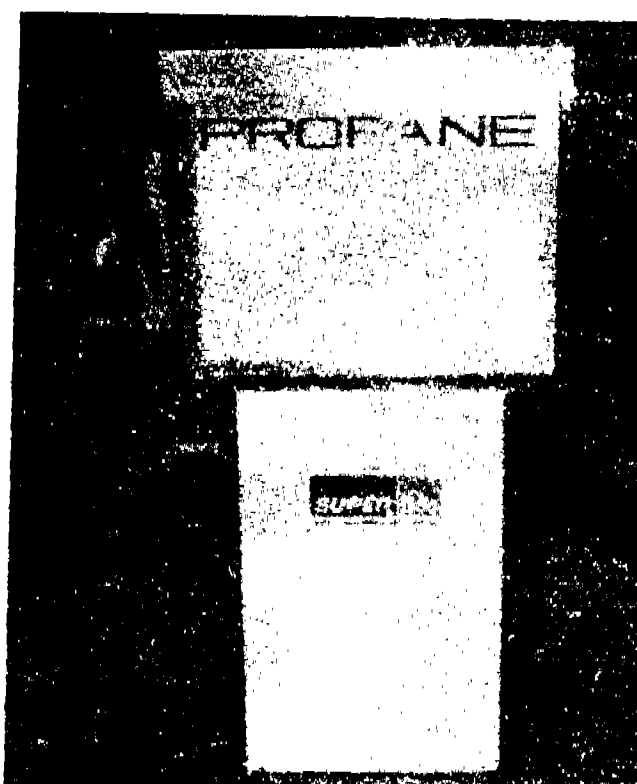
[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(121)/97]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 13th March, 1999

**S.O. 872.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Dispenser for liquefied propane gas of KRP series (hereinafter referred to as the Models) manufactured by M/s Kraus Industries Ltd., 204 Day Street, Winnipeg, Manitoba, R2C 1A8, Canada and used in India by M/s G&T-SHV Energy Distribution Co. Ltd., New Delhi and which is assigned the approval mark IND/09/98/118 :



The model (given in the figure) is a Dispenser for liquefied propane gas with flow rate of 12 to 50 litre per minute. It is fitted with register of Micron 100 or Micron 200 type.

[F. No. WM-21 (121)/97]

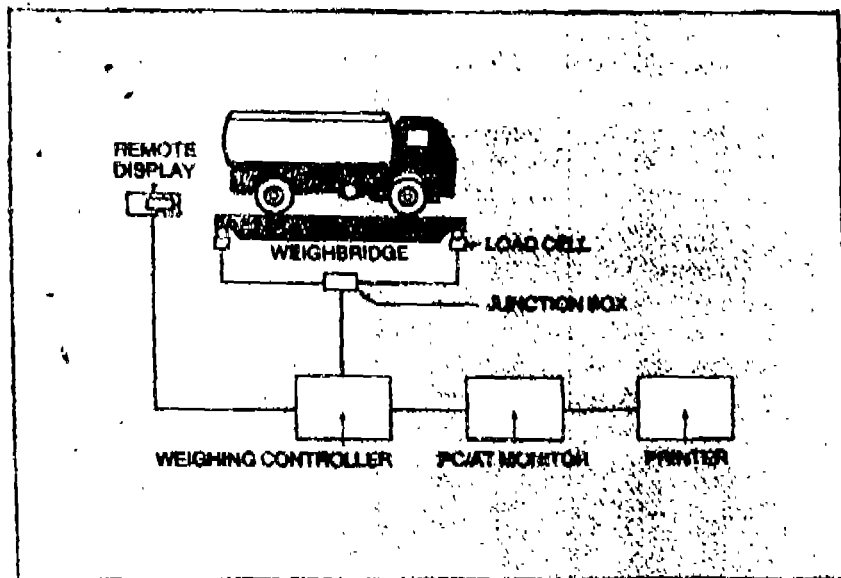
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1999

**का.आ. 873.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते वर्ग III यथार्थता (मध्यम यथार्थता) वाली "डिमोमेट जे आर बी" शृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वचालित, इलेक्ट्रॉनिक, तुला चौकी तोलन मशीन के माडल का, जिसके बांड का नाम "सबैक" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स जेनसन एण्ड निकोलसन इण्डिया लिमिटेड, 225, ए जे सी बोम रोड कलकत्ता-20, द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी. 09/98/102 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 40 टन है और न्यूनतम क्षमता 200 किलोग्राम है। सत्यापन मापमान (ई) 10 किलोग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भारी ग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 9×3 मीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 (एन < 10,000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1, 2, 5 शृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(8)/94]

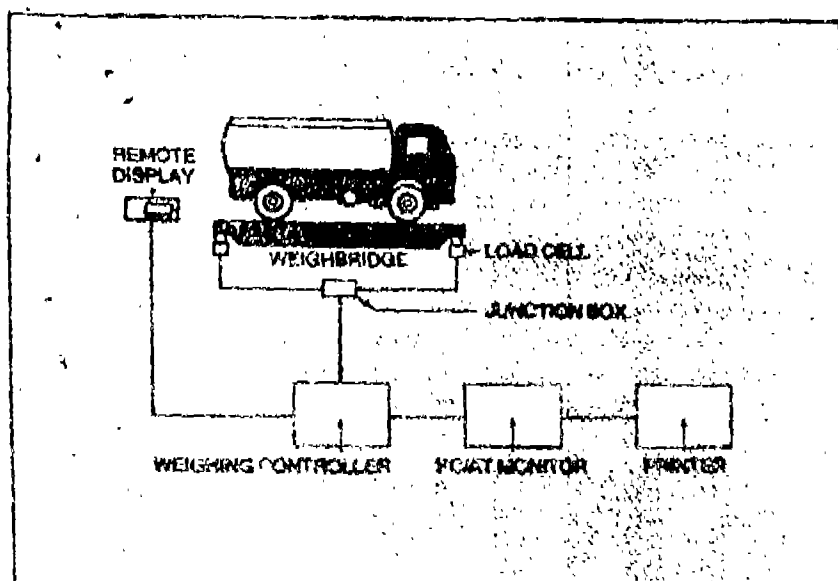
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 15th March, 1999

**S.O. 873.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain the accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic weighbridge of type "DISOMAT JRB" series of class III accuracy (Medium accuracy) and with brand name "SCHENCK" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Jenson & Nicholson India Limited, 225, AJC Bose Road, Calcutta-20, and which is assigned the approval mark IND/09/98/102;

The said Model is a Medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 40 tonne and minimum capacity of 200kg. The verification scale interval (e) is 10kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 2×3 meter. The light emitting diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value of 1.2.5 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (8)/94]

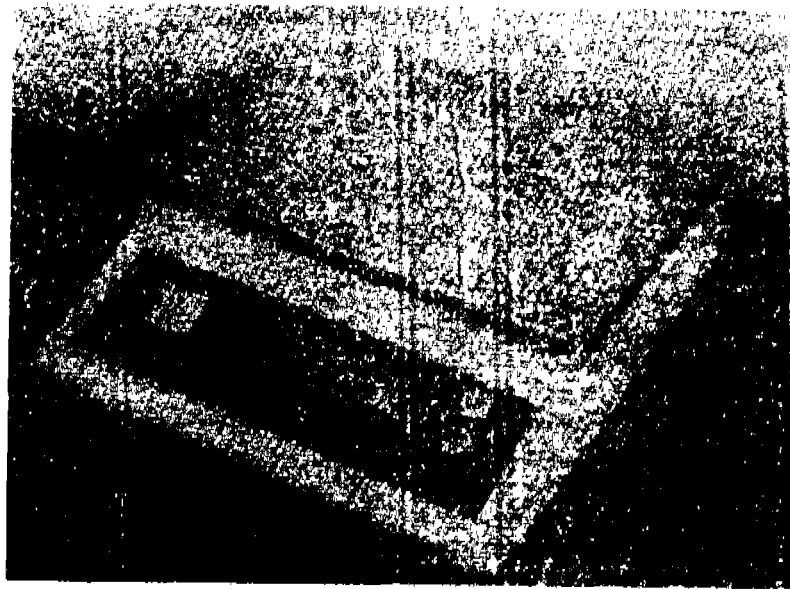
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1999

का.आ. 874.—केंद्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधियों में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा करता रहेगा,

अतः, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग II यथार्थता (उच्च यथार्थता), सततः संचालित, इलेक्ट्रॉनिक, मेजगतल तोलन मशीन के माडल का, जिसके बांड का नाम "माइक्रान" है (जिसे इनमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैन्स माइक्रान इलेक्ट्रॉनिक वेइंग सिस्टम, पी-7, मोहन इस्टेट, खोखरा, अहमदाबाद-380008 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी. 09/98/124 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल उच्च यथार्थता (उपधारा वर्ग II) का तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 22 किलो ग्राम और न्यूनतम क्षमता 50 ग्राम है। सत्यापन मापमान (ई) 1 ग्राम है। इसमें एक आद्यचतुरास गुणित है जिसका अंत प्रतिपाद चकलनात्मक धारित आद्यचतुरास प्रभाव है। भारी ग्रामी आकृताकार है जिसकी भुजाएं 250 × 215 मिलीमीटर हैं। प्रकाश उत्सर्जक तथोपकरणों से तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 (एन  $\leq$  10,000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1, 2, 5 शृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(35)/96]

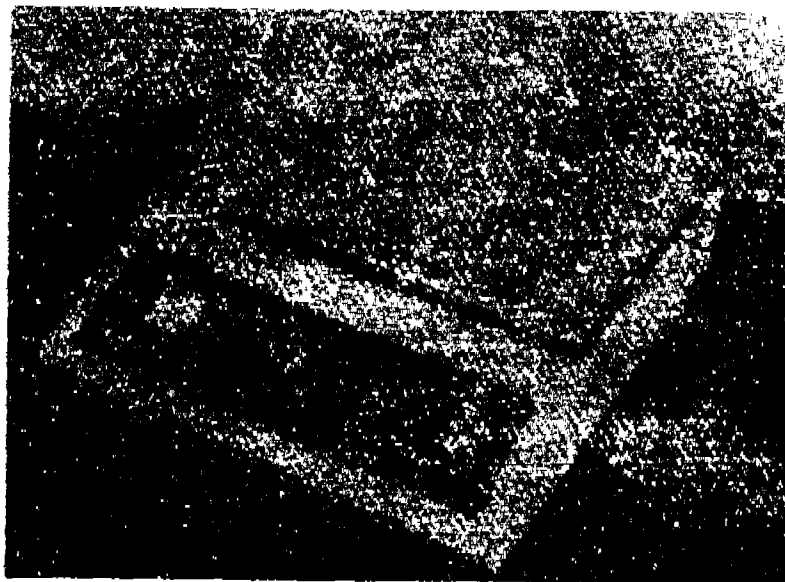
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 15th March, 1999

**S.O. 874.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, electronic table top weighing machine of class II accuracy (high accuracy) and with brand name "Micron" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Micron Electronic Weighing System, B-7, Mohan Estate, Khokhra, Ahmedabad-380008 and which is assigned the approval mark IND/09/98/124;

The said Model is a high accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 22 kg and minimum capacity of 50g. The verification scale interval (e) is 1g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular shape of sides 250 × 215 millimeter. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification scale interval (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value of 1,2,5 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (35)/96]

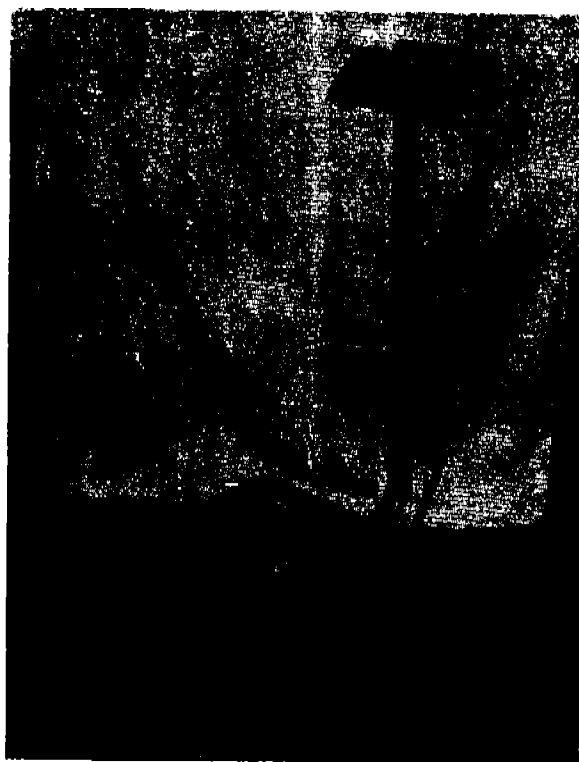
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1999

का.आ. 875.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और संभावना यह है कि अविरत उपयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ग III यथार्थता (मध्यम यथार्थता), वाली "सी ई" श्रृंखला की, स्वतःसूचक, अस्वचालित, तोलन मशीन (प्लेटफार्म प्रकार की) के माडल का जिसका ब्रांड नाम "केल्ट्रान स्केलेक्स" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मेसर्स काल्ट्रान स्केलेक्स, 1, जगत नगर सोसाइटी, दिनेश के सामने, इंडिया कालोनी रोड, बापू नगर, अहमदाबाद द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी. 09/98/138 समनुदेशित किया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

यह माडल मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 120 किलो ग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) 20 ग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। भार ग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 500×550 मिली मीटर है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 चोस्ट और 50 हर्टज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यकरण वाला ऐसा तोलन उपकरण भी होगा, जिसका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है और जिसके सत्यापन मापमान का अन्तराल (एन) की अधिकतम संख्या 10,000 (एन  $\leq$  10,000) से कम या उसके बराबर है तथा जिसका "ई" मान 1,2,5 श्रृंखला का है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(72)/96]

पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 15th March, 1999

**S.O. 875.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, weighing instrument (platform type) of "CE" series of class III accuracy (medium accuracy) and with brand name "CALTRON SCALEX" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Caltron Scalex, Jagatnagar Society, Opp. Dinesh, India Colony Road Bapunagar Ahmedabad and which is assigned the approval mark IND/09/98/138;

The said Model (See figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 120 kg and minimum capacity of 400g. The verification scale interval (e) is 20g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular shape of sides 500x550 millimeter. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts 50 hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum number of verification scale Division (n) less than or equal to 10,000 ( $n \leq 10,000$ ) and with 'e' value of 1,2,5 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (72)/96]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director, Legal Metrology



## श्रम मंत्रालय

## SCHEDULE

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1999

का.आ. 876:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.एम. पी.डी. आई.एल. के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं 2 (धनबाद) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-2-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-20012(210)/94-आई.आर. (सी.-I)]

श्याम सुंदर गुप्ता, डेस्क अधिकारी

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th February, 1999

S.O. 876.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad-2 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of C.M.F.D.I.L. and their workman, which was received by the Central Government on 16-2-99.

[No. L-20012/(210)/94 IR(C-I)]

S. S. GUPTA, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2)  
AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 92 OF 1995

PARTIES :

Employers in relation to the management of  
C.M.P.D.I. L., Ranchi and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None.

On behalf of the employers : None

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad the 9th February, 1999

## AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(210)/94-I.R. (Coal-I), dated, the Nil.

787 GI/99-12

“Whether the action of the management of Central Mine Planning & Design Institute Ltd., Ranchi is justified in denying promotion to the workmen S/Shri P. Chakraborty, S. K. Tiwary, J. Sharma, R. C. Balmiki, Surendra Kumar Sharma, Haripal and Smt. Sushma Das from Clerk Gr. III to Gr. II when Smt. Bimla Singh and 15 others were promoted from Clerk Gr. III to Gr. II without holding typing test? If not, to what relief these workman are entitled and from what date?”

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were served upon the parties. But neither of the parties turned up nor took any steps. Then again and again notices were issued to them but in spite of the issuance of notices they abstained from appearing before this Tribunal and taking any steps leading to an inference that presently there is no dispute existing between the parties. Under the circumstances, a ‘No dispute’ Award is being rendered and the reference is disposed of on ‘No dispute’ Award basis presuming that no industrial dispute is existing between the parties presently.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1999

का.आ. 877:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार में बी.सी.सी.एल. के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण धनबाद-2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-3-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-20012 (282)/92-आई.आर. (सी.-1)]

श्याम सुंदर गुप्ता, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th March, 1999

S.O. 877.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad-2 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-3-97.

[No. L-20012/(282) '92-IR(C-I)]

S. S. GUPTA, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 306 of 1993

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kustore Colliery of M/s. B.C.C.L. and their workman.

## APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None.

On behalf of the employers : None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 23rd February, 1999

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(282)/92-I.R.(Coal-I), dated, the 30th September, 1993 :

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kustore Colliery of M/s. BCC Ltd., in denying categorisation of the workman in Excavation Grade 'C' w.e.f. March, 1986 and Excavation Grade 'B' from March, 1989 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. In this reference none of the parties turned up in spite of the issuance of notices to them. Then again and again notices were served upon them. But in spite of the service of notices both the parties neither appeared before this Tribunal nor took any steps leading to an inference that presently there is no dispute existing between the parties. Under the circumstances, this Tribunal has been left with no other alternative but to pass a 'No dispute' Award in this reference. The reference is accordingly disposed of on 'No dispute' Award basis.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1999

का.आ. 878 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी.एल. के प्रबन्धतंत्र के संशुद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण धनबाद-2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 3/3/99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/316/92-आई.आर. (सी-I)]

एस.एस. गुप्ता, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th March, 1999

S.O. 878.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad-2 as shown in the Annexure to the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-3-99.

[No. L-20012/316/92-IR(C-I)]

S. S. GUPTA, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 190 of 1993

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Basantimata Colliery of M/s. BCCL Area No. XII and their workmen.

## APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None.

On behalf of the employers : None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 23rd February, 1999

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(316)/92-I.R.(Coal-I), dated, 3/9-11-93 :

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Basantimata Colliery of M/s. B.C.C.L. Area No. XII in dismissing workman Shri Subash Sethi with effect from 30-3-1992 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. But both the parties abstained from appearing before this Tribunal and taking any steps. Then again and again notices were issued to them but in spite of the issuance of notices to them they neither appeared before this Tribunal nor took any steps leading to an inference that presently there is no dispute existing between the parties. Under such circumstances this Tribunal has been left with no other alternative but to pass a 'No dispute' Award in this reference. Thus a 'No dispute' Award is being rendered and the reference is disposed of on 'No dispute' Award basis.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1999

का.आ. 879 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी.एल. के प्रबन्धतंत्र के संशुद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण धनबाद-2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-3-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-20012/(354)/92-आई.आर. (सी.-I)]

व्याम सुन्दर गुप्ता, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th March, 1999

S.O. 879.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad-2 as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-3-1999.

[No. L-20012/(354)/92-IR(C.I)]

S. S. GUPTA, Desk Officer.

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT  
DHANBAD

## PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 184 of 1993

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Barora Coal Washery of M/s. BCCL and their workmen.

## APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None.

On behalf of the employers : None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 23rd February, 1999.

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(354)/92-I.R.(Coal-I), dated, the 5/9-11-93.

## SCHEDULE

"Whether the action of the Chief General Manager, Barora Washery Organisation of M/s. B.C.C.L. is denying to promote Sh. Brahamdeo Pd. Mandal, Elect. Cat. V w.c.f. 23-4-1988 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. But both the parties abstained from appearing before this Tribunal and taking any steps. The reference proceeded its course and then again notices were issued to both the parties. But neither of the parties turned up before this Tribunal nor took any steps leading to an inference that presently there is no dispute existing between the parties. Under such circumstances a 'No dispute' Award is being rendered and the reference is disposed of on 'No dispute' Award basis.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1999

का० आ० 880.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर के प्रबन्धक के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण,

जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-2-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/81/95-आई.आर. (बी.-1)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th February, 1999

S.O. 880.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner & Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 23-2-1999.

[No. L-12012/81/95-IR (B-I)]

SANATAN, Desk Officer

अनुवन्ध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय  
जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्री चांदमल तोतला, आर.एच.जे.एस.

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संख्या 6/1996

श्री जितेन्द्रकुमार सिधवी द्वारा जोनल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय  
स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर कर्मचारी संघ एस.बी.  
बी. जे. मुराणा मार्केट शाखा, पाली मारवाड़।

\* \* \* प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबंधक-II, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर जोनल  
ऑफिस जोधपुर।

\* \* \* अप्रार्थी

उपस्थिति :—

(1) प्रार्थी प्रतिनिधी श्री ललित शर्मा उपस्थित।

(2) अप्रार्थी प्रतिनिधी श्री मनोहर लाल पुरोहित उपस्थित।

अधिनियम

दिनांक 06-1-1999

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या 12012/  
81/95-आई.आर. (बी.) दिनांक 24-6-96 से श्रमिक  
कर्मचारी तथा उसके नियोजक के मध्य उत्पन्न हुआ निम्ना-  
ंकित औद्योगिक विवाद इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को  
निर्णय हेतु प्रेषित किया गया तथा 20-8-1996 को नियमित  
औद्योगिक विवाद संख्या 6/96 पंजीकृत हुआ :—

"Whether the action of Regional Manager-II S.B.B.J., Zonal Office, Jodhpur in not considering the application dated 4-8-1992 of Sh. Jitendra Kumar Singhvi for withdrawing the consent for the Head Cashier is legal and justified? If not, to what relief the concerned worker is entitled?"

उपरोक्तानुसार निर्णय हेतु प्रेषित विवाद तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र व उसके उत्तर को देखते हुए यह प्रकट होता है कि विवाद कर्मचारी को मुख्य लिपिक के पद पर पदोन्नत कर बाहर स्थानान्तरित करना उचित है। संबंधित कर्मचारी श्री जितेन्द्र कुमार ने इसे अवैधानिक व अनुचित बताते हुए अखिल भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ ब्रीकानेर एण्ड जयपुर कर्मचारी संघ के अंचल सचिव के माध्यम से प्रस्तुत अपने आवेदन में बताया है कि यह संगठन बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा प्रार्थी कर्मचारी भी इस संघ का सदस्य है। आवेदन के अनुसार प्रार्थी की नियुक्ति कैशियर/गोदामपाल के पद पर स्टेट बैंक ऑफ़ ब्रीकानेर एण्ड जयपुर के सुराणा मार्केट पाली में हुई थी तथा उसका अग्रिम प्रधान लिपिक के पद हेतु किया गया व इस पद पर उसकी नियुक्ति सुमेरपुर शाखा में की जानी प्रस्तावित थी जिस हेतु प्रार्थी ने अपनी सहमति दी हुई थी परन्तु प्रार्थी ने विपक्षी नियोजक बैंक के दिनांक 29-6-92 के परिपत्र के अनुसार अपनी इस सहमति को वापस लेकर अर्थात् “बिड़ो” की एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र सुराणा मार्केट शाखा प्रबन्धक को 30-6-92 को प्रेषित कर दिया जिसके द्वारा उसी दिन क्षेत्रीय प्रबन्धक चतुर्थ ज़ोनल ऑफिस जोधपुर को अग्रेषित कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा सहमति वापस ले लेने के बावजूद भी प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रधान लिपिक के पद पर सुमेरपुर कर दिया गया। बताया गया कि जब प्रार्थी ने अपनी सहमति वापस ले ली थी तो उसके इस स्थानान्तरण का कोई औचित्य नहीं था तथा उसे सुराणा मार्केट पाली में ही रखा जाना था जिस हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया परन्तु ध्यान नहीं दिया एवं जानबूझकर उसे रिलीव कर दिया गया तथा इस पर कर्मचारी संघ ने श्रम विभाग में यह कार्यवाही प्रारम्भ की जिस पर यह विवाद प्रारम्भ हुआ। बताया गया कि प्रार्थी का स्थानान्तरण अनुचित एवं अवैध है। प्रार्थना की गई कि स्थानान्तरण को अवांछनीय एवं अवैध घोषित करते हुए प्रार्थी को सुराणा मार्केट पाली शाखा में स्थापित किया जावे।

विपक्षी ने अपने उत्तर में बताया है कि कर्मचारी सुराणा मार्केट पाली शाखा में कैशियर नियुक्त था तथा बैंक के 7-6-91 के पत्र के जरिये बैंक की सभी शाखाओं को सूचित किया कि जिन कर्मचारियों ने 1-4-91 को पांच वर्ष की सेवा कर ली है वे प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्ति के पात्र हैं। अतः इच्छुक प्रार्थी/कर्मचारी प्रार्थना-पत्र प्रेषित करे-कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली सहमति स्थान विशेष के लिए लिए हुई थी तथा कर्मचारी ने किसी स्थान के लिए सहमति दी हो तो उसे वापस लेने की न तो अनुमति थी न ही ऐसा सम्भव था। उत्तर में बताया गया है कि प्रार्थी ने सुमेरपुर शाखा में प्रधान लिपिक पद पर अपनी इच्छा व सहमति व्यक्त की थी तथा प्रधान लिपिक के इस पद पर स्पेशल एलाउन्स भी देय था व प्रार्थी की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही उसे सुराणा मार्केट पाली में 22-8-92 को सुमेरपुर शाखा में प्रधान लिपिक के लिए रिलीव किया गया जहां प्रार्थी ने अपना कार्य जोड़ने किया। उत्तर में बताया

गया है कि प्रार्थी की सहमति पर ही उसकी यह नियुक्ति की गई थी तथा एक बार सहमति देने के बाद सहमति वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था व 30-6-92 को प्रार्थी ने जो पत्र प्रस्तुत किया वह मान्य नहीं था। यह भी बताया गया है कि प्रार्थी को स्पष्ट ज्ञान था कि एक बार सहमति देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती तथा जब प्रार्थी को प्रधान लिपिक सुमेरपुर के पद पर नियुक्त करने का निर्णय ले लिया गया था तो उसके बाद में सहमति में कोई भी परिवर्तन करना बैंक के कार्य में अवरोध भी पैदा करता है। बताया गया कि प्रार्थी का सुमेरपुर स्थानान्तरण करने में बैंक के किसी परिपत्र या नियम की अवहेलना नहीं की गई है तथा यह भी कहना असत्य है कि मन-मर्जी से द्वेष भावना से या जानबूझकर यह कार्यवाही की गई। उत्तर में यह भी बताया गया कि इस तरह विवाद उठाने का कोई भी अधिकार प्रार्थी को नहीं है तथा मांग व मांग-पत्र पूरी तरह से आधारहीन व गलत है। आवेदन अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

विपक्षी के उत्तर का प्रार्थी की ओर से प्रति उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि 29-6-92 के एक अन्य परिपत्र के अनुसार पूर्व में दी गई सहमति वापस ली जा सकती है तथा 29-6-92 का यह परिपत्र जारी होने के साथ ही पूर्व में जारी परिपत्रों का कोई भी प्रभाव नहीं रहा। यह भी बताया गया कि प्रार्थी ने एक अन्य कर्मचारी श्री श्रवणकुमार की जैतारण हेतु दी गई सहमति को भी उसे वापस लेने का अधिकार दिया तथा यह प्रावधान है कि स्वीकृति वापस लेने में दो वर्ष का (पदोन्नति नहीं) प्रावधान लागू होता है। बताया गया कि जारी किये गये नियुक्ति-पत्र में स्वीकृति वापस लेने का अधिकार था तथा 10-10-91 के परिपत्र में प्रार्थी को सूचित किया गया कि यदि प्रार्थी प्रधान लिपिक के पद पर जाने से मना करता है तो दो वर्ष का अवधि के लिए अवरोध किया जायेगा जिस पर प्रार्थी ने अपनी सहमति वापस ली। प्रार्थना की गई कि प्रार्थी के स्थानान्तरण को अनुचित श्रम अध्यास घोषित करते हुए नियोजक के प्रधान को निर्देश दिये जावे कि भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करे।

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से स्वयं प्रार्थी कर्मचारी जितेन्द्र कुमार का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदन में अंकितानुसार बताया गया तथा विपक्षी की ओर से प्रारम्भ में श्री राजेन्द्र प्रकाश का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु बाद में श्री मनोहरलाल पुरोहित का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिस शपथ-पत्र में उत्तर में अंकित तथ्यों के अलावा यह भी बताया गया कि प्रार्थी का सुमेरपुर स्थानान्तरण करने में कोई भी अनुचितता या अवैधानिकता नहीं थी तथा पुनः पाली स्थानान्तरण करने का प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार भी नहीं है परन्तु बैंक ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रार्थी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण सुमेरपुर से पाली कर दिया। शपथगृहताओं से प्रतिपरीक्षण भी हुआ

दस्तावेजों में बैंक के परिपत्रों इत्यादि की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गईं।

उभय-पक्ष के प्रतिनिधीगण के तर्क सुने पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने शपथ-पत्र पर अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने मुमैरपुर हैड कैंपियर की सहमती दी थी जो सहमती उसने वापस ले ली। विपक्षी अधिकारी श्री पुरोहित ने प्रतिपरीक्षण में जो बताया है उसके अनुसार पदोन्नति के बाद में प्रार्थी ने आवेदन किया कि वह हैड-क्लर्क नहीं बनाना चाहता जब कि पदोन्नति के पहले प्रार्थी ने सहमति दे दी थी। श्री श्रवणकुमार के मामले से अधिकारी ने अनभिज्ञता जाहिर की है। गवाह के अनुसार एक बार दी गई सहमति वापस लेने तथा वापस लेना भिन्न मामला है व स्थानान्तरण हो जाने के बाद में अलग से कोई सहमति नहीं मानी जा सकती क्योंकि सहमति होने पर ही आदेश निकलता है। सहमति व इस संबंध में उच्चाधिकारी के प्रमाण-पत्र के प्रकीर्ण की प्रतियां प्रस्तुत की गईं।

जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं वे 7-6-91, 22-10-90, 29-6-92 के परिपत्र हैं तथा प्रार्थी का वापस पाली स्थानान्तरण होने 25-3-97 का आदेश भी प्रस्तुत किया गया और कोई भी दस्तावेज किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। बैंक कर्मचारियों के सम्बन्ध में लम्बे समय से प्रभावी एक एवार्ड है जिसे कि शास्त्री एवार्ड के नाम से जाना जाता है। यह एवार्ड तर्कों के दौरान प्रस्तुत किया गया जिसमें पैराग्राफ 534 से 536 ट्रांसफर के बारे में है तथा इनको देखने से प्रकट होता है कि ट्रांसफर पर कोई सामान्य या इसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है न ही कोई शर्त अंकित की गई है। मोटे तौर पर यह बताया गया है कि कर्मचारियों की कठिनाइयों का ध्यान रखा जाना चाहिये तथा न्यूनतम स्थानान्तरण किया जाना चाहिये। व एक साल में ज्यादा ट्रांसफर नहीं किये जाने चाहिये। पैराग्राफ-535 में निम्न अंकित किया गया है :—

“Policy regarding transfers is a constant source of friction between the banks and the workmen now organized into unions. The cry of victimization of office bearers and activists of trade unions is raised whenever such transfers are mooted. We have found that such allegations are easily made but not so easily substantiated. Transfers are rendered necessary by the exigencies of administration. The proper view to take is that transfers are normal incidents of the working of a bank and they must be left to the discretion of those who guide the policy of the bank and manage its affairs. It is possible that the discretion may be abused and transfers effected on considerations other than the needs of administration. The percentage of transfers as

shown by the figures furnished by some of the banks in the course of arguments leads us to the conclusion that the question of transfer even as it affects only a very small number of persons.”

इस बारे में कुछ निर्देश भी दिये गये जो विशेषतौर से संगठन के सक्रिय सदस्य या ओफिस बीयरर इत्यादी के लिए हैं जिन्हें भी स्थानान्तरण प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

प्रार्थी के आवेदन से ही स्पष्ट है तथा विपक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी ने हैड-क्लर्क मुमैरपुर हेतु अपनी सहमति दी थी जो प्रार्थी ने वापस ले ली जिसका पत्र 30-6-92 को उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया। अतः यह कहा जा सकता है कि अब इस संबंध में केवल मात्र परिपत्रों व दिशा निर्देशों पर ही देखा जाना है।

दिनांक 7-6-91 के परिपत्र के अनुसार परिपत्र में उल्लेखित दस स्थान के हैड-क्लर्क की नियुक्तियां की जानी थीं जिन स्थानों में मुमैरपुर भी एक है तथा दस नियुक्ति के लिए इसी परिपत्र के पैरा-6 के अनुसार कर्मचारियों से सहमति लेकर के प्रेषित की जानी थी। परिपत्र के पैरा-5 में बताया गया है कि योग्य कर्मचारी उस हेतु अपनी सहमति दे सकते हैं जिस सहमति में प्रिफेन्स के अनुसार एक से अधिक स्थान अंकित किये गये हैं तथा सहमति निश्चित स्थान के लिए भी हो सकती है। यह भी उल्लेख किया गया है कि “Once an employee gives his consent, he will not be permitted subsequently to withdraw the same.”

इस तरह प्रार्थी को अधिक लाभ के जिस पद पर स्थानान्तरित किया गया उस पद के लिए मांगी गई सहमति में स्पष्ट अंकित कर दिया गया था कि एक बार प्रस्तुत की गई सहमति वापस नहीं ली जा सकती। यही पर यह उल्लेखनीय है कि यह परिपत्र जून 1991 का है तथा पदोन्नति पर अस्मात्, 1992 में रिलीज करना बताया जाता है तथा इस परिपत्र के लगभग 13-14 महीने बाद में पदोन्नतियां व नियुक्तियां की गईं। यह स्पष्ट है कि इस तरह की सहमति इत्यादि लेने के बाद में पदोन्नति हेतु विभागीय कार्यवाही में भी पर्याप्त समय लगता है। अतः प्रारंभिक स्तर पर ही यह कहा जा सकता है कि एक बार सहमति देने के बाद में सहमति वापस यदि ली जाती है, जिसका कि कोई विशेष कारण नहीं हो तो विभाग को काफी परेशानी होगी—पद रिक्त रह सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कार्य में गम्भीर व्यवधान भी हो सकते हैं तथा यदि कोई पदोन्नति नहीं लेना चाहे तो अन्य जो कि पदोन्नति का अधिकारी है, को पदोन्नति में विलम्ब हो सकता है।

दिनांक 22-10-1990 का परिपत्र स्थानान्तरण के लिए एक सामान्य परिपत्र है तथा इसके साथ में भी परिशिष्ट-के पैरा-6 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि योग्य कर्मचारियों से सहमति मांगी जायेगी तथा एक बार सहमति देने के बाद में कर्मचारी उस सहमति को वापस

नहीं ले सकेगा। 29-6-92 का परिपत्र विशेष भत्ते वाले पदों पर नियुक्त के लिए है। यह इसी तरह के पद पर नियुक्ति का मामला है इस परिपत्र में ऐसे पद पर नहीं लिये जाने पर "Debarment Period" का उल्लेख है तथा "बी" श्रेणी में बताया है कि जो विशेष भत्तों वाले पदों पर जाने हेतु सहमति नहीं देते हैं उनको उसी तरह के या समकक्ष पदों पर दो वर्ष के लिए नहीं किया जा सकता। यहां यह उल्लेख कर देना उचित है कि अधिक लाभ वाले पदों पर न जाने पर दो वर्ष का प्रतिबन्ध है परन्तु इस पत्र से किसी तरह से यह निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है कि एक बार सहमति देने पर तथा बाद में वह भी लगभग एक वर्ष बाद में उस सहमति को वापस लिया जा सकता है। प्रतिनिधि प्रार्थी ने तर्क दिया है कि सहमति कभी भी वापस ली जा सकती है तथा उस परिस्थिति में दो वर्ष के लिए प्रतिबन्ध होगा—तर्क दिया गया कि प्रतिबन्ध होने का अर्थ ही नहीं है कि सहमती कभी भी वापस ली जा सकती है। न्यायालय की राय में यह तर्क नहीं माना जा सकता। 29-6-92 के इस परिपत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो मना कर दिया है या जाने में असमर्थ है वह दो वर्ष तक ऐसा नहीं कर सकेगा। इसका अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि सहमति देकर वापस लेने पर यह प्रतिबन्ध लागू होगा। यदि प्रार्थी के द्वारा दिये गये तर्क को मान लिया जावे तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सहमती दे सकेंगे तथा वास्तव में आदेश हो जाने पर इन्कार कर देंगे जब दो वर्ष का यह प्रतिबन्ध होगा। उस परिस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था में अच्छी-खासी परेशानी व अवरोध उत्पन्न हो जायेंगे।

प्रार्थी की ओर से अन्य कोई भी दस्तावेज या नियम प्रस्तुत नहीं हुए जिससे यह प्रतीत हो कि प्रार्थी द्वारा एक बार सहमति दे देने पर वापस लेने का अधिकार हो। प्रार्थी ने बताया है कि 29-6-92 के परिपत्र के अनुसार उसे सहमति वापस लेने का अधिकार था। इस परिपत्र का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है इसका अर्थ किसी तरह से यह नहीं लिया जा सकता।

प्रार्थी द्वारा जो सहमती दी गई वह स्थान विशेष अर्थात् सुमेरपुर के लिए दी गई, जून, जुलाई 1991 में दी गई तथा 30-6-92 को वापस ली गई अर्थात् एक साल भर बाद वापस ले ली गई जबकि पदोन्नति के संबंध में काफी कार्यवाही हो चुकी थी तथा बाद में पदोन्नति की गई। प्रारम्भ में ही यह अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में बताया गया है व आदेश-निर्देश दिये गये हैं कि एक बार सहमति देने के बाद वापस नहीं ली जा सकेगी। इस तरह प्रार्थी द्वारा हेड-क्वैटियर (प्रधान निषिक्त) के पद हेतु दी गई सहमति जून 1992 में वापस लेना उचित नहीं है। सहमति वापस लेने का कोई प्रभाव भी नहीं हो सकता, प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता।

प्रार्थी का स्थानान्तरण मार्च 1997 में सुरणा भाकट पाली शाखा में कर दिया गया जहां से जाने के लिए बी

गई सहमती प्रार्थी ने वापस ले ली थी अतः अब इस विवाद का कोई महत्व भी नहीं रह गया है। प्रार्थी विशेष लाभ वाले पद पर सुरणा भाकट शाखा पाली में स्थापित हुआ, इस आधार पर भी प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता तदनुसार यह विवाद अधि-निर्णित किये जाने योग्य है।

#### अधिनिर्णय

श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की विज्ञापित सं 12012/81/95 के अन्तर्गत प्रेषित विवाद इस तरह से अधिनिर्णित किया जाता है कि प्रार्थी जितेन्द्र कुमार के हेड-क्वैटियर (प्रधान निषिक्त) के पद हेतु दो गई सहमति 4-8-1992 वापस लेने की वैधता पर अप्रार्थी रिजनल मनेजर—II, स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर जोनल ओफिस, जोधपुर द्वारा विचार नहीं करना पूर्णतया उचित एवं वैधानिक है। प्रार्थी अप्रार्थी नियोजक से कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस अधिनिर्णय को प्रकाशनार्थ श्रम मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया जावे।

यह अधिनिर्णय ग्राज दिनांक 06-1-1999 को न्यायालय में हस्ताक्षर कर गुनाया गया।

चांदमल टोन्सा, न्यायधीश

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1999

का.आ. 881.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्धन के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-2-1999 को प्राप्त हुआ था।

[नं. एल-12012/240/97-आई.आर. (बी.-I)]

मनालन, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th February, 1999

S.O. 881.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner & Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 23-2-1999.

[No. L-12012/240/97-IR(B-I)]

SANATAN, Desk Officer

## अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,  
जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्री चांदमल तोतला, आर.  
एच. जे. एम.

ओ. वि. (केन्द्रीय) सं. :—13/1997

मंगलसिंह पुत्र श्री गणेशा जी ग्राम पोस्ट कानन्दरी  
नहसील एवं जिला सिरोही ।

... प्रार्थी

बनाम

1. जनरल मनेजर, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड  
जयपुर, जयपुर ।

2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड  
जयपुर जिला सिरोही ।

... अप्रार्थीगण

उपस्थिति :

(1) प्रार्थी की ओर से श्री विनोद पुरोहित  
प्रतिनिधि उप.

(2) अप्रार्थीगण की ओर से श्री जगदीश व्यास  
प्रतिनिधि उप.

अधिनिर्णय

दिनांक 01 फरवरी, 1999

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति सं. 240/97  
दिनांक 30-7-97 से श्रमिक कर्मचारी तथा उसके नियोजक  
के मध्य उत्पन्न हुआ निम्नलिखित विवाद अधिनिर्णय हेतु  
इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रेषित किया गया तथा  
दिनांक 15-11-97 को नियमित ओ. विवाद सं. 13/97  
पंजीकृत हुआ :—

"Whether the action of the management of  
State Bank of Bikaner' Jaipur for termi-  
nating the services of Shri Mangal Singh  
is legal and justified. If not to what re-  
lief the workman is entitled?"

उपरोक्तानुसार विवाद प्रार्थी श्री मंगलसिंह की सेवा-  
सूचित की वैधानिकता व औचित्यता से संबंधित है तथा  
प्रार्थी ने उसकी कथित सेवामुक्ति को अवैधानिक व अनुचित  
बताते हुए प्रस्तुत किये गये अपने मांग पत्र में बताया  
है कि वह विपक्षी राजस्थान स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड  
जयपुर के अधीन पीओन काम करण के पद पर मार्च 1972  
से दिसम्बर 1973 की अवधि में नियोजित रहा अतः  
विपक्षी उसका नियोजक तथा प्रार्थी श्रमिक है तथा इस  
अवधि में प्रार्थी ने विपक्षी अधिकारियों के मौखिक आदेशों  
के अनुसार लम्बी अवधि तक सेवाएं करी तथा 26-12-73  
के बाद उसकी सेवाएं अधिनियम के प्रावधानों का

उल्लंघन करने हुए समाप्त कर दी । आवेदन मांग-पत्र  
के अनुसार प्रार्थी 26-3-72 को नियोजित हुआ तथा  
26-12-73 तक भिन्न-भिन्न अवधि में कुल 122 दिन कार्य  
किया तथा 7-12-73 व 26-12-73 को प्रार्थी के संबंध  
में आदेश भी जारी किये गये जो प्रदर्श-1 व 2 हैं ।  
प्रार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद का कार्य करता था  
जैसे कि सफाई करना, पानी भरना, पानी पिलाना, स्टेशनरी  
निकालना, जमा कराना, बाऊचर मिलाई करना इत्यादि ।  
प्रार्थी की नियुक्ति दैनिक वेतन पर नियमित चपरासी के  
स्पष्ट रिक्त पद के विरुद्ध हुई थी । अधिनियम के प्राव-  
धानों का उल्लंघन करने हुए 26-12-73 के बाद में प्रार्थी  
की सेवा नहीं बढ़ाई जाकर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी  
गई तथा बाद में अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति दे दी गई ।  
आवेदन में यह भी बताया गया है कि विपक्षी बैंक द्वारा भूतपूर्व  
बैंक कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति देने के लिए सूचना  
प्रकाशित करवाई तथा समाचार-पत्र में भी प्रकाशित हुई  
जिस पर प्रार्थी ने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु  
रिक्त पद उपलब्ध होते हुए भी प्रार्थी को नियुक्त नहीं किया  
गया तथा भूतपूर्व कर्मचारियों को नियोजित करने के संबंध  
में विपक्षी बैंक द्वारा कोई परिवर्तन समय-समय पर जारी  
किये गये तथा प्रार्थी ने अपने आवेदन भी निश्चित समय  
अवधि में प्रस्तुत किये जो आवेदन विज्ञप्तियों तथा प्रार्थी  
के प्रतिवेदन प्रदर्श-3 से प्रदर्श-12 हैं । आवेदन में बताया  
गया है कि प्रार्थी की सेवा समाप्त करने समय अधिनियम  
की धारा 25-एफ व अन्य प्रावधानों की पालना नहीं की  
गई तथा अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम 77  
के अनुसार वरिष्ठता सूची भी नहीं रखी गई न हो  
प्रकाशित की गई तथा प्रार्थी की सेवा समाप्ति के बाद में भी  
अन्य कई व्यक्तियों को नियोजित किया गया । सम्माननीय  
उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका संख्या 532/87  
श्रीमती संतोष कुमारी व अन्य बनाम पंजाब राज्य  
में दिनांक 2-5-88 के निर्णय का उल्लेख करते हुए बताया  
गया कि जब नियमित पद उपलब्ध था तो 89 दिन की  
ही नियुक्ति की गई इसका कोई उत्तर नहीं है तथा इस  
रिट याचिका में संबंधित प्रार्थी की सेवाएं समाप्त नहीं  
करने के निर्देश दिये गये थे अतः प्रार्थी भी निर्णय के अनुसार  
स्थाई या अस्थायी नियमित पद पर नियुक्ति का अधिकारी  
है । आवेदन के अनुसार प्रार्थी ने नियोजित हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किये गये जिनके उत्तर में प्रार्थी को 29-12-90  
को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया  
गया तथा प्रार्थी साक्षात्कार में उपस्थित भी हुआ परन्तु  
फिर भी उसे कोई प्रनोप नहीं दिया गया अतः सज्जन  
उसे न्याय प्राप्त के लिए विपक्षी को नोटिस भी देना  
पड़ा जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श-15 है । सांग-पत्र ने बताया  
गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एच  
के प्रावधान बाध्यकारी हैं तथा ये कर्मचारी जिन्होंने कि  
240 दिन की सेवा विभाग में पूर्ण नहीं की है भी प्राथ-  
मिकता के आधार पर नियोजित होने के अधिकारी हैं ।

जिन प्रावधानों की पालना नहीं की गई है तथा अन्वेषकों को नियोजन करने से पूर्व प्रार्थी को विधिवत अनुवर्णन रूप में देय नियोजन का प्रस्ताव भी नहीं दिया गया तथा प्रार्थी के आवेदनों पर उसे आश्वासन के अतिरिक्त और कोई राहत नहीं दी गई। आवेदन में बताया गया है कि प्रार्थी ने इस हेतु सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 755/87 (तुटी) मंगलसिंह बनाम एस. बी.बी. जे. दायर करी जिसमें सम्माननीय उच्च न्यायालय ने 25-4-97 के आदेश से प्रकरण को संबंधित श्रम न्यायालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश जारी किये। आवेदन में बताया गया है कि सम्माननीय उच्चतम न्यायालय के संतोष कुमारी बनाम पंजाब राज्य के निर्णय के अनुसार प्रार्थी नियुक्ति का अधिकारी है तथा इस तरह के मामलों में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कम लेबर कोर्ट कानपुर ने भी 29-1-86 के निर्णय से भूतपूर्व कर्मचारी को सेवा में लेने तथा बकाया वेतन के भुगतान इत्यादी के निर्देश दिये गये हैं। यह भी बताया गया है कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति श्रमिक विरोधी कार्यवाही है तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई है। सम्माननीय राज. उच्च न्यायालय की डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2903/88 रामचन्द्र यादव व अन्य बनाम आर.एस.आर.टी.सी. दिनांक निर्णय 9-5-89 तथा रिट याचिका संख्या 2732/91 ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स बनाम प्रेसाईडिंग ऑफिसर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल व अन्य का उल्लेख करते हुए बताया गया कि प्रार्थी नियोजक के यहां नियुक्त किये गये अन्य कर्मचारियों की तिथि से पुनः नियुक्ति तथा तमाम वेतन व अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी की 26-12-73 से की गई सेवा-मुक्ति को शून्य एवं अवैधानिक घोषित करने हुए विपक्षी को निर्देश दिया जावे कि रिक्त पद पर नियोजन के लिए प्रार्थी के मामले पर विचार कर प्रार्थी को पुनः नियोजित किया जावे तथा विपक्षी के यहां नियोजित किये गये अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से तमाम वेतन व अन्य लाभ प्रार्थी को प्रदान किये जावे।

विपक्षी ने अपने उत्तर में प्रकट किया है कि प्रार्थी ने 26-3-72 से 26-12-73 तक की अवधि में आवेदन में बताये अनुसार कार्य किया परन्तु कार्य पूर्णतया अस्थायी तौर पर "अंशकालीन दैनिक वेतन भोगी" के रूप में किया। उत्तर में इससे इन्कार किया है कि प्रार्थी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद के विरुद्ध की गई थी-इससे इन्कार किया है कि प्रार्थी के स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त कर दिया गया तथा बताया गया कि इस कालन्दरी शाखा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद ही सर्वप्रथम 19-1-77 से सुजित हुआ है जिस पद पर भर्ती प्रक्रिया अनुसार श्री सरपाराम को नियुक्त किया गया। विपक्षी बैंक द्वारा जारी की गई नियोजन की अधिसूचना के उत्तर में प्रकट किया गया है कि विपक्षी प्रदर्श-3 लिपिक वर्ग हेतु थी तथा प्रदर्श-3 व 4 के अनुसरण में प्रार्थी ने कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं

किया तथा प्रदर्श-5 के अनुसरण में प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु इस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट था कि जिन कर्मचारियों ने 1-1-82 के बाद में 90 दिन या अधिक कार्य किया वे ही आवेदन कर सकते हैं तथा प्रार्थी ने 1-1-82 के बाद में कार्य ही नहीं किया था अतः वह पात्रता नहीं रखता था। उत्तर में यह भी बताया गया है कि प्रार्थी को कभी किसी के द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया तथा प्रार्थी ने कनिष्ठ व्यक्तियों को भी प्रार्थी के कथनानुसार नियुक्त नहीं किया गया। उत्तर में यह भी बताया गया है कि विपक्षी के अन्य परिपत्रों के अनुसार प्रार्थी आवश्यक न्यूनतम मानदण्ड योग्यता नहीं रखता था तथा 24-10-90 की विज्ञप्ति के अनुसरण में प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1-1-82 से बाद में नियुक्त व कार्य किये कर्मचारी ही इस हेतु पात्र थे अतः प्रार्थी को नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी तथा प्रार्थी को साक्षात्कार हेतु अवश्य आमंत्रित किया गया था परन्तु उसे नियुक्त नहीं किया जा सका। आवेदन में वर्णित न्याय दृष्टान्त के संबंध में उल्लेख किया गया कि उन सभी मामलों के तथ्य भिन्न थे जो इस मामले में लागू नहीं होते। यह भी बताया गया कि नियमों के अनुसार अस्थायी तौर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को समय-समय पर प्राथमिकता के आधार पर नियोजन प्रदान किया गया तथा प्रार्थी अब बैंक में पुनः नियोजन व/या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उत्तर में यह भी बताया गया कि प्रार्थी नियुक्ति हेतु अधिकतम आय पार कर चुका था तथा लास्ट कम फर्न्ट गो के सिद्धान्त का भी उल्लंघन नहीं किया गया। व्यय सहित आवेदन अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से स्वयं प्रार्थी श्री मंगलसिंह का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदन के अनुसार बताते हुए प्रकट किया है कि उसकी सेवा समाप्ति विधिक व श्रम कानून के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए की गई अतः वह पुनर्नियुक्ति तथा सम्पूर्ण अवधि के नगम लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी की ओर से श्री रफीक आजम शाखा प्रबन्धक कालन्दरी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उत्तर के अनुसार बताया गया। शपथ-गृहताओं से प्रतिपरीक्षण हुआ। प्रार्थी के आवेदन पर विपक्षी को विभिन्न दस्तावेजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये प्रार्थी की ओर से उसके द्वारा दिये गये विभिन्न आवेदनों विपक्षी के परिपत्रों की प्रतिलिपियां प्रदर्श-1 से 15 प्रस्तुत की गई एवं विपक्षी द्वारा किसी भी स्तर पर कभी भी इन्हें चुनौती नहीं दी गई प्रतीत होती है तथा उत्तर में भी इनमें से कुछ का उल्लेख है अतः दस्तावेज प्रदर्श-1 से 15 को साक्ष्य व प्रकरण के निस्तारण के लिए सामग्री के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

अभ्यर्थक के प्रतिनिधिगण के तर्क सुने गये। पताचली का अवलोकन किया गया।



प्रकरण के तथ्यों व तर्कों को देखते हुए सर्वप्रथम प्रार्थी के विधोचल के समय तथा कार्यदिवसों पर विचार करना उपर्युक्त है। प्रार्थी के शपथ-पत्र तथा आवेदन के अनुसार प्रार्थी ने 26-3-73 से 26-12-73 तक कार्य किया। विपक्षी ने अपने उत्तर में प्रार्थी द्वारा इस अवधि में कार्य करना स्वीकार किया है। इस तरह आवेदन में अंकित अवधि में प्रार्थी द्वारा कार्य करना प्रमाणित है। यह अवधि आवेदन व शपथ-पत्र में उपरोक्त तरह से दर्शाई की गई है तथा प्रमाणित होता है कि प्रार्थी ने 26-3-72 से 26-12-73 की अवधि में कुल 122 दिवस कार्य किया। स्वयं प्रार्थी के अनुसार उसकी सेवामुक्ति 26-12-73 को की गई। उपरोक्त विवरण के अनुसार 26-12-73 से पहले के ठीक 12 माह में 27-12-72 से होते हैं 27-12-72 से 26-12-73 में प्रार्थी के कार्यदिवस कुल 34 रहे हैं। यहां पर यह उल्लेख करना उचित है कि 26-3-72 से 26-12-73 तक प्रार्थी की कार्य अवधि रही है इसमें से किसी भी समय के कोई भी बारह महीने किये जाके तब भी प्रार्थी के कार्यदिवस 240 या अधिक नहीं होते—26-3-72 से 25-3-73 की अवधि मानी जाके तब भी यह कार्यदिवस 102 ही रह जाते हैं। इस तरह प्रार्थी ने कभी भी किसी भी वर्ष में 240 या अधिक दिवस कार्य नहीं किया।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी का अन्तिम कार्य-दिवस 26-12-73 रहा है तथा आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को यथावत मान लिया जाये तब भी प्रार्थी ने विपक्षी को न्यय प्राप्ति हेतु अधिवक्ता के माध्यम से सर्वप्रथम नोटिस 4-1-97 को दिया तथा इस समय में सर्वप्रथम वैधानिक कार्यवाही सम्मानीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 755/97 प्रस्तुत करके की अर्थात् सन् 1997 में की अर्थात् कथित सेवामुक्ति के 24 वर्षों बाद में की गई इस अत्यधिक देरी का कोई भी मानने योग्य कारण नहीं बनाया गया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि सामान्य क्रम में सम्पूर्ण सेवा-काल लगभग 35 वर्ष का होता है जिसमें से इस तरह लग-भग 25 साल प्रार्थी ने बिना कोई कार्यवाही किये निकाल लिये हैं। प्रार्थी की ओर से आवेदन में जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है उनमें से सभी अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रार्थी की ओर से उसके तर्कों के समर्थन में आर.एल.आर. 1989 (1) 637 रामचन्द्र यादव बनाम आर.एल.आर. टी.सी.-राज. न्यायालय, आर.एल.आर. 1991 (2) 159 ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स बनाम प्रेमाडिडिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट इण्डस्ट्रीयल व आयर राज. उच्च न्यायालय प्रस्तुत की गई जिन व्यवस्थाओं का आदरपूर्वक अवलोकन कर प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के मन्दर्भ में विचार किया गया। रामचन्द्र यादव वाले मामले में पक्ष परिवहन निगम द्वारा वर्ष 86 व 87 में दैनिक वेतन पर नियुक्ति दी गई जिसकी सेवाएं सितम्बर 1987 में समाप्त कर दी गई तथा कुछ समय बाद में ही कनिष्ठ को पुनः नियोजित कर दिया गया जब कि उन्हें पुनः सेवा में आने का प्रस्ताव नहीं दिया गया तो ऐसे कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। यहां यह उल्लेखनीय है कि अन्य कनिष्ठों को नियोजन किये

जाने के तुरन्त बाद में प्रार्थी ने वैधानिक कार्यवाही करते हुए याचिका प्रस्तुत की। ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स वाले उपरोक्त मामले में प्रार्थी ने 79 दिवस तक वर्ष 86 में कार्य किया तथा सेवामुक्ति के विरुद्ध विलम्ब किये बिना कार्यवाही की गई तथा 25-जी व 25-एच के उल्लंघन पर पुनः स्थापन के निर्देश दिये गये।

प्रार्थी ने अपने शपथ-पत्र में आवेदन में अंकितानुसार बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में प्रकट किया है कि बैंक में उस समय चपरासी का कोई पद नहीं था तथा बैंक में कर्मचारी एक मैनेजर तथा एक प्रार्थी स्वयं था। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि इस शाखा में उस समय केवल मात्र एक नियमित कर्मचारी शाखा प्रबंधक था अतः यह कहना ठीक नहीं प्रतीत होता कि प्रार्थी की नियुक्ति किसी नियमित कर्मचारी के विरुद्ध की गई थी या प्रार्थी ने किसी नियमित कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले कार्य के विरुद्ध कार्य किया। प्रार्थी ने यह भी कहा है कि उसे सन् 73 में नौकरी से निकाला गया उसके बाद वह हर माह रजिस्ट्री से कागज भेजता रहा यह मानने योग्य प्रतीत नहीं होता कि सन् 73 से याचिका प्रस्तुत करने तक 25 वर्षों तक इस तरह से पंजीकृत डाक से प्रतिमाह पत्र भेजता रहा यदि प्रतिमाह पत्र भेजे जाते तो प्रार्थी उपर्युक्त समय में उपरोक्त सम्बन्ध में कार्य-वाही भी प्रारंभ कर सकता था। यहां यह उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्री की कोई भी पोस्टल रसीद इत्यादि प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रार्थी ने इससे अनभिज्ञता जाहिर करी है कि उन्हीं लोगों को नियुक्त किया गया जिन्होंने कि 1-1-82 के बाद में कार्य किया है।

विपक्षी के शाखा प्रबंधक ने अपने शपथ-पत्र में उत्तर के अनुसार बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में प्रकट किया है कि प्रार्थी ने मार्च 73 से 73 तक पार्लेटाइस पीयोन-कम-फार्मिंग का कार्य किया तथा प्रार्थी की सेवाएं 26-12-73 को समाप्त हो गई। शाखा प्रबंधक ने यह भी बताया है कि यह एक ही कर्मचारी की शाखा थी तथा कोई पद नहीं था अतः सेवाएं समाप्त हो गई तथा प्रार्थी को मुख्यालय से अनुमति लेकर सफाई करने, पानी भरने इत्यादी के कार्य पर नियुक्त किया गया बाउचर पिलाई, बैंक बन्द करने का कार्य मैनेजर ही करता है। विपक्षी के इस गवाह ने स्वीकार किया है कि कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई तथा वर्ष 77 में इस शाखा में सरुगराम को नियुक्ति दी गई जिसके पहले प्रार्थी को नियुक्ति हेतु कोई सूचना नहीं दी गई। यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए साक्षात्कार पत्र भेजा गया था तथा नियोजन के लिए विज्ञापित जारी हुई थी।

प्रतिनिधि प्रार्थी ने नर्क दिया है कि सन् 1973 में सरुगराम को नियुक्त किया गया उसके पहले प्रार्थी को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। विपक्षी की ओर से बताया गया कि यह नियमित भर्ती प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति थी अतः प्रस्ताव भेजे जाने का प्रश्न ही नहीं था यहां पर यह उल्लेखनीय है कि सन् 1977 के बाद में भी कम से कम 20 वर्ष बाद में प्रार्थी ने कार्यवाही शुरू करी है अतः यदि प्रार्थी को

सन् 77 में इस नियुक्ति से कोई अधिकार उत्पन्न हुए तब भी वह सब अधिकार समय के साथ पूरी तरह से समाप्त, गौण या अत्यधिक क्षीण हो गये थे। इस तर्क को भी नहीं नकारा जा सकता कि की गई नियमित भर्ती चयन प्रक्रिया अनुसार हुई थी, अतः प्रार्थी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते।

प्रार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि सन् 1991 की विज्ञप्ति के अनुसरण में केवल 1-1-82 के बाद में नियुक्त कर्मचारी को ही नियुक्त किया जाना गलत है तथा भारत-सरकार या विपक्षी नियोजक द्वारा लगाई गई यह शर्त कि 1-1-82 के बाद में जिन्होंने कार्य किया है वे ही पात्र हैं विधिवत नहीं है। प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि यह "कट ऑफ डेट" प्रार्थी पर बाध्यकारी नहीं हो सकती तथा प्रार्थी को नियोजन हेतु कन्सीडर किया जाना चाहिये था। विपक्षी की ओर से इसका विखण्डन करते हुए बताया कि प्रार्थी ने उसके लिए नियोजन के जो अवसर थे उसके अनुसरण में आवेदन प्रस्तुत नहीं किये तथा अनिश्चित काल तक पूर्व में 10-20 वर्षों पहले कार्यरत रहे कर्मचारियों को अवसर नहीं दिया जा सकता।

उपरोक्त तर्कों पर विचार किया गया। न्यायालय की राय में इस प्रश्न पर गहराई या विस्तार से विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। प्रार्थी सन् 72 में ही नियोजित हुआ था तथा स्वाभाविक तौर से उस समय उसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये तथा सन् 91-92 में उसकी आयु कम से कम 37-38 वर्ष हो गई अतः निर्धारित आयु सीमा इत्यादि को देखते हुए भी कोई अवसर दिये जाने का औचित्य नहीं था। यहाँ पर यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जिन मामलों में विधिक तौर से कोई समय अवधि निर्धारित नहीं हो उनमें भी प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं है कि अनिश्चित काल या बहुत अधिक लम्बे समय के बाद भी अनुतोष हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सके। बिना कारण के किये जा रहे या करने वाले प्रत्येक विलम्ब के परिणाम-स्वरूप यदि कोई अधिकार हैं तो वे समाप्त होते जाते हैं या क्षीण होते जाते हैं। प्रार्थी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने बैंक में चपरासी के लिए एक ही बार आवेदन प्रस्तुत किया था। इस तरह प्रार्थी ने कुल मिलाकर एक ही बार आवेदन दिया है जिसके फलस्वरूप उसे वर्ष 1990 में साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। इस तरह से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी ने इससे पहले जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी ने 9-6-87, 15-7-88 के उसके कथित आवेदनों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की हैं परन्तु प्रतिलिपि प्रदर्श 6, 7 व 9 प्रस्तुत करने के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि उसने संबंधित विधिकारियों को यह आवेदन प्रस्तुत किये थे। दिनांक 6-11-85 की विज्ञप्ति प्रदर्श-10 के अनुसार 1-1-76 के बाद में जो व्यक्ति कार्यरत रहे थे उनमें भी नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये तथा 23-4-87 के परिपत्र प्रवर्ग 8 के अनुसार इस तरह के कर्मचारियों को नियोजन हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे व 22-4-87, 17-9-89 के पत्रों से भी इस तरह के

निर्देश दिये गये। इन परिपत्रों में से कुछ 1-7-75 के बाद में कार्यरत कर्मचारियों को पात्र बताया गया ऐसी कोई भी मानने योग्य माध्य व तथ्य नहीं है कि प्रार्थी ने 1990 में पहले कोई आवेदन दिया हो। प्रार्थी की ओर से सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका संतोष कुमारी बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के 2-5-88 के निर्णय की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जो प्रदर्श-13 है। इस निर्णय में पंजाब राज्य को निर्देश दिये कि जब नियमित पद हो तो सेवाएं केवल इस आधार पर समाप्त नहीं की जाएं कि उन्हें नियुक्ति केवल 89 दिन के लिए ही दी गई थी। सम्माननीय न्यायालय के इस निर्णय से प्रार्थी को किसी तरह से लाभ मिलता हो यह नहीं बताया गया अतः प्रार्थी इस आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता।

प्रार्थी ने उसकी सेवा समाप्ति के 25 वर्ष बाद में यह कार्यवाही प्रारम्भ की है। 25 वर्ष अत्यधिक लम्बा समय केवल उपर्युक्त मामलों में केवल मात्र देरी के आधार पर अनुतोष प्रदान किये जाने से इंकार किया जा सकता है। इस बार में सम्माननीय उच्चतम न्यायालय व सम्माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा कई व्यवस्थाओं में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं जिन्हें उल्लेख करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। 25 वर्ष की अत्यधिक देरी प्रार्थी की कार्य अवधि के लिए उल्लेख किया जा चुका है। प्रार्थी ने नियोजन हेतु परिपत्र व विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन ही नहीं किया—जब आवेदन किया तब उसकी सेवा समाप्त किये हुए 17 वर्ष हो चुके थे तथा विज्ञप्ति के अनुसार वह आवश्यक योग्यता भी नहीं रखता था। अतः तमाम तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता। तदनुसार यह विवाद अधिनिर्णित किये जाने योग्य है कि प्रार्थी अब कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी की सेवा समाप्ति की गई तब उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त नहीं किया गया। प्रार्थी की सेवा भी गत एक वर्ष में कुल 34 दिन ही थी अतः 26-12-73 से की गई सेवा समाप्ति अवैधानिक या अनुचित नहीं मानी जा सकती।

#### अधिनिर्णय

श्रम मंत्रालय भारत सरकार की विज्ञप्ति सं. 240/97 के अन्तर्गत प्रेषित विवाद इस तरह से अधिनिर्णित किया जाता है कि शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ़ कीकानेर एण्ड जयपुर कालम्बरी-सिरोही द्वारा प्रार्थी भंगल सिंह पुत्र गणेश को सेवा से पृथक् करना अवैधानिक व अनुचित नहीं है। प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस अधिनिर्णय को प्रकाशनार्थ श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जावे।

यह अधिनिर्णय आज दिनांक 01 फरवरी 1999 को न्यायालय में हस्ताक्षर कर मूनाया गया।

चंद्रमन नाजक, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

अधिनिर्णय

का.आ. 882 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बीकानेर, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12011/51/95-आई.आर. (बी.-I)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 882.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bikaner as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner & Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 4-3-1999.

[No. I-12011/51/95-IR(B-I)]

SANATAN, Desk Officer.

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण, बीकानेर

केन्द्रीय औद्योगिक विवाद प्रसंग सं. 2 सन् 1997:

श्री आर.पी. पुरोहित माफत-

अखिल भारतीय एस.बी.बी.जे. कर्मचारी संघ, वालहरि निवास,

प्रांत दूत के सामने चाँतीना कृपा, बीकानेर।

—प्रार्थी/श्रमिक

बनाम

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्रथम), स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, अंचल कार्यालय, पब्लिक पार्क, बीकानेर (राज.)

2. उप महा-प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, अंचल कार्यालय, पब्लिक पार्क, बीकानेर (राज.)

—अप्रार्थीगण/नियोजक

प्रसंग अन्तर्गत धारा 10(1)(घ), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

न्यायाधीश—श्री गुलाम हुसैन, आर.एच.जे.एस.

उपस्थिति :—

1. श्री श्रीनारायण पुरोहित, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण के लिये

2. श्रमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं;

दिनांक: 1 फरवरी, 1999

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947" जिसे आगे चलकर केवल "अधिनियम" कहा गया है की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 12011/51/95 दिनांक 4-3-97 के द्वारा प्रेषित इस प्रसंग के अन्तर्गत निम्न विवाद अधिनिर्णयार्थ इस अधिकरण में भेजा है :

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur, Bikaner is justified in transferring Shri R. P. Purohit Clerk Typist to Napasur Branch Distt. Bikaner on his selection as special resistan- tant while keeping junior workman Sh. B. D. Kothari at Hospital Road Branch of S.B.B.J., Bikaner in violation of transfer policy of award staff issued vide circular Number 104/87 dated 24-10-83? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. प्रसंग प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। श्रमिक राजेन्द्र प्रसाद की ओर से यूनियन के सचिव द्वारा स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश किया गया। इसकी नकल अप्रार्थी बैंक को दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया। पक्षावली श्रमिक की साक्ष्य के लिये नियत है। आज दिनांक 1-2-99 को जब यह प्रकरण हमारे समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हुआ तो श्रमिक अथवा उसकी ओर से कोई भी प्रति- निधि बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए हैं जबकि अप्रार्थी नियोजक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक की यूनियन अब इस विवाद को आगे चलाने में इच्छुक नहीं रही है अतः पक्षकारों के मध्य "कोई विवाद नहीं" का पंचाट पारित किया जाना उचित एवम् न्यायसंगत है।

3. अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित इस विवाद में पक्षकारों के मध्य "कोई विवाद नहीं" का यह पंचाट पारित किया जाता है जो अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

4. आज्ञा आज दिनांक 1-2-99 को सर इजलास लिखाई एवं मुनाई जाकर हस्ताक्षरित की गयी।

गुलाम हुसैन, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

का.आ. 883.- -औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर, बंगलौर के प्रबंधतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/51/92-आई.आर. (बी-III/बी-I)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 883.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bijapur Gramin Bank and their workman, which was received by the Central Government on 4-3-1999.

[No. L-12012/51/92-IR (B III/B.I.)]

SANATAN, Desk Officer.

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT BANGALORE

Dated 15th February 1999

PRESENT :

JUSTICE R. RAMAKRISHNA  
PRESIDING OFFICER.

C.R. NO. 61/92

#### I PARTY

Shri Mohammed Yusuf D. Naikodi,  
Ex-Messenger-cum-Sweeper,  
Near Gurjikatti Oni,  
Basavana Bagewadi 585203,  
Bijapur District.

#### II PARTY

The Chairman  
Bijapur Gramin Bank,  
Head Office,  
Bijapur-586101.

#### AWARD

1. Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2A of the section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 has referred this dispute vide Order No. L-12012/51/92-IR.B.III dated 20-7-92 for adjudication on the following schedule.

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bijapur Gramin Bank, Bijapur in terminating the services of Shri Mohammed Yusuf D. Naikodi, Ex-Messenger-cum-Sweeper is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The case of the first party is that he was appointed as a Messenger-cum-Sweeper in the year 1984. He has continuously worked without any break to the satisfaction of his superiors. On 14-6-91 he was not allowed to attend to his duties. There was no prior notice. His several appeals were not taken into consideration. Thereafter he issued a legal notice and raised a conciliation.

3. The main contention is that he has worked 5 to 6 years and a certificate was also issued to this effect. Therefore his termination amounts to retrenchment. Since the mandatory provisions of Sec. 25F of ID Act was not complied the order of termination is a nullity and he is entitled for reinstatement, backwages and other consequential benefits.

4. The second party has resisted the claim statement and mainly contended that the first party was not appointed as messenger-cum-sweeper nor he has worked continuously 4 to 6 years as contended by him. They have admitted that the Branch Manager at Basavana Bagewadi engaged him to sweep the bank premises casually in the absence of the regular employee and he was paid daily wages. He has worked only 30 days during the period 17th December, 1988 to 4th September, 1991. The second party further denied non-compliance of Section 25F, as the same does not arise in the facts of the case.

5. Since it is a case alleged by the first party and denied by the second party no additional issues are framed. Parties are directed by an order dated 8th August, 1994 to lead the evidence on the points shown in the schedule.

6. The second party examined 2 witnesses and got marked 4 documents, MW-1 B. Visudev who was working as Manager at the relevant time has stated in his evidence that the first party was doing the work of messenger-cum-sweeper whenever the permanent incumbent is on leave. He has further stated that the first party has worked only 30 days as per the statement Ex. M-3. As it regards to certificate Ex. W-1 this witness has stated that though he had no power to issue such certificate, on the behest of the first party he has issued the certificate on humanitarian grounds.

7. Nothing much was elicited in the cross examination and the very same case made out by the first party that one Mr. Banakar was the then manager was denied and according to the second party, no person by such name worked at any point of time under the second party bank.

8. Evidence on MW-2 Panduranga is only to show that as per Staff service regulation the Chairman is the only competent authority and the branch managers are not empowered to issue a certificate like Ex. W-1. He has also made reference to the conditions laid down in staff service regulation, 1993 marked as Ex. W-4.

9. As against this evidence the first party has contended that he was appointed during 1984. He was working from 10.30 A.M. to 5.30 p.m. and the second party was paying the salary of Rs. 2,800 per month. According to him he continued to work till 13th June, 1991. On 14th June, 1991 when he went to the bank he was informed not to attend the work and on his request a certificate Ex. W-1 was given. Thereafter he issued a legal notice and raised a dispute.

10. In the cross examination he has stated that no appointment order was given to him. He has not given any application for appointment nor he asked the management to give appointment letter. He has denied the suggestion that there was no person by name Banakar. He has also admitted that he has no documents to evidence that his salary was Rs. 2,800 per month.

11. On going through both oral and documentary evidence it is crystal clear that the first party has worked only about 30 days as contended in Ex. M-3. Unless he was a permanent employee he will not be allowed to work continuously as stated by the first party. If a salary of Rs. 2,800 is given for him per month that is always in the form of cheques where an account shall be opened in the name of the first party. The staff service regulation Ex. M-4 shows under Chapter 2, the procedure for appointment and termination of service. Any appointment shall be in commensurate with rules prescribed and every such appointment will be in writing and the workman will be put on probationary, whatever may be his grade.

12. Ex. W-1 certificate on which the first party made much of it is only a certificate issued by incompetent person without knowing the consequence. That does not give a right to make out a case of this nature. Ex. W-3 is a certificate issued by Rural Development and Self-Employment Training Institution, Dharwad. This certificate shows that the first party has undergone comprehensive Agriculture and Allied Activities training from the institution. Through this certificate the Director requested the manager of the bank to extend financial assistance for the first party to become a self employed. Therefore the first party can not claim that this is the certificate on it the bank is appointed him.

13. However it is still open to the second party to extend any financial benefit to the first party if he fulfils all the conditions to become a self employed person.

14. In the circumstances the first party has failed to prove that he was a workman as envisaged under the I.D. Act and therefore it is not proved that the second party has terminated his services. In the result I make the following order :

#### ORDER

This reference is rejected.

(Dictated to Stenographer, transcribed by her, corrected and signed by me on 15-2-99.)

JUSTICE R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

का.प्र. 884.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, बंगलूर के प्रबंधन के संवद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, शत्रुता में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलूर से संसद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एम-12012/69/91-आर. बी-III/बी-I]  
मनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 884.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Karnataka Bank Ltd., Bangalore and their workman, which was received by the Central Government on 4-3-1999.

[No. L-12012/69/91-IR B-III/B-I]  
SANATAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated, 15th February, 1999

**PRESENT:**

Justice R. Ramakrishna, Presiding Officer.

C. R. No. 20/1991

C.G.A. 03/1991

**1st Party/Applicant**

Shri D. Basavarajiah,  
S/o K. Doddaiiah,  
Opp. Government College,  
5th Cross, B. H. Road,  
Tumkur-570002.

**2nd Party/Respondent**

The Chairman,  
Karnataka Bank Ltd.,  
P.B. No. 716,  
Bangalore-575003.

#### AWARD

1. C. R. No. 20/91 is a reference made by Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2A of the Section 10 of the I.D. Act, 1947 has referred this dispute vide Order No. L-12012/69/91-IR-B-III dated 8-4-91 for adjudication on the following schedule:

#### SCHEDULE

"Whether the management of Karnataka Bank Ltd. is justified in terminating the services of Shri D. Basavarajiah by way of voluntary retirement, w.e.f. 23-10-90? If not, to what relief he is entitled?"

2. C.G.A. 3/91 is an application filed under Section 33.C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the first party for an Order directing the second party to pay a sum of Rs. 42,699.65 as salary due to the first party for rejected leave period.

3. The first party was appointed as a Clerk during January 1978 and was working at Tumkur branch. He was transferred to Sullia branch of Mangalore District, and was relieved on 28-2-1989. The first party joined Sullia branch on 3-6-1989. After working for one day he availed joining time from 5-6-89 to 10-6-89. He worked for one day on 12-6-89. He again worked for one day on 17-6-89. Therefore he was absent for duty from 13-6-89 to 16-6-89, and from 19-6-89 to 29-8-89. He reported to duty for one day on 29-8-89. These periods were treated as leave by the second party. The first party once again treated remaining absent from 30-8-89 to 3-9-89. Since 3rd and 4th September, 1989 being holidays he reported to duty for a day on 5-9-89, and he then remained absent from 6-9-89 to 10-8-90 except working for 2 days on 25-9-89 and 26-4-90. Therefore he was absent for 333 days and the second party declaring the said absence as unauthorised has not paid any salary for that period.

4. The first party repeated his modus operandi of reporting to duty for a day on 11-8-90 and started remaining absent for 77 days at a stretch from 20-8-90 to 22-10-90. Due to this tendency the second party considered his absence as voluntary retirement after giving a notice or contemplated under Clause V of Bipartite Settlement. But the first party again made a pretence of reporting to the duty on 11-8-90 for one day and then again remained absent from 13-8-90 for more than 30 days. Again a registered notice dated 12-9-90 was issued. Since the notice returned unserved a paper publication was made in 2 leading dailies one in Kannada and another in English i.e. Prajavani and Deccan Herald. After complying the legal formalities the first party was removed from service as it is a case of voluntary retirement.

5. It is also on record the first party withdrew a sum of Rs. 2,85,000 on three different dates by using two withdrawal slips and one cheque slip of his cheque book. Though the usual practice is to keep those used withdrawal slips and cheques in bundles stitched together. The first party managed to remove those slips and cheques and made a false complaint to the State Consumer Redressal Forum alleging that he has not withdrawn any money. The management after making thorough investigation came to the conclusion that the first party deliberately committed this act have filed a criminal complaint against the first party. The first party having known that he will be held criminally liable has approached the second party for settlement for all the disputes between them. At the mediation of the lawyers of both sides, the parties have settled and thereafter a joint Memo was prepared on the terms that the second party withdraws the order of dismissal dated 23-10-90 and in substitute the management accepts the resignation tendered by the first party. They have also mutually agreed that there is no claim against each other pertaining to the service of the first party. This Joint Memo was made use by the first party to get his complaint withdrawn from Consumer Forum.

6. The above facts are undisputed. This settlement is dated 5-10-91.

7. The first party has filed a claim statement on this reference on 31-7-1991.

8. He has justified his absence on the ground that climate at Sullia was not suitable and therefore he has continuously making application for grant of leave supported by medical certificates. He has also given an explanation for not getting himself examined by the company doctor on the pretext that the said doctor once rejected to examine him and again he has unnecessarily asked the first party to wait for a considerable length of period which was not possible due to the ill health of the first party.

9. He has also made a reference to an enquiry conducted against him on a charge sheet dated 27-12-89 resulted in stoppage of one increment with cumulative effect. Admittedly the first party was not attended the said enquiry therefore it is the contention of the first party that the second party with mala fide intention got rid of the first party which is legally unsustainable.

10. As it relates to the application CGA 3/91 the order sheet does not disclose for having any order and it is in the stage of recording evidence. Later the said application called along with the main reference as any order in favour of first party in the main reference would automatically decide the merit of the application.

11. After completion of pleadings this tribunal having found that there is no scope for framing any additional issues has made an order to decide this dispute on the points covered by schedule to the reference keeping open to decide subsidiary points if they arise in the course of the case.

12. The parties have not made any progress in the earlier stages. Later on strong insistence made by this court both parties have placed their oral and documentary evidence.

13. The second party to justify their action have examined K. S. Ganapathi as M-1 who was working as an officer during 1989 and was entrusted to look after the matters, connected to leave applications. This witness has given a detailed evidence as it covered by the pleadings in respect of absence of the first party from the time he was transferred to Sullia branch till he was removed from service.

14. In addition to this evidence this witness has deposed about the conduct of the first party in sending recommendation letters by some VIPs to cancel his transfer and to retain him at Tumkur. These recommendation letters were sent to the second party bank during the period March and April, 1989. These recommendation letters are marked from Ex. M-1 to Ex. M-6. The authors of these letters are Secretary, Indira Women Junior College of Arts, Science and Commerce, Principal Siddaganga Polytechnic, Sri S. Mallikarjuniah, Deputy Chairman, Karnataka Legislative Council, Shri Chenniah Odeyar, Member of Parliament and Sri M. Krishna Rao, Member of Parliament.

15. After exhausting his attempt to send these recommendations the first party having found that the second party yielded to these influences, appears to have reported for duty on 3-6-89 though he has been relieved 28-2-89.

16. The first party in his evidence has made much of his work before his transfer in mobilising deposits and receipt of meritorious service certificates from Ex. W-1 to Ex. W-17. With regard to his continuous and intermittent leave his contention is that he was ailing and therefore could not attend the work at Sullia.

17. As the medical certificate does not give rise to any presumption that he was totally described to do the work, nor there is any material that he is total in capacity to work during those period. It is admitted of no doubt that he had made a pretence of going to a nominated doctor from the bank and therefore his evidence is bereft of truth. He has not contravened in his evidence the issue of letters by various VIPs for cancellation of his transfer and place him at Tumkur. This is a point which shows that the first party without there being a valid reason for his absence has refused to work at Sullia and his previous conduct is a mirror to reflect his later conduct of remaining absent only to cause inconvenience to the bank.

18. The second party also placed materials that at present he is a nominated Director of Kalpatharu Gramena Bank of Tumkur District.

19. It is brought to the notice of this tribunal that the first party, in fact filed an application under Section 33-C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947 in GA No. 24/89 before the Labour Court for similar relief. He has obtained an order in his favour. This order of the Labour Court was upheld by the High Court in W.P. No. 15168/91 dated 7-1-97. The first party has suppressed this fact with ulterior motive.

20. The second party have complied to the clause 16 of Bipartite Settlement by issuing a notice as contemplated and only thereafter the first party was removed from service.

21. Now the other question that requires consideration is a settlement in the form of joint Memo, a copy of which is marked as Ex. W-14. The first party in his evidence has not disputed this fact.

22. He states "it is true a joint Memo was filed on 5-11-91 agreeing that the parties have no claim against each other. Ex. M-14 is the copy of the said joint Memo and his signature is at Ex. M-14(a)". In fact the first party has made use of this joint Memo to withdraw a case pending before the Consumer Forum, Bangalore. In fact a certified copy of the order is also made available. Therefore it is crystal clear that the first party has acted on this Memo and therefore it is not open for him to make an about turn and give a complete go by to the solemnity of this settlement. For the purpose of record I am marking the comprise Memo filed by both parties as court exhibits i.e. Ex. C-1 and Ex. C-2.

23. Section 2(P) of Industrial Disputes Act defines what is settlement. According to this a settlement arrived at in the course of conciliation proceedings and includes written agreement between the employer and workmen arrived at in the course of conciliation proceedings.....".

24. Section 18 defines the binding nature of settlements and awards on the persons who are the signatory. According to sub-clause (1) settlement arrived at by agreement between the employer and workman otherwise than in the course of conciliation proceedings shall be binding on the parties to the agreement.

25. In view of the discussions made above the first party is not entitled for any relief. In fact the conduct of the first party is not innocence, but he has deliberately made attempt to nullify a judicious order made by the second party and he has also suppressed the fact of making use of joint Memo to withdraw a case filed against him. He has also suppressed the fact of obtaining an order on identical question by the Labour Court under Section 33-C(2) of the I.D. Act. Therefore the act of the first party being deliberate with sinister motive, it amounts to be little the law by wood winking and therefore it is a case where the second party is entitled to be compensated. The first party is now working as a Director of Kalpatharu Gramena Bank at Tumkur and he has not suffered in any manner due to the orders passed by the second party.

26. He is not only guilty of putting the second party in awkward position, but he has also suppressed the material facts before this tribunal. His attempt is nothing but speculative. He has wasted the valuable time of this tribunal by continuing his case though he knew that it is a useless adventure.

27. The question is whether the tribunals are empowered to award cost in the disputes coming under I.D. Act? My answer is yes. The award of cost is a discretionary power which is to be exercised according to rules, reasons and justice. It should not be arbitrary, vague and fanciful. The well recognised principles would be the conduct of a party to the dispute which is reprehensible such as harassing the opposite party or keeping the opposite party out of their legitimate rights. In such events award of cost are justified.

28. Taking into consideration the conduct of the first party a sum of Rs. 2500 is ordered to be paid as a cost to second party in accordance with law. If the first party fails to pay the cost the second party is at liberty to recover the same in accordance with Section 11(7) of the Industrial Disputes Act, 1947.

29. Consequent to the discussions made above the reference is rejected.

(Dictated to the stenographer, transcribed by her and corrected and signed by me on 15th February, 1999.)

JUSTICE R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

का.आ. 885.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ़ हैदराबाद के प्रबंधन के संबंध में निष्पत्ति और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापट्टनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/71/97-आई.आर. (बी-1)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 885.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Visakhapatnam as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Hyderabad and their workman, which was received by the Central Government on 4-3-1999.

[No. L-12012/71/97-IR(B-I)]

SANATAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT VISAKHAPATNAM

#### PRESENT :

Sri K. Satyanand, B.Sc., LL.M., Chairman & Presiding Officer.

Wednesday, the 16th day of December, 1998

I.T.D. (C) : 34/97

#### BETWEEN

M. Sagthamma,  
C/o Sri A. Rama Mohan,  
D. No. 5-112, Upstairs,  
Motaji Street,  
Gopalapatnam,  
Visakhapatnam.

.. Workman.

#### AND

The Regional Manager,  
State Bank of Hyderabad,  
Registered office : Region-I,  
Seethampeta Main Road,  
Visakhapatnam.

.. Management.

This dispute coming on for final hearing before me on a reference made by Government of India vide letter No. L-12012/71/97-IR(B.I.) dated 9-12-97 in the presence of the workman in person and the management get exparte, upon hearing the argument of workman, and on perusing the entire material on record, the court passed the following :

#### AWARD

(1) This is an industrial dispute that came up for adjudication before this court on a reference made by the Government of India which framed the terms of reference as follows :

"Whether the action of the management of State Bank of Hyderabad, Regional Office, Visakhapatnam in terminating the services of Smt. Madagala Sitamma, Sweeper, State Bank of Hyderabad, Chuchukonda Branch w.o.f. 7-1-1994 without following the procedure laid down under Industrial Disputes Act, 1947 is justified? If not, to what relief the concerned worker is entitled to?"

(2) The profile of the claim as culled out from the pleadings is briefly as follows : The workman claimed to have joined the service of the State Bank of Hyderabad, Chuchukonda branch as a Sweeper on a monthly salary of Rs. 75. It seems her wages used to be deposited every month in her S. B. Account. She proceeded to submit that after some time she fell sick. During her sickness her husband was deputed by her and the bank used to take his services.

While things stood thus, her services, she complained came to be terminated abruptly by the bank authorities without any notice whatsoever. She therefore got issued a lawyer's notice to the bank authorities. The bank authorities gave a reply admitting her services. Then she approached the Government for re-conciliation but with no avail. It is how the matter came to be referred to this court. She pleaded for reinstatement with back wages and other reliefs.

(3) The management remained exparte and did not choose to appear and file its statement.

(4) The workman examined herself as WW1 and marked Exs. W1 to W6. She relied upon more particularly the reply of the management to her lawyer's notice marked as Ex. W2 and the statement of the management before the ALC marked as Ex. W4. She reiterated her averments in the claim statement in the course of her deposition. Heard counsel for the workman.

(5) The points that arise for consideration are :

(1) Whether the applicant was the employee of the management in question?

(2) Whether the retrenchment of the workman by the management is true and valid in law?

(3) To what relief?

(6) Point Nos. 1 and 2 : Though the workman did not ever in her statement the exact period during which she worked under the management, she stated in her evidence that she worked under the management from the year 1989 to 1994. Naturally that remained un rebutted. She filed a xerox copy of the reply notice purported to have been issued by the management which is marked as Ex. W2. In the said reply notice, the management in question clearly admitted that this workman worked under them but for a brief period from 28-3-89 to 31-7-90. This shows that the management in question extracted the services of this workman at one point of time or the other. This tie of employment admitted by the management highly probablises the un rebutted testimony of the workman that she had worked for quite a long time as 1989 to 1994. Moreover, once the management admitted the employer-employee relationship at one point of time or the other it becomes strongly incumbent upon the management to produce the muster rolls contemplated by Sec. 25D and seniority list contemplated by Rule 79 to disprove that she worked only for a short period. This proposition of law is derived from a catena of decisions of which the decision in AIR 1986 SC 132 figures prominently. When the workman asserts that she/he worked for a particular period and when the management concedes the factum of such employer-employee relationship enuring for some time and still fails to bring out the entire record for which it is the natural custodian, not only under the provisions of the I.D. Act but also under the provisions of various labour laws, it is not unreasonable for the labour court to draw an adverse inference against the management. In this case the management did not choose to rebut the testimony of WW1. Thus, the totality of circumstances highly probablise the truth of the workman's case. In other words I have no hesitation to hold that the workman worked for the qualifying period entitling her to invoke the protection under Sec. 25F of the I.D. Act what with the banking business being well known to be an industry and the applicant being its workman firmly established. It is not the case of the management that it ever followed the provisions of Sec. 25F of the I.D. Act while discharging the workman from service. Thus, the retrenchment of the workman is undoubtedly illegal.

(7) Point No. 3 : In view of the findings given above, an award is passed directing the management to reinstate the workman with back wages and continuity of service and also pay to the workman an amount of Rs. 500 (Rupees five hundred only) by way of costs.

Dictated to steno transcribed by her given under my hand and seal of the court this the 16th day of December, 1998.

K. SATYANAND, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE IN I.T.D. (C) 34/97  
WITNESSES EXAMINED :

## FOR WORKMAN :

WW1 : Seethamma.

For Management—None.

## DOCUMENTS MARKED :

## FOR WORKMAN :

- Ex. W1 : 1-11-95 : Copy of the lawyer notice.  
 Ex. W2 : 21-11-95 : Reply of the management to lawyer Notice.  
 Ex. W3 : Copy of the petition in OP7(2)/96 before ADC, Visakhapatnam.  
 Ex. W4 : Statement of management before ALC (Central), Visakhapatnam.  
 Ex. W5 : 4-11-96 : Report of the ALC (Central) Visakhapatnam in OP7(2)/96.  
 Ex. W6 : SB A/c no. 30 passbook of M. Narayana Murthy of State Bank of Hyd., Chuchukonda.

## FOR MANAGEMENT : NIL.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

क्र.सं. 886.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर, बंगलूर के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिहरण, बंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/236/93-आई.प्रार. (बी-1)]  
सनातन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 886—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Mysore, Bangalore and their workman, which was received by the Central Government on 4-3-1999.

[No. L-12012/236/93-IR(B.I.)]  
SANATAN, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, BANGALORE

Dated 16th February 1999

## PRESENT :

Justice R Ramakrishna, Presiding Officer.

C. R. No. 17/94

## I PARTY

The General Secretary,  
 State Bank of Mysore  
 Employee Association,  
 No. 344, 32nd Cross,  
 4th Block, Jayanagar,  
 Bangalore-560011.

## II PARTY

The Managing Director,  
 State Bank of Mysore,  
 Head Office, K. G. Road,  
 Bangalore-560009.

## AWARD

1. The Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2A of the section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred this dispute vide Order No. L-12012/236/93-IR.B.I. dated 11-2-94 for adjudication on the following schedule.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of Mysore in not regularising the services of Shri Siddamallarayya Shastri as Telex Operator is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. This dispute was espoused by the General Secretary State Bank of Mysore Employees Association.

3. The first party, herein after referred to as Sastry. A post of Telex operator became vacant at Bangalore branch. The willingness of Sastry was considered and he was appointed as Telex operator by an Order dated 20-1-1992 on temporary basis. Mr. Sastry says that his request to regularise in the post of Telex Operator was not considered. Since he was not regularised he has put to monetary loss. According to him appointment to this post should be on the basis of Branch Seniority. He has also alleged a deemed regularisation as he has been working on the temporary basis, within three months of his appointment.

4. The second party has denied all material averments except the fact that this Sastry was working on officiating basis as Telex Operator and his contention branch wise seniority is denied as, the basis would be on centrewise seniority. Since the post of Telex operator is on the basis of centrewise seniority and temporary, the question of regularisation does not arise. They further contended that Sastry is not eligible for regularisation as he was working only on officiating basis and therefore there is no question of filling up all vacancies within 3 months. The second party also denied the averments of practicing unfair labour practice and they averred that the claim petition is misconceived, frivolous and untenable.

5. Since there was no scope to frame any issue, the parties are directed to lead evidence on the points referred in the schedule to the reference.

6. The witness for the second party while justifying the action of the second party has stated that Sastry was in fact transferred to Sudamnagar branch on 31-7-1991 where Telex Operator work was entrusted to him. The bank by virtue of settlement Ex. M-4 taken into consideration the centre wise seniority inspite of branch seniority and in fact due to Mechanisation of works the Telex Operators were given an option to become Special Assistants. This offer is accepted by Sastry and he has also given his consent on 19-5-1997 and on consequent to that he was designated as Special Assistant and transferred to Nalamangla vide order Ex. M3 dated 31-12-1997.

7. The above materials discloses Mr. Sastry has made a false plea which was supported by union who has espoused this dispute. Mr. Sastry and the general Secretary of this union have coolly withdrawn themselves from this case and left the fate of the dispute to be decided only on the basis of second parties approach. This method of treating the cases are reprehensible. It was open for the General Secretary or the concerned workman to make submission in this case to reject the reference without making so many exercise of recording evidence, adjourning the case from time to time. Since the union and the first party who are responsible for rising this dispute knowing that the settlement Ex. M-4 gave little chance to have successful end and having failed to do so, the concerned workman is liable to pay a sum of Rs. 200 as cost to the second party. The second party is at liberty to recover this cost by making deduction in the salary drawn



by Mr. Sastry reserving the right to take recourse under Section II, sub-clause 7 of Industrial Disputes Act, 1947. Consequently the reference is rejected.

(Dictated to the stenographer, corrected and signed by me on 16th February, 1997).

JUSTICE R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1999

का.आ. 887:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार फ़ेडल बैंक लिमिटेड, एलाई, के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निश्चित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण अलापुजा, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/92/96-आई.आर. (बी.-I)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th March, 1999

S.O. 887.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Alappuzha as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Federal Bank Ltd., Alwaye and their workmen, which was received by the Central Government on 8-3-99.

[No. L-12012/92/96-IR(B-I)]

SANATAN, Desk Officer.

#### ANNEXURE

#### IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ALAPPUZHA

(Dated this the 15th day of January, 1999)

#### PRESENT :

Shri K. Kanakachandran, Industrial Tribunal.

L.D. No. 23/97(C)

#### BETWEEN

The Chairman, Federal Bank Ltd., Head Office, P. B. No. 103, Alwaye 683 101, Kerala State.

#### AND

Their workman represented by the General Secretary, Federal Bank Employees Union Central Office, P. B. No. 10, Alwaye 683101, Kerala.

#### REPRESENTATIONS :

M/s. B. S. Krishnan Associates, Advocates, Warriam Road, Ernakulam, Cochin-682016.-- For Management.

Sri. M. Ramachandran, Advocate, Ernakulam.-- For Union.

#### AWARD

1. In this dispute, which is referred by the Government of India through order No. 12012/92/96-IR (B.I) dated 16-7-97 following issues were referred for adjudication :

“Whether the action of the management of Federal Bank Ltd. Alwaye in imposing the punishment of stoppage of one increment without commulative effect from December, 1995 on Shri. P. O. Shanmughan, Clerk, Vaikom Branch is reasonable and justified? If not, to what relief the workman is entitled?”.

2. The workman in this dispute is an employee of management Bank working at Vaikom Branch. Pursuant to the disciplinary action initiated against him, a domestic enquiry was conducted. The Enquiry Officer after conducting enquiry found that the employee concerned was guilty of charges. The management imposed the punishment of stoppage of one increment without cumulative effect from December, 1995. The justifiability of that punishment is the issue to be resolved in this dispute.

3. The management produced the enquiry file which contained the memo of charges issued to the worker on 28-3-1988. For getting the factual details and background leading to the disciplinary action, it will be appropriate to extract the charges in full which were based on the allegation of unauthorised absence.

“(a) Shri. Shanmughan, PF 2640, Clerk of Branch Vaikom absented from duty from 14-12-1987 to 17-12-1987. For the above day Shri. Shanmughan neither got any leave sanctioned nor informed the leave sanctioning authority the reasons for his absence. As the branch had no information regarding his absence, on 15-12-1987 the branch Manager had sent a telegram directing Shri. Shanmughan to join duty immediately and to explain the reason for the unauthorised absence. A letter was also sent by the branch confirming the telegram having been sent to him on 15-12-1987.

(b) On 16-12-1987 Shri. Shanmughan came in front of the branch and participated in the demonstration along with other striking employees of the Bank. Thereafter he entered the Manager's cabin along with the branch representative Shri. Lonachan K. J. and started arguments with the Manager justifying his absence. He also produced a medical certificate certifying absence for the 14-12-1987 to 17-12-1987. Since it was mentioned in the medical certificate that Shri. Shanmughan require absence up-to 17-12-1987, Shri. Sebastian Mattom, Branch Manager did not allow him to join duty on that day. Shri. Shanmughan told the Manager that his wife who is working in the Bank's Palluruthy branch tried to contact Branch Vaikom over phone on 14-12-1987 for informing about his

illness to the Manager. Shri. Shanmughan also told the Manager that since the telephonic conversation was not clear, his wife entrusted the telephone exchange staff to inform the matter of the Branch Manager.

- (c) In fact the Manager did not receive any information from Shri. Shanmughan's wife or from telephone exchange staff about his illness and the consequent absence. Instead a lady said to be working in telephone contacted the Manager on 14-12-1987 and enquired whether Shri. Shanmughan was present in the Office or not. If it was her intention to inform the illness to the Manager, the lady could have informed the Manager who responded the telephone call accordingly. But she did not inform anything regarding the illness or the leave. When this was told to him by the Manager Shri Shanmughan started shouting at the Manager that the Manager is telling lie and only because of Manager's foul-play he was forced to come to the Office in spite of the illness. Shri. Shanmughan had also arranged some local people to come inside the branch when his conversation was on with the Manager. While Shri. Shanmughan continued his arguments with the Manager in a very loud voice, the local people numbering approximately 20-30, entered the branch and surrounded the Manager's cabin for sometime, Shri. Shanmughan tried to impress upon the local people that the Manager was deliberately harassing him, with the intention to win the support and sympathy's of them in his favour and also to create ill will/displeasure among them against the Manager.
- (d) Though Shri. Shanmughan produced a medical certificate dated 14-12-1987 recommending absence from 14-12-1987 to 17-12-1987, he did not forward it to the Branch on 14-12-1987. He has not given any reason for doing so.
- (e) On 18-12-1987 Shri. Shanmughan joined duty at the branch after the absence. Thereafter on the same day Shri. Shanmughan was served with a copy of the confirmation letter dated 15-12-1987 sent to him on 15-12-1987 regarding his absence, wherein he was directed to explain the unauthorised absence. Shri. Shanmughan did not submit any explanation till date when he was asked orally by the Manager about the explanation. Shri. Shanmughan informed him that he was not prepared to submit any explanation in the matter.
2. The aforesaid acts/omissions on the part of Shri. Shanmughan, Clerk, if proved, would amount to acts of misconduct of :
- (i) doing any act prejudicial to the interest of the Bank.

- (ii) riotous or disorderly or indigent behaviour on the premises of the Bank; and
- (iii) wilful insubordination or disobedience of any lawful and reasonable order of the management or of a superior.

3. Shri. Shanmughan is directed to explain to the undersigned in writing the facts and circumstances appearing against him in the matter and why disciplinary action should not be taken against him. His explanation shall reach the undersigned within 3 days of the receipt of this letter, failing which it will be presumed that he has nothing to submit in the matter and the matter will be proceeded accordingly.

4. The workman submitted his explanation stating that he was not on unauthorised leave on 14-12-87 and in fact due intimation was given by his wife working in Cochin branch (Palluruthy) through telephone to the Branch Manager in which the workman was working on the relevant date. Notwithstanding that on the next day i.e. On 15-12-1987, he received a telegraphic message from the Branch Manager asking his explanation for absence. On getting that telegram on 15-12-1987, the workman reported for work on 16-12-1987 itself, but he was not allowed to join duty. The Branch Manager sent a report regarding this to the Head office. On the basis of that report, disciplinary actions were initiated. The contention raised by the union on behalf of the workman is that the very initiation of disciplinary proceedings was vindictive in nature. The domestic enquiry conducted itself was an empty formality and the findings of the Enquiry Officer was perverse. The relationship between the employee and the management was rather strained on account of his participation in the All India Struggle of Bank Employees during 1987-88. Although all the disciplinary proceedings initiated against the other employees were dropped, in his case alone, management was very adamant. Therefore the plea of the union is for setting aside the punishment imposed on the workman.

5. In the written statement of the management it is contended that the workman concerned absented from duty from 14-12-1987 to 17-12-1987. For availing leave on those days, no advance information was given. Nor he has even obtained any sanction from the sanctioning authority. Since there was no information from him, the Branch Manager sent a telegram directing the workman concerned to join duty immediately and to explain the reason for unauthorised absence. Following that, a letter was also sent to him confirming the telegram on 15-12-1987 itself. The workman came to the branch on the next day i.e. on 16-12-1987 and participated in the demonstration along with the striking employees. Thereafter, he entered the Manager's Cabin along with the Branch representative and started arguments with the Manager justifying his absence. He also produced a Medical Certificate certifying

his absence from 14-12-1987 to 17-12-1987. Since it was mentioned in the medical certificate that the employee required absence upto 17-12-87 the Branch Manager did not allow the workman to join duty on that day. The acts/omissions on the part of the workman proved to be a misconduct which is prejudicial to the interest of the bank. Any kind of wilful insubordination or disobedience or any lawful and reasonable orders of the management or of a superior officer also attracts punishment. Though he was charge sheeted he was not prepared to submit any explanation to that. Therefore the management conducted a domestic enquiry through another Branch Manager, who was working at Madras then. That Branch Manager conducted an enquiry in compliance of the principles of natural justice. The Vice President of the union participated in the enquiry and defended workman. Based on the evidence adduced in the enquiry, the workman was again given opportunity to explain the findings entered into against him. The disciplinary authority after appreciating evidence and also looking through the submission made by the workman, had concurred with the findings made by the Enquiry Officer. Before imposing punishment, although the workman was given one more opportunity, he did not choose to avail that. In that circumstance he was awarded with the punishment of stoppage of one increment with cumulative effect by an order dated 14-7-1995. The workman filed an appeal against that punishment before the Appellate Authority. The Appellate Authority found that there was no mitigating circumstances to interfere the punishment. However taking a lenient view in the matter, the Appellate Authority reduced the punishment as one of stoppage of one increment without cumulative effect. Therefore according to the management there is no reason to interfere on the punishment awarded. As an alternative, it is pleaded that in case the enquiry is found vitiated, management may be permitted to adduce fresh evidence to substantiate the charge against the workman.

6. No oral or documentary evidence was adduced before this Tribunal. The management produced enquiry files containing the depositions of witness and the documents marked at the time of domestic enquiry and also the findings of the Enquiry Officer. After the receipt of the enquiry file, the learned counsel for the workman had submitted that the union was conceding the validity of the enquiry. According to the learned counsel, the union is aggrieved only at the perverse findings entered into by the Enquiry Officer and on the action taken thereon by the management. In this background this issue referred for adjudication has to be looked into.

7. The domestic enquiry file in this dispute was produced by the management. The charge sheet issued to the workman on 28-3-1988 will give sufficient details under what circumstance discipli-

nary proceedings were initiated. According to the workman on account of Viral fever he had to be on casual leave for three days from 14-12-1987. He further states that the fact regarding his ailment was duly communicated through telephone by his wife who is also an employee under the management working Palluruthy Branch. According to him that information which was conveyed by his wife to the Manager was not given attention. On the very next day, that is on 15-12-1987, the Branch Manager sent a telegram directing the workman to join duty immediately and to explain the reason for his unauthorised leave for previous day. A letter of confirmation was also sent by post on 15-12-1987. Surprisingly, a very unusual method was adopted by the Branch Manager in sending telegram seeking an employee's explanation for availing leave for one day or two days. On receipt of telegram the workman reported in the branch on 16-12-1987 itself and explained to the Manager under what circumstances he was absenting on 14th and 15th of December 1987. To vindicate his stand the workman had produced a medical Certificate obtained from a Registered Medical Practitioner certifying the need for his absence from duty from 14-12-87 to 17-12-1987. After noting that certificate, the Branch Manager disallowed the workman to join duty on 16-12-1987 itself. Reason for that was certification of leave till 17-12-1987. Noting this very strange stand adopted by the Branch Manager, the branch representative of the union met the Branch Manager and made enquiry regarding the unusual steps adopted by him in dealing with leave application of the delinquent workman. On account of the defiant attitude shown by the Branch Manager, there was every possibility of heated arguments and that lead to the disciplinary action against the workman. From these facts which are coming mostly from the content of the charge sheet, one thing is clear. The Branch Manager was really responsible for precipitating the whole thing to that level. It appears he acted with vindictiveness.

8. There is no case for the management that there was no leave to the credit of the workman either as casual leave or sick leave for the purpose of availing leave. It is impossible to seek prior permission from the Branch Manager when an employee is on sick. Any how information regarding absence will be given through some mode. It can be either through telephonic message or message through co-workers. Usually it will be followed by written application in the prescribed form also. The workman's specific case is that his wife who is also an employee in a different branch under the management, had given telephonic message to the Branch Manager. It is surprising to note that for one day's absence, the Branch Manager had sent telegraphic notice seeking explanation for availing leave. Not only that, on the same day itself, a letter of confirmation was also sent. All these were done by the Branch Manager purposely to harass the employee concerned. After getting telephonic

message and letter of confirmation, the workman reported on 16-12-1987 itself with Medical Certificate. Then Branch Manager tried to exploit situation by taking note of the period of leave recommended by the Registered Medical Practitioner. Finding that medical advice was to avail leave upto 17-12-1987, the Branch Manager refused to admit him to duty on 16-12-87. All these will only show the very hostile attitude on the part of the Branch Manager towards workman. Highlighting all these memo of charges was framed. When the domestic enquiry was conducted, both sides stuck on their respective stand. Ultimately accepting the findings of the Enquiry Officer, the management imposed the punishment of barring of one increment with cumulative effect.

9. A report sent by the Branch Manager confidentially to the head office on 30-12-1987 is self explanatory. The very purposeful and vindictive attitude on the part of the Branch Manager was very evident from that confidential report which is also part of the enquiry file [marked as ME(7)].

10. While going through the entire enquiry files it can only be gathered that if at all any untoward incident happened in the branch on 16-12-1987, that was only on account of the precipitation by the Branch Manager. Workman's roll is only of contributory in nature. He cannot be characterised as the creator of the trouble. In view of the above discussion, it is held that the whole disciplinary proceedings and punishment were purely vindictive in nature. Hence it is very difficult to sustain the punishment so imposed on the workman, although it is of only barring on one increment without cumulative effect. Any how same has to be set aside.

Award is passed accordingly.

(Dated this the 15th day of January, 1999.)

K. KANAKACHANDRAN,  
Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1999

का.आ. 888 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हुबली के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बंगलोर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/300/89-आई.आर. (बी.-I)]  
सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th March, 1999

S.O. 888.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the

Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Hubli and their workman, which was received by the Central Government on 9-3-1999.

[No. L-12012/300/89-IR(B-I)]  
SANATAN, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR  
COURT, BANGALORE

Dated 26th February, 1999

PRESENT :

JUSTICE R. RAMAKRISHNA,  
Presiding Officer.

C.R. No. 48/1990

I PARTY :

Shri V. M. Mahapurush  
Nana Dixit Wada,  
Line Bazar,  
Dharwad-580001.

II PARTY :

The Chief Regional Manager,  
State Bank of India,  
Regional Office,  
Lamington Road,  
Hubli-580020.

## AWARD

1. The Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2A of the section 10 of the Industrial disputes Act, 1947 has referred this dispute vide Order No. L12012/300/89-IR(B.1) dated 12-6-98 for adjudication on the following schedule.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of India in terminating the services of Shri V. M. Mahapurush w.e.f. 31-8-89 is just and legal. If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. A notice issued under an ordinary post was returned unserved with a shara "LEFT NOT KNOWN". A notice under RPAD was issued which was returned with same shara. The second party is now represented by a learned advocate.

3. Since the first party on whose insistence this reference is made is not available inspite of the best efforts made by this court, the matter can not be decided on its merits. There is no other mode to secure the presence of first party.

4. Therefore this reference is rejected.

(Detected to the stenographer, transcribed by her, corrected and signed by me on 26th February, 1999.)

JUSTICE R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1999

का. आ. 889 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सदर्न रेलवे के प्रबन्धतल के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 09-03-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—41012/31/86—डी II (बी.),  
सं. एल.—41012/24/86—डी. II (बी),  
सं. एल.—41012/28/86—डी. II (बी),  
सं. एल.—41012/34/86—डी. II (बी),  
सं. एल.—41012/36/86—डी. II (बी),  
सं. एल.—41012/33/86—डी. II (बी)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th March, 1999

S.O. 889.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Southern Railways and their workman, which was received by the Central Government on 09-03-1999.

[No. L-41012/31/86-D.II(B),

L-41012/24/86-D.II(B),  
L-41012/28/86-D.II(B),  
L-41012/34/86-D.II(B),  
L-41012/36/86-D.II(B),  
L-41012/33/86-D.II(B)]

SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Dated, 1st March, 1999

PRESENT:

Justice R. Ramakrishna, Presiding Officer.

C. R. No. 107/1987

I Party

Shri R. Rajendran,  
S/o Ruthnam,  
No. 111, 3rd Cross,  
Prakashnagar,  
Bangalore-21.

II Party

Divisional Railway Manager,  
Southern Railways,  
Bangalore City Railway  
Station, Bangalore.

C. R. No. 108/1987

I Party

Shri Ranga,  
S/o Dasappa,  
No. 158, Swathanthnagar,  
Srirampuram,  
Bangalore-21.

II Party

Divisional Railway Manager,  
Southern Railways,  
Bangalore City Railway  
Station, Bangalore.

C. R. No. 142/1987

I Party

Shri P. Changanrayan,  
S/o S. Loganathan,  
No. 97, III Cross,  
Prakashnagar,  
Bangalore-21.

Shri K. Ramanaiah,  
S/o Vengaiyan,  
No. 279, 9th Cross,  
Prakashnagar,  
Bangalore-21.

Shri Palani, A.,  
S/o K. M. Annamali,  
Balegowda Compound,  
I Main, Deepanjali Nagar,  
6th Cross, Mysore Road,  
Bangalore-21.

Shri K. Gangadharan,  
S/o Kalimuthu,  
No. 158, Swathanthnagar,  
Srirampuram,  
Bangalore-21.

Shri S. Murthy,  
S/o Subramany, Major,  
No. 215, 6th Cross,  
Prakashnagar,  
Bangalore-21.

Shri Ravi, R.,  
S/o K. Raju,  
No. 44/2, Metadabjalli,  
Bangalore-32.

Shri Krishnamurthy, V.,  
S/o Veeraswamy,  
No. 1538, Mariyappanapalyam,  
Srirampuram, Bangalore-21.

Shri Devan, P.,  
S/o Periappa,  
No. 140, II Main Road,  
Ramachandrapuram,  
Srirampuram, Bangalore-21.

Shri R. Selva, since dead  
rep. by his L.R's.,  
Smt. Julian Mery, wife,  
S. Rajesh—son,  
S. Shalini—daughter,  
No. 135-D, New Railway  
Quarters' near Vasanthnagar,  
Post Office, Bangalore-52.

II Party

Divisional Railway Manager,  
Southern Railways,  
Bangalore City Railway  
Station, Bangalore.

Divisional Railway Manager,  
Southern Railways,  
Bangalore City Railway  
Station, Bangalore.

Divisional Railway Manager,  
Southern Railways,  
Bangalore City Railway  
Station, Bangalore.

Divisional Railway Manager,  
Southern Railways,  
Bangalore City Railway  
Station, Bangalore.

The Divisional Railway  
Manager, Southern Railways,  
Bangalore Railway Station,  
Bangalore.

The Divisional Railway  
Manager, Southern Railways,  
Bangalore Railway Station,  
Bangalore.

The Divisional Railway  
Manager, Southern Railways,  
Bangalore Railway Station,  
Bangalore.

The Divisional Railway  
Manager, Southern Railways,  
Bangalore Railway Station,  
Bangalore.

The Divisional Railway  
Manager, Southern Railways,  
Bangalore Railway Station,  
Bangalore.

C. R. No. 145/1987

#### I Party

Shri T. Venkatesh,  
S/o Thammayya,  
No. 276-L, M. G. Railway  
Quarters, Bangalore-23.

#### II Party

The Divisional Railway  
Manager, Southern Railways,  
Bangalore Railway Station,  
Bangalore.

C. R. No. 146/1987

#### I Party

Shri B. V. Srinivasalu,  
S/o B. Venkataswamy,  
No. 21-8, 1st Cross,  
II Main Road,  
Prakashnagar,  
Bangalore-21.

#### II Party

The Divisional Railway  
Manager, Southern Railways,  
Bangalore Railway Station,  
Bangalore.

C. R. No. 22/1988

#### I Party

Shri N. Rajendran,  
S/o Natarajan,  
No. 4th Block,  
Rajajinagar,  
Bangalore-10.

#### II Party

The Divisional Railway  
Manager, Southern Railways,  
Bangalore Railway Station,  
Bangalore.

#### COMMON AWARD

1. The Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2A of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred all the above disputes for adjudication by their reference Numbers :

C. R. No. 107/1987

(a) No. L-41012/31/86-D.II(B) dated 22-5-1987.

#### SCHEDULE

"Whether the management of Southern Railway is justified in terminating the services of Shri R. Rajendran w.e.f. 16-5-84? If not, to what relief the workman is entitled?"

C. R. No. 108/1987

(b) No. L-41012/24/86-D.II(B) dated 22-5-1987.

#### SCHEDULE

"Whether the management of Southern Railway is justified in terminating the services of Shri Ranga w.e.f. 16-5-87? If not, to what relief the workman is entitled?"

C. R. No. 142/1987

(c) No. L-41012/28/86-D.II(B) dated 25-8-1987.

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Southern Railway in terminating the services of nine workmen (as shown below) w.e.f. 16-5-85 is legal and justified? If not, to what relief these workmen are entitled?"

1. Shri P. Changalarayan
2. Shri K. Ramanaiah.
3. Shri A. Palani.
4. Shri K. Gangadharan
5. Shri S. Murthy.
6. Shri R. Ravi.
7. Shri V. Krishnamurthy.
8. Shri P. Devan.
9. Shri Selva.

C. R. No. 145/1987

(d) No. L-41012/34/86-D.II(B) dated 25-8-1987.

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Southern Railway in terminating Shri T. Venkatesh from service w.e.f. 16-5-84 is legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

C. R. No. 146/1987

(e) No. L-41012/36/86-D.II(B) dated 2-9-1987.

#### SCHEDULE

"Whether the termination of Shri Srinivasalu w.e.f. 16-5-84 by the management of Southern Railway is legally in order and justified? If not, to what relief and from what date, the workman is entitled to?"

C. R. No. 22/1988

(f) No. L-41012/33/86-D.II(B) dated 12-5-1988.

## SCHEDULE

"Whether the management of Southern Railway is justified in terminating the services of Shri N. Rajendran w.e.f. 16-5-84? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The above references are sent to this Tribunal on various dates referred to above. The disputes were registered in respective case numbers as and when they are received. Since the cause of action alleged by all the workmen and the question of law and the fact involved in all these cases are being similar, all these cases are clubbed and a common evidence was recorded in C. R. No. 108/1987. All the

workmen were examined as witnesses in support of their respective cases. The second party has examined one Shri C. Rangaraj, the then Assistant Personnel Officer, Southern Railway as M.W.1 and closed their evidence. Both defence and workmen documents were marked as exhibits. The learned advocates have filed their written arguments.

3. All these workmen have taken a common plea in their respective claim statements. Their plea both on facts and on the question of law is almost similar. Therefore it is unnecessary to narrate the plea of each workman. The following chart disclosing the date of appointment, date of passing medical examination and date of termination are based on their pleadings.

## CHART

Name S/Sri	Date of appointment	Date of passing of medical exam	Date of termi- nation
P.Changalarayan	6-4-83	11-5-83	15-5-1984
N.Rajendran	6-4-83	11-5-83	15-5-1984
R.Rajendran	6-4-83	11-5-83	15-5-1984
A.Palani	6-4-83	11-5-83	15-5-1984
Ranga	20-4-83	26-7-83	15-5-1984
C.Gangadhran	20-4-83	26-7-83	15-5-1984
S.Murthy	20-4-83	26-7-83	15-5-1984
R. Ravi	20-4-82	26-7-83	15-5-1984
B.V. Srinivasulu	20-4-83	26-7-83	15-5-1984
V. Krishnamurthy	20-4-84	26-7-83	15-5-1984
P. Devan	20-4-83	26-7-83	15-5-1984
Venkatesh	20-4-83	26-7-83	15-5-1984
Selva	20-4-83	23-6-83	15-5-1984
Ramanaiah	20-4-83	21-6-83	15-5-1984

5. Their consistent case is that they have been appointed as substitute Khalasi's on a pay scale of Rs. 196—232 per month. They are under the control of CTXR/BYPL, against the existing vacancies w.e.f. respective date of appointments as shown in the chart. They worked continuously, uninterrupted and to the utmost satisfaction. When this being the case the second party stopped their services w.e.f. 15-5-1984 without assigning any reasons.

6. They have worked continuously for more than 13 months which is more than 240 days in a period of 12 calendar months. Therefore it is mandatory for the second party to follow the provisions of Chapters V-A and V-B of Industrial Disputes Act, 1947, shortly Act. According to them Section 25F was not complied and therefore their termination is a nullity under law. Therefore they have prayed for reinstatement, continuity of service, back wages and other reliefs.

7. The contention of the second party in all these disputes are that these workmen have not been appointed in any capacity under the second party at all. The alleged order produced by the first party alleged to have been signed by Shri C. Rangaraj, the then Assistant Personnel Officer, Southern Railway are denied and the matter was under investigation by the Railway vigilance commission.

8. Therefore the main contention of the second party is that these workmen were never appointed by the second party and therefore all other allegations contained in their claim statement are totally false and the alleged appointment orders are forged and therefore the first party workmen are not entitled for any reliefs.

9. After completion of pleadings this tribunal has initially framed an additional issue on 16-7-1987 as follows:

"Whether the first party workmen proves that they have been employed by the second party as contended by them?"

10. Again on 21-9-1987 one more additional issue was framed as follows:

"Whether the first party workmen committed fraud as alleged in the counter statement?"

11. The initial burden was placed on the second party to justify the order of termination in respect of these workmen.

12. In view of the respective stand taken by the parties the question has to be resolved by appreciating both oral and documentary evidence. It is a very serious situation where the second party alleges that these workmen were never appointed and the orders of appointment are forged one. On the contrary the workmen alleges that they have been appointed as narrated in their evidence and the documents relied by them came into existence as a result of their appointment and therefore the second party with view to avoid their legal obligation have made a very serious allegations against the workmen.

13. Before deciding the case on its merits and on preliminary issues, some of the events that took place during the pendency of these cases are necessary to be adverted, which will help for proper appreciation.

14. Before rising a conciliation these workmen have filed Writ Petitions in W.P. Nos. 13339 to 13350 and 13593 of 1984. Their prayer was for issue of direction to the second party to reinstate them and pay them full wages from the date of their alleged termination. During the pendency of these Writ Petitions a plea was raised by these workmen that the second party has not paid their wages agreed by them completely and therefore the wages for the 13 months is required to be paid to them. A learned advocate for the second party was agreed to pay the wages for each workman for the actual number of days worked as evidenced by muster roll. The learned Judge noting this admission directed the workmen to rise an Industrial dispute under Sec.

10(1) of the Act with further direction to the conciliation officer. Therefore a liberty to receive the wages for 13 months and the right to rise an Industrial dispute was accorded and Writ Petitions were dismissed.

15. Thereafter during the pendency of these disputes, the workmen have filed applications for grant of interim relief, pending disposal of these cases for the reasons stated by them. Their applications are allowed and all the workmen are getting the interim relief regularly. The workman Selva was died during the pendency and his legal representatives brought on record.

16. Though under the schedule to the reference, the burden of proof is for the second party to prove the factum of termination, due to a specific contention taken by the second party two additional issues stated at para 9 and 10 of the judgment are framed by this court. These two additional issues are shifted the burden to the first party workmen. In the event the workmen succeeds in proving these two additional issues the points referred in the schedule will automatically provides an answer. Keeping these points in view we have to appreciate the case of the first party.

17. Almost all the workmen have placed their oral evidence on Oath. On behalf of the 9th claimant his wife tendered the evidence as this workman died on 2-4-89. The tenor of the evidence both in examination-in-chief and in cross examination is identical except the persons are different workmen. Therefore the gist of the evidence is to be adverted.

18. Almost all the witnesses have unequivocally stated that they have been appointed as Khalasi's by the Divisional Personnel Officer Srikanthan on various dates referred in the chart and they have been asked to work under CTXR Nityananda, who was the Chief Train Examiner. The another Train examiners by name Muniswamy, Mohan, Yusuf, Gopal-Krishna and Alfred Devis also supervising the work of these workmen. They have made available some appointment orders, which are under dispute and they also relied on providing them train passes which used to be given to any workmen under railways, who worked more than 120 days continuously.

19. Their further case is that after they rendered a continuous service for about 13 months their services are terminated by oral instructions. Their further case is that the second party has not paid their wages from the date of their joining till they are terminated from the service.

20. In the cross examination of these witnesses the second party made several suggestions disputing the alleged appointment orders, free train passes, but they are denied all the suggestions. They are made to say that they do not have copy of their applications filed before the second party and they are fabricated documents and thereby they are making a false claim of employment.

21. The second party examined only one witness by name Sri Rangaraj, the then Assistant Personnel Officer in Bangalore Division. This witness has denied for having issued any appointment order to these workmen. He has also denied the signature found in Ex. M-1 and Ex. M2 which are in the nature of appointment orders bearing Nos. B/P/ME-CH/294/83 and B/P/294/March/83. He has also similarly denied the signature found on Ex. M-3. He has relied on two documents Ex. M-4 and Ex. M-5 a promotional orders only to show that the signature which has made on those documents are his signatures which are different from signatures found in Ex. M-1 and Ex. M-3. In fact he has stated that he came to know these facts when the first party workmen have filed a Writ Petition before the Hon'ble High Court of Karnataka.

22. It is elicited in his cross examination that a casual workmen appointed by the competent authority attains temporary status after continuously working for 120 days and thereafter he gets pass and medical benefits. Khalasi's and substitutes are recruited from open market. For Class III the age limit is 25 and for Class IV it is 28 years. There are some relaxation for SC & ST and Ex. Servicemen.

23. When we peruse the oral evidence of the workmen with MW-1, the evidence is in the nature of oath against oath. There is an element of suggestions and denials. In these circumstances it is necessary to place reliance on

document, and other circumstantial evidence. A man may lie but the circumstances will not lie.

24. The second party, except C. Rangaraj, has not examined any other witnesses whose names are stated by these workmen. The second party also not given any reasons for not examining these witnesses. Of course, it is the prerogative of the second party to choose the witnesses best suited according to them. But when the workmen specifically says the name of the persons under whom they were working it is incumbent on the part of the second party to examine those witnesses. In the event they are not able to examine them, they should give proper reason to the court for non examining them. Whenever a material witness is not examined or his evidence is withheld, then the courts can draw adverse inference against the party who has failed to place materials which was in his control and which facts are absolutely necessary to come to a correct conclusion.

25. This case is very peculiar on its own facts and circumstances as the second party made out a case that these workmen are so intelligent to manipulate the documents and then claim an employment which is unknown to the law.

26. I hasten to say that all these witnesses, when they are tendered for cross examination they appears to be a rough working individuals, not bestowed with intelligence which generally possess by the persons of their age. Therefore we have to rely on preponderance of probabilities on the basis of materials placed by both parties. As I said earlier there shall be appreciation of direct evidence, documentary evidence and circumstantial evidence.

27. Now we have to examine the documentary evidence placed by the parties and other circumstances available in this case.

28. It is undisputed that immediately after the termination/stoppage of work, the said action was questioned before the Hon'ble High Court of Karnataka in W.P.s 13339 to 13350 and 13593 of 1984. The prayer of these workmen in that writ petition was to declare that their termination was illegal and therefore they are entitled for reinstatement and back-wages. During the pendency of these writ petitions they have claimed the wages for 13 months which was not paid to them. On the undertaking made by the learned advocate for the second party the learned Judge after noting the submission has dismissed the writ petitions giving liberty to the workmen to raise an Industrial Dispute.

29. If we take the facts and circumstances of these writ petitions, the learned judge has directed the second party to pay the wages for the period they have actually worked as withholding of those wages is quite unfair. This reasoning of the learned judge is supported by the materials placed by the first party. Therefore there is no impediment to hold that these workmen did worked for the period claimed by them. If once it is accepted then it is for the second party to prove that the Hon'ble High Court has ordered to pay the wages for 13 months, only on the basis of undertaken given by the learned advocate appearing for them before the Hon'ble High Court. They also made some efforts before this tribunal that these workmen have not worked on those 13 months where the Hon'ble High Court has indirectly come to the conclusion that their contention are genuineness and they are entitled for the wages for the period they actually worked. But the second party has not placed any material except denying out right, the case of the first party. They have not cared to examine the persons named by the first party workmen who were all in their employment. It is not their case that those persons are fictitious persons and their names are wrongly stated by the first party.

30. Now coming to the documents that were made available in this case, Ex. W2 to Ex. W9 are free railway passes issued to nine workmen who are connected to this dispute. Ex. W10 is a true copy of the order DME/SBC Message Ref. DME/SBC PC No. 14/5/23 dated 15-5-84 which shows the names of all the 14 workmen and the message is that they were stopped from the work w.e.f. 15-5-84. Ex. W-11 is a true copy of the statement showing the engagement of non-rev'd substitute Khalasi's at Bayvappanahalli Depot which bears the name of these 14 workmen. Ex. W-15 is another railways pass Ex. W-16 is the order of the Hon'ble Court in the Writ Petitions referred above.



31. Now coming to the management exhibits we have Ex. M-1, Ex. M-2, Ex. M-3, the alleged appointment orders. Ex. M-6, is an office order dated 14-12-83, showing the names of the 10 workmen, who are the candidates approved and appointed as substitute Khalasi's.

32. There are some un-marked documents which are the extract from the muster roll. On a perusal of these documents they are the attendance extracts of these workmen from May 1983 to May, 1984. They bear the seal of the second party and they were duly signed by an authorised officer. For the purpose of identification these extracts has marked as court exhibits from Ex. C-1 to Ex. C-14.

33. If we peruse all these documents in the light of the pleadings and the evidence, it is conclusively proved that these workmen have worked as Khalasis as contended by them. The second party, who are in better position to tell the circumstances under which these documents came into existence have miserably failed to prove and, therefore, their statement and evidence does not attach credence of its genuineness. Therefore, there is no impediment to hold that the second party have not followed the mandatory provisions contained in chapter V-A and V-B of the Act.

34. The earliest judgement on this point, which holds the field in spite of its 39 years is State of Bombay and Others vs. Hospital Mazdoor Sabha and others reported in 1960 (1) LLJ SC 251 according to this judgment non-compliance with the provisions contained in Section 25F (b) of the Act, renders the retrenchment invalid, void and inoperative.

35. In State of India vs. Sundaramoney, 1976 (1) LLJ page 478. His Lordship, Krishna Iyer J., as he then was, held:

"Section 2(oo) is the master of the situation and the Court cannot truncate its amplitude.

"Termination... for any reason whatsoever" are the key words. Whatever the reason, every termination spells out retrenchment. So the sole question is, has the employee's service been terminated? Verbal apparel apart, the substance is decisive. A termination is where a term expires either by the active step of the master or the running out of the stipulated term. To protest the weak against the strong, this policy of comprehensive definition has been effectuated. Termination embraces, not merely the act of termination by the employer, but the fact of termination, however, produced. May be, the present may be a hard case....

"Retrenchment" is no longer terra incognita but area covered by an expansive definition. It means, "to end, conclude, cease" in the present case, the employment ceased concluded ended on the expiration of nine days automatically, may be, but cessation all the same. To write into the order of appointment, the date of termination confers no moksha from S. 25F(b) is inferable from the provision to S. 25F(1). True, the section speaks of retrenchment by the employer and it is urged, that some act of volition by the employer to bring about the termination is essential to attract S. 25F and automatic extinguishment of service by effluxion of time cannot be sufficient [Rex vs. Secretary of State, (1973) (2) A.P.R. 103].

Reinstatement is the necessary relief. In the particular facts and circumstances of this case, the respondent shall be put back where he left off but his new salary would draw where he to be appointed in the same post de novo. As regards his emoluments, he will have to pursue other remedies, if any.

36. Later Judgments on his point have followed the judgments rendered earlier on this issue.

37. In view of the facts and circumstances discussed above, the first additional issue held in the affirmative and the second additional issue held in the negative. Consequent to

these findings the schedule to the points of reference is to be held against the second party. Therefore the second party are not justified in terminating the services of these workmen.

38. In the result I make the following order.

#### ORDER

The second party are not justified in terminating the services of the workmen who are involved in respective cases. Therefore the termination is set aside. Since the second party is also found not following the mandatory provisions contained under Sec. 25F of the Act, the workmen are eligible for reinstatement, continuity of service and backwages. Since they have reached age which made them ineligible for the appointment, for the purpose of this case their age shall be taken on the date they have first worked and they shall be provided a suitable employment in accordance with rules governing the second party.

39. As it relates to the workman Selvan in C.R. No. 142/87 the legal representatives are represents him due to his death on 2-4-1989. The order of reinstatement in his case is not possible. He has left his wife a son and a daughter. The benefit of back wages shall be paid in equal proportion to the wife and children. If the children are minor the amounts shall be deposited in a scheduled bank making their mother as guardian. Any one of the member shall be appointed to a suitable post on compassionate grounds.

40. The second party are entitled to make necessary deductions for the money paid by them towards wages for 13 months and interim relief that they are paying to the first party throughout.

(Dictated to the stenographer, transcribed by her, corrected and signed by me on 1st March, 1999).

JUSTICE R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999

का. आ. 890 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ ट्रान्स्वाकोर के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार लेबर कोर्ट कोजार्हिकोडे के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—12012(116)/88 डी III ( ए )]

सनतान, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th March, 1999

S.O. 890.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Labour Court, Kozhikode as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Travancore and their workman, which was received by the Central Government on 10-03-1999.

[No. L-12012/116/88. D.III(A)]

SANATAN, Desk Officer

## ANNEXURE

IN THE LABOUR COURT, KOZHIKODE,  
KERALA STATE

Dated this the 14th day of December, 1998

PRESENT:—

Shri P. D. Barkath Ali, B.Sc., LL.B., Presiding  
Officer.

I.D. (C) No. 70/88

BETWEEN

The Regional Manager,  
State Bank of Travancore,  
Zonal Office,  
P.B. No. 25, Calicut-1. . . Management

AND

Sri Madhudarsanarajan,  
Kunnath House,  
Varavoor P.O.,  
(Vadakkancherry),  
Trichur, Kerala. . . Workman.

REPRESENTATIONS:—

Sri. K. P. Damodaran Nambiar, Calicut—Advo-  
cate—For Management.Sri. K. M. Suresh Chandran, Advocate, Calicut—  
For Workman.

## AWARD

This is an industrial dispute between the management of M/s. State Bank of Travancore and its workman Sri Madhudarsanarajan regarding the justifiability of the dismissal of the workman from service by the management which is referred for adjudication to this court by the Ministry of Labour, Government of India by Order No. L-12012(116)88-D.III(A) dated November 10, 1988.

2. The material averments in the claim statement of the workman, in brief, are these:—The workman was employed as a Peon in the main branch of the management bank at Trichur. He was served with a charge-memo on September 4, 1986 alleging that he assisted two persons by name Shri P. D. Xavier and Sri. P. D. Babu to open a Savings Bank Account in a fictitious name and enabled them to forge the signature of another account holder Smt. P. K. Prabhavathy, that he altered the figure 1000 written under the deposit column and balance scheme in the Savings Bank Account No. 6373 opened by the aforesaid persons by prefixing the number 9 to the figure 1000 as a result of which the above said persons were able to withdraw a sum of Rs. 25000 on 24-1-1983 and Rs. 56000 on 25-1-1983 thereby causing a loss of Rs. 80000 to the bank. He was further charged to the effect that out of the illegal gains obtained by him he closed 3 loans and lent money to 5 persons and that also destroyed the voucher for the remittance of Rs. 1000 so as to destroy the evidence of falsification of accounts and that thereby committed the misconduct as envisaged in paragraph 19 5. (b) (d) (T) (I) of the Bipartite settlement of 1966. He was suspended from service on

March 9, 1983. Sri. M. Valsalan, the Manager of the Palakkad Branch of the bank was appointed as an Enquiry Officer to conduct a domestic enquiry into the charges levelled against the workman. Six witnesses were examined on the side of the management and two witnesses on the side of the workman. The management produced 12 documents and the workman produced 2 documents. The Enquiry Officer found that the charges levelled against the workman is proved. On the basis of the report of the Enquiry Officer the management dismissed the workman from service on March 2, 1988. The Enquiry Officer did not conduct the enquiry properly. He has not complied with the principles of natural justice. The evidence of the Enquiry Officer are perverse. There was no evidence to prove the charges levelled against the workman. The Enquiry Officer should not have believed the evidence of Sub Inspector of Police and should not have accepted the alleged confession statement of the workman. The delay in framing the charges was not explained by the management. Therefore an award may be passed directing the management to reinstate the workman in service with backwages, continuity of service and other attendant benefits.

3. The management in their statement contended thus:—It is true that the workman was employed as a Peon in the main branch of the management bank at Trichur. On January 14, 1983 a Saving Bank Account No. 6373 in the name of one P. K. Vijayan was opened in the Trichur Main Branch of the bank on depositing a sum of Rs. 1000. A sum of Rs. 25000 was withdrawn from the deposit on January 24, 1983 and a further sum of Rs. 56000 on January 25, 1983. The withdrawals were made possible by adding the figure '9' before the sum of Rs. 1000 in the Savings Bank Account Ledger so as to make it appear that there was 91000 to the credit of the account holder. The fraud was noticed on February 22, 1983 at the time of balancing the monthly account. Matter was reported to the Police and the Police has charged a case under Section 420 of Indian Penal Code. They arrested the workman and recovered from his house considerable amount on February 28, 1983. Therefore he was placed under suspension from March 9, 1983 onwards. Thereafter the charges were levelled against the workman and a charge-memo was served on him on September 4, 1986. As his explanation was found not satisfactory Sri M. Valsalan, Manager of the Branch of the management bank at Palakkad was appointed as the Enquiry Officer to conduct a domestic enquiry into the charges levelled against the workman. The Enquiry Officer found that the charges levelled against the workman are proved. Accepting the report of the Enquiry Officer, the workman was dismissed from service. The Enquiry Officer has conducted the enquiry fairly and properly. He has complied with the principles of natural justice. As the relevant records were seized by the Police, charges could not be framed against the accused earlier. Sufficient opportunity was given to the workman to cross-examine the witnesses of management and to adduce evidence on his behalf. If it is found that the domestic enquiry is not valid, management may be given an opportunity to adduce evidence to prove the charges levelled against the workman. The punishment of dismissal of the

workman, is proportionate to the gravity of the misconducts proved. Therefore an award may be passed rejecting the claim of the workman.

4. As the workman disputed the validity of the domestic enquiry conducted, a preliminary point was raised regarding the same and MW1 and WW1 were examined and Exts. M1 to M5 were marked. This court by order dated April 17, 1989 found the domestic enquiry conducted is valid and proper. However this court found that the findings of the Enquiry Officer are perverse and directed the management to reinstate the workman with backwages, continuity of service and other attendant benefits by award dated June 15, 1989. The award was confirmed by the High Court by Judgment in O.P. 8375/89 V dated March 3, 1994. In Writ Appeal No. 767/1994 B by judgment dated August 4, 1998 while confirming the findings of the court regarding the validity of the domestic enquiry conducted, the High Court has set aside the award holding that the finding of this court regarding the perversity of the findings of the Enquiry Officer is not correct and remanded the case to this court for considering afresh the question regarding the perversity of the findings of the enquiry Officer and also regarding the punishment. After remand no fresh evidence was adduced.

5. The following points arise for consideration after remand:—

- (1) Whether the findings of the Enquiry Officer are perverse?
- (2) If not, whether the punishment of dismissal of the workman from service is disproportionate to the gravity of the misconducts proved?
- (3) If so, what is the proper punishment?

6. Point No. 1 :—The first question for consideration is whether the findings of the Enquiry Officer are perverse. In other words, the question is whether the finding of the Enquiry Officer are supported by legally

acceptable evidence. The following are the charges levelled against the workman as revealed from the memo of charges served on the workman.

- (i) you assisted two outsiders Sri. P. D. Babu, Pallipurathu House, Moorkanikkara, Trichur and Sri. F. D. Xavier, opening the Savings Bank Account No. 6373 with our Trichur (Main) Branch on 14-1-1983 by the former under fictitious name and address namely Sri P. K. Vijayan, Plassery House, Ollur Trichur with an initial deposit of Rs. 1000. You also enable the outsiders to forge the signature of Smt. P. K. Prabhavathy, account holder of the S. B. Account No. 6299 in the introduction column on the account opening form submitted by the said Sri. P. D. Babu to give a fraudulent impression that the account was duly introduced by the account holder of S. B. Account No. 6299 viz. Smt. Prabhavathy.
- (ii) You fraudulently altered the figure '1000' written under the 'deposit' column and 'balance' column in the Savings Bank Account No. 6373 opened as aforesaid in the fictitious name of Sri P. K. Vijayan, by prefixing the number '9' to '1000', causing it to appear as '91000' with a view to facilitating fraudulent withdrawals of Rs. 25000 on 24-1-1983 and Rs. 56000 on 25-1-1983 thereby expressing the bank to monetary loss of Rs. 80,000.
- (iii) Out of the illegal gains obtained by you by defrauding the bank as narrated in sub-para (i) & (ii) above, you closed the following 3 loan accounts spending in aggregate Rs. 5,513.

Number of loan account and branch	Limit	In the name of	Amount remitted for closing
(i) AGL. 62/82 Trichur	Rs. Rs. 1700/-	M. Moidu	Rs. 1832.00
(ii) AGL 452/82 Rrichur	ADS Rs. 1400/-	K.P. Jacob	Rs. 1516.00
(iii) AGL 453/92 TRICHUR	ADS Rs. 2000-	Madhudarrsanarajan	Rs. 2165.00
Total			Rs. 5513.00

Further you lent to the following members of staff attached to Trichur Main Branch a total amount of Rs. 3325.

Sl. No.	Name of the Official	Designation	Amount lent.
(i)	Smt. K. Droupathy	Officer	Rs. 1,575.00
(ii)	Sri M. Unnikrishnan	Head Clerk	200.00
(iii)	Sri P. Madhavan Nair	Bill Collector	350.00
(iv)	Sri R. Sathyaseelan	Peon	300.00
(v)	Sri K.M. Venu	Part-time Sweeper	900.00
Total			Rs. 3,325.00

- (iv) Further you fraudulently removed from the records of the branch and destroyed the voucher representing the initial remittance of Rs. 1000 made for opening the fictitious account mentioned above, with a view to destroying evidence of your fraudulent acts".
2. The aforesaid circumstances and facts would show that you have committed gross-misconduct under para 19.5 (b)(d)(1) and (1) of the Bipartite Settlement of 1966 as amended till date rendering you liable for punishment under para 19(6) thereof".
7. PW1 to PW6 were examined and Exts. PEX 1 to PEX 12 were marked on the side of the management and DW1 and DW2 were examined by the workman before the Enquiry Officer. PW1 was Mrs. Droupathy, the then Additional Officer of the bank. She testified before the Enquiry Officer that a fraud was committed in the account No. C 6373 during January 1983 by altering the figures 1000 to 91000 in the ledger, that there was difference in the ink between the figure 1000 and 9 and that she borrowed Rs. 1575 from the workman in the first week of February 1983. She further stated before the Enquiry Officer that the corresponding deposit voucher was found missing, that it was the workman who stitched and sorted the voucher and that the workman had the opportunity to remove that voucher. PW2 was Mr. M. Unnikrishnan, the then Special Assistant of the bank. He stated before the Enquiry Officer that he borrowed Rs. 200 from the worker during the first or second week of February 1983 to purchase a coir mattress which was brought to the bank by a person. PW3 was Mr. Sathyaseelan, a Peon of the bank who has sworn before the Enquiry Officer that he has also borrowed Rs. 300 from the workman just before police started investigation. PW4 was Sri. K. N. Venu, a part-time Sweeper of the bank who has also borrowed Rs. 900 from the workman during the first week of February 1983.
8. PW5 was the then Sub-Inspector of Police, Trichur East who investigated criminal case. He arrested the workman as well as one Mr. Babu and one Xavier who opened the account and withdrew the amount from the bank, and recorded their confession statements. On the basis of the information given by the workman, PW5 searched the house of workman and recovered Rs. 25307 and other articles purchased by the workman with the amount given to him by Mr. Babu and Xavier. PW3 testified before the Enquiry Officer that the accused Xavier was the close friend of workman and that accused Babu was the brother of Xavier and that hand-writing in the account opening form in the name of Sri. P. K. Vijayan is of Sri Babu as reported by the Hand-writing Expert Forensic Science Laboratory, Trivandrum. PW6 was Sri. V. K. Neelakandan, a clerk of the bank. He joined the service of the management bank on December 1, 1983. Prior to that he was running a private finance company by name Bhadratha Financiers, Varavoor. The mother of workman was a partner of the said firm. PW6 has sworn before the Enquiry Officer that the workman deposited in his firm Rs. 1000 each in the names of Sri T. C. Ansu and Sri V. Sankaranara-

yanan in 1983 and that the workman also opened an account in the name of his wife for Rs. 1800 for the purpose of granting loan to one Sri V. V. Krishnalyer. The Enquiry Officer believed the evidence of the management and found the workman guilty of the charges levelled against him. The Enquiry Officer mainly relied on the evidence of PW5, the Sub-Inspector of Police and the Confession statement made by the workman to PW5, copy of which was marked as Ext. PEX 6-2. PW5 has also prepared a Mahassar regarding the recovery of the amount and the other articles from the house of the workman, the copy of which was marked as Ext. PEX 6-1. The counsel for the workman argued that the confession statement of the workman and the Mahassar prepared by PW5 are not admissible in evidence in view of "the prohibition under" Section 26 of the Indian Evidence Act. The above contention of the workman has been rejected by the High Court in the Writ Appeal. The High Court has held that a confession or admission of guilt made by a person accused of an offence while in the custody of a Police Officer or a statement under Section 161 Criminal Procedure Code is acceptable in a disciplinary proceedings and there is no illegality in relying on such statements. Therefore, the evidence of PW5, the confession statement made by the workman before PW5 and the Mahassar prepared by PW5 were admissible in evidence before the Enquiry Officer. The question however is whether the evidence of PW5, the confession statement of workman and the Mahassar marked as Ext. PEX-6-1 and PEX 6-2 before the Enquiry Officer are worthy of acceptance. For the following reasons I am inclined to hold that the evidence of PW5, the confession statement of the workman and the Mahassar prepared by PW5 are worthy of acceptance and the Enquiry Officer is justified in relying on the same. The workman has no case either in pleadings or in evidence that his confession statement was recorded by PW5 under duress or that PW5 coerced him in any other manner to extract such a confession. Workman has also no case that no such confession statement was given by him to PW5. Though sufficient opportunity was granted by the Enquiry Officer to the workman to cross-examine PW5, he did not cross-examine PW5. If actually the workman did not make any such a confession statement to the PW5 or if actually PW5 has coerced the workman he could have cross-examined PW5 on that aspect. The evidence of PW5 regarding confession is not vitiated by any improbabilities or any other evidence in the case. The evidence regarding the loans taken by PWs 1 to 4, from the workman and the recovery of Rs. 25,307 from the house of the workman leads support to the confession recorded by PW5. Having regard to all these facts and circumstances I am inclined to hold that the confession statement made by the workman before PW5 and the Mahassar prepared by PW5, the copies of which were marked as Ext. PEX 6-2 and PEX 6-1 respectively and also the evidence of PW5 can be safely accepted and acted upon.

9. A reading of Ext. PEX 6-2 shows that it was the workman who connived with Sri Xavier and Sri Babu and opened the account by depositing Rs. 1000 in the name of Sri. P. K. Vijayan, that he helped Sri Xavier and Sri Babu to forge the signature of another account holder Smt. P. K. Prabhavathy in the introducing

column of the account open form and that the workman altered the figure 1000 to 91000 in the ledger of the bank which enabled Sri Babu to withdraw Rs. 80000 from the bank. He further admitted in his confession statement that out of the amount withdrawn he has taken Rs. 50000 and closed the loan taken by him and also lent amounts to PW1, PW2, PW3, PW4 and one Madhavan Nair. He further admitted the deposit of Rs. 1800 and Rs. 2000 in the firm of PW6. He has stated in his confession statement that he has purchased some other articles and that the balance amount he has kept in his house. These amount and some other articles were recovered from the house of workman by PW5 for which he has prepared the Mahassar, copy of which was marked as Ext. PEX 6-1 before the Enquiry Officer. Having regard to all these facts and circumstances I am inclined to hold that the Enquiry Officer is perfectly justified in believing the evidence of PWs 1 to 6 and accepting Ext. PEX 1 to 12 hold that charges Nos. 1(i) to 1(iii) against the workman are proved.

10. Charge No. 1(iv) is that the workman destroyed the voucher showing the initial remittance of Rs. 1000. Nothing has been mentioned about the same in his confession statement. PW1 would only say that the workman was the person who stitched and sorted the voucher and that therefore he had opportunity to destroy that voucher. But on the basis of the evidence of PW1 alone it cannot be said that workman destroyed that voucher. There was no witness who had actually seen the workman destroying the voucher. Therefore, the Enquiry Officer is not correct in coming to the conclusion that the workman has destroyed the relevant voucher. That being so, it has to be held that the charge No. 1 (iv) against the workman is not proved. It follows that the finding of the Enquiry Officer on charge No. 1(iv) is perverse and has to be set aside. Taking into account all these facts and circumstances, I hold that the charges 1(i) to 1(iii) are proved and that the findings of the Enquiry Officer in respect of those charges are not perverse. Charge No. 1(iv) is not proved and therefore the finding of the Enquiry Officer in respect of that charge is perverse and has to be set aside.

11. Point No. 3.—The next question to be considered is whether the punishment of dismissal of the workman by the management is disproportionate to the gravity of the misconducts proved. The workman has committed a grave misconduct of falsifying the documents of the bank and misappropriating to the tune of Rs. 80,000. In such a case the punishment of dismissal cannot be said to be excessive or harsh as held in *D. Padmanabhudu vs. Bank of India* and another (1995(1) LLJ 1076 Karnataka). Therefore I hold that the punishment of dismissal if the workman from service by the management is just and proper in the facts and circumstances of the case and is not disproportionate to the gravity of the misconducts proved. It follows that the workman is not entitled to any of the reliefs prayed for and an award has to be passed rejecting the claim of the workman.

12. In the result, an award is passed rejecting the claim of the workman.

Dictated to the Confidential Assistant, transcribed by him, revised, corrected and passed by me on the 14th day of December, 1998.

P. O. BARKATH ALI, Presiding Officer.

#### APPENDIX

Witnesses examined on the side of the Workman :—

WW1.—Madhudarsanarajan.

Witnesses examined on the side of the Management :—

MW1.—M. Valsalan.

Documents marked on the side of the Workman :—

NIL.

Documents marked on the side of the Management :—

Ext. M1.—Enquiry Register.

Ext. M2.—do-

Ext. M3.—Enquiry Report.

Ext. M4.—Copy of charge memo dt. 4-9-86.

Ext. M5.—Reply dt. 6-3-1987 by the delinquent to the letter dt. 27-2-1987.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1999

का. आ. 891:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ मद्रास लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-03-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12011/28/96-आई. आर. (बी-1)]  
सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th March, 1999

S.O. 891.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Madras Ltd., Calcutta and their workman, which was received by the Central Government on the 11-03-1999.

[No. L-12011/28/96-IR (B-I)]

SANATAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 7 of 1998

**Parties :**

Employers in relation to the management of  
Bank of Madura Ltd., Calcutta.

AND

Their Workmen

**Present :**

Mr. Justice A. K. Chakravarty, Presiding Officer.

**Appearance :**

On behalf of Management : Mr. A. Roy, Advocate with Mr. J. Dasgupta, Advocate.

On behalf of Workman : Mr. A. C. Chattopadhyay, Advocate with Mr. N. Rakshit, Advocate.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Banking

**AWARD**

By Order No. L-12011/28/96-IR(B-1) dated 3-2-1998 the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Bank of Madura in not regularising S/Shri Sanat Khan (2) Nani Gopal Nath (3) Dilip Kr. Saha (4) P. Subramaniam (5) Biman Bose as Special Assistants, is justified? If not to what relief the workmen are entitled?"

2. When the case is called out today, management is represented by its learned Advocates. None appears for the sponsoring union, namely, Bank of Madura Employees Association. It appears from record that sponsoring union filed an application on 12-11-1998 stating that it is no longer interested to proceed with the matter any further as four of the concerned workmen under reference, namely, Nani Gopal Nath, Dilip Kr. Saha, P. Subramaniam and Biman Bose have submitted their resignations to the sponsoring union and such resignations being accepted, they have ceased to remain as members of the said union. Regarding the other concerned workman, namely, Sanat Khan, it is alleged that he had already been regularised in service and accordingly the sponsoring union prayed for disposal of the matter by passing a "No Dispute" Award. It further appears from record that another union, namely, Bank of Madura Employees Union prayed for contesting the matter on behalf of the aforesaid four concerned workmen by getting itself added as a party in this reference. This union prayed for corrigendum of the reference but that prayer was rejected by the Central Government. The aforesaid application of the Bank of Madura Employees Union being not supported by any application of the four concerned workmen that they have become members of this union and nothing also having been produced to show prima facie that these workmen have become members of the Bank of Madura Employees Union that this union cannot be added as a party in this reference. The union's application for impleading it as a party in this reference accordingly stands rejected.

3. In the aforesaid circumstances, the sponsoring union having already prayed for disposal of the matter by passing a "No Dispute" Award and no further step on their behalf having been taken today, this Tribunal has no other alternative but to pass a "No Dispute" Award in the absence of any material on record to come to any finding in respect of the issue under reference, excepting Sanat Khan whose service has admittedly been regularised already.

4. A "No Dispute" Award is accordingly passed.

This is my Award.

A. K. CHAKRAVARTY, Presiding Officer  
Dated, Calcutta,

The 1st March, 1999.

नई दिल्ली 1 मार्च, 1999

का.आ. 892:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. रमेश ट्रांसपोर्ट कं. के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार [औद्योगिक अधिकरण, सं.-1, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-3-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-31011/2/96-आई.आर. (विविध)]  
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st March, 1999

S.O. 892.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (1 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Ramesh Transport Co. and their workmen, which was received by the Central Government on 1-3-99.

[No. L-31011/2/96-IR(Misc.)]  
B. M. DAVID, Desk Officer

**ANNEXURE**

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

**PRESENT :**

Shri Justice C. V. Govardhan, Presiding Officer.

Reference CGIT No. 45 of 1996

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of M/s.  
Ramesh Transport Company.

AND

Their Workmen.

**APPEARANCES :**

For the Management : Shri Jambhalikar, Advocate.

For the Workmen : Shri S. R. Wagh, Advocate.

STATE : Maharashtra.

Mumbai, dated the 12th day of February, 1999

## AWARD

Versus.

1. The Central Government has referred the following dispute between the management of M/s. Ramesh Transport Company and Transport and Dock Workers' Union for adjudication by this tribunal:

"Whether the action of the management of M/s. Ramesh Transport Company in terminating the services of S/Shri Narichandra V. Kashid, Hiralal K. Gupta, Gangadhar B. Gawade and Shri Pratap P. Jadhav w.e.f. 28-4-1995 is justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

2. Subsequent to the filing of claim statement and written statement by the respective parties, the matter is posted today for hearing. The Union filed an application today stating that the Union does not want to proceed further in the reference and withdraws the same. The Union has prayed for an award to be passed accordingly. This application has been signed by the advocate for the Union also. The advocate for the Company has made an endorsement no objection an signed the same. This application is recorded. The Union is permitted to withdraw the reference and an award is passed accordingly.

C. V. GOVARDHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1999

का.आ. —893. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिनियम चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-1-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-12012/349/95-आई.आर.-बी-11]  
सी. गंगाधरन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th March, 1999

S.O. 893.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workman which was received by the Central Government on 21-1-1999.

[No. L-12012/349/95-IR(B-II)]  
C. GANGADHARAN, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI B. L. JATAV, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
CHANDIGARH

Case No. I.D. 103/97

Sh. B. K. Munjal,  
House No. 186-A GG-I, Vikasपुरी,  
New Delhi-18. ... Petitioner

Regional Manager,  
Central Bank of India,  
Rohtak

... Respondent.

## APPEARANCE :

For the workman : None.

For the management : Shri Yogesh Jain.

## AWARD

The Central Govt. vide Notification No. L-12012/349/95-I.R. (B. 2) dated 30th December, 1996 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Sh. B. K. Munjal is just fair and legal. If not what relief, he is entitled to and from what date?"

2. Today the case was fixed for filling of claim statement by the workman. None appeared on behalf of the workman. The rep. appearing on behalf of the management made the following statement :—

"The matter under reference is pending before Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Delhi for adjudication for the same relief claimed by the workman in this reference vide I.D. 77/97. This reference may be returned to the Ministry for appropriate action."

3. In view of the above, since the reference claiming same relief is pending before CGIT-cum-LC, Delhi, this reference is returned to the Ministry accordingly. Appropriate Govt. be informed.  
Chandigarh,

11-11-1998

B. L. JATAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1999

का.आ. 894.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिनियम, भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-22012/77/94-आई.आर. (बी-11)]  
बी.के. राजन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th March, 1999

S.O. 894.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal Bhubaneswar as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 5-3-99.

[No. L-22012/77/94-IR (C-II)]  
V. K. RAJAN, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

Present :

Sri H. Mohapatra, O.S.J.S. (Sr. Branch), Presiding Officer, Industrial Tribunal, Orissa, Bhubaneswar.

#### INDUSTRIAL DISPUTE CASE NO. 40 OF 1994 (CENTRAL)

Dated, Bhubaneswar, the 20th February, 1999

#### BETWEEN

The management of Food Corporation of India,  
Kacheri Road, Balasore, Orissa.

— First party-  
management.

#### AND

Their workman Sri Narayan Roul, represented  
through PCI Employees' Union At : Sanab-  
bay Bhawan, Janpath. Bhubaneswar.

— Second Party  
workman.

Appearances :

Sri Prasant Routray, Advocate—For the First  
Party management.

Sri Ajit Kumar Das, Advocate.—For the Second  
party-workman.

#### AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred upon them by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) have referred the following dispute for adjudication by this Tribunal vide Order No. L-22012/77/94-IR (C-II) dated 3-8-94 :

“Whether the action of the management of F.C.I. Food Storage Depot, Rupsa in not regularising the services of Shri Narayan Roul and in not paying him wages at par with the monthly rated employees of the organisation, rather terminating his services during the pendency of the conciliation proceedings is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?”

2. The case of the second party briefly stated is that he was appointed as a Sweeper in the Food Storage Depot of the Food Corporation of India, Rupsa with effect from 1-5-87 and was being paid Rs. 50/- per month. In the year 1988 on the request of the Sr. Regional Manager, F.C.I., Bhubaneswar the District Manager, F.C.I. Bhubaneswar furnished a list of casual labourers wherein the name of the second party found place. While six such casual workers were made regular the second party was ignored. The second party made a representation for consideration of his case to the Sr. Regional Manager and remanded him from time to time for his regular absorption. In August, 1991 the second party represented for enhancement of his wages to Rs. 25/- per day. He was neither regularised nor paid the enhanced wages. As such, the second party raised an industrial dispute before the A.L.C. (C), Bhubaneswar on 18-9-92 through the union for regularisation of his service and the A.L.C. on 3-11-92 directed maintenance of status quo till the matter was disposed of. On the said date the representative of the management admitted about the engagement of the second party as a casual labourer. The Asstt. Manager of the Depot did not pay the salary to the workman for the month of October '92. When the second party produced the letter of the A.L.C. Bhubaneswar dtd. 21-10-92 for maintenance of status quo he was informed that his services have been terminated w.e.f. 17-10-92 and was offered a sum of Rs. 177/- on account of retrenchment compensation. It is pointed out that the District Manager, F.C.I. who attended the conciliation proceedings on 3-11-92 had also admitted about the engagement of the second party in the Depot. According to the second party he rendered service for more than five and half years and consequently he could not be retrenched while other employees were regularised. According to the second party, the termination of his service during pendency of the conciliation on the flimsy pretext of ban of temporary appointment is illegal. He also claimed the differential wages at par with the regular employees from 1-5-87 to September, 1992 and back wages from October, 1992 till the date of reinstatement.

3. The management filed written statement admitting about the engagement of the second party as a Part-time temporary Sweeper w.e.f. 1-5-87. According to him, the engagement was for about an hour a day. Some casual workman engaged prior to 2-5-86 were regularised and the services of the second party were terminated on 17-10-92 before receipt of the letter from the Conciliation Officer as the second party was not available in the Depot since 17-10-92. In order to support the action of termination the first party-management has relied on a Circular No. 28 of 1986. It is pleaded that mere continuance of an incumbent in casual work does not give him a right for absorption on regular job. Admitting about the submission of a list of casual labourers which included the name of the second party, the management also admitted that all the five remaining workmen were regularised. The submission of representation by the second party for regularisation and enhancement of wages on 27-6-91 and the raising of an industrial dispute before the A.L.C. (C) for regularisation are also admitted.



4. On the basis of the pleadings of the parties, the following issues are settled :—

#### ISSUES

1. Whether Sri Narayan Roul, Sweeper was working for certain hours being as temporary employee under the first party management and was getting Rs. 50/- per month?
2. Whether the service of Sri Narayan Roul requires to be regularised in a permanent cadre?
- Whether pay of Rs. 50/- per month payable to Narayan Roul requires upward revision?
4. Whether the termination of service of Narayan Roul during pendency of the conciliation proceeding is justified, if not, to what relief he is entitled?

#### ISSUE No. 1 :

5. Though no document is proved in support of the engagement of the second party as a Sweeper, the parties in their pleadings and evidence are in agreement that the second party was engaged as a Sweeper on temporary basis with effect from 1-5-87 on a monthly wage of Rs. 50/-. It is elicited in the evidence of M.W. No. 1 that the establishment of the first party at Rupsa where the second party was employed was operating in a building having a plinth area of 4000 sq. ft. and the engagement of the second party was hardly for an hour for sweeping the floors. It is further in the evidence that the second party was being paid from the contingent fund. M.W. No. 1 has proved the circular dtd. 2-5-86 as Ext. B which prohibited employment of casual/daily rated and part-time in the offices/depots of the Corporation which is sought to be utilised as the ground for terminating the services of the second party. Ext. D is the letter issued in pursuance of Ext. B wherein the District Manager, F.C.I. Balasore intimated the Assistant Manager to retrench the second party from service on payment of retrenchment compensation under intimation to him. The Asstt. Manager, F.C.I., Rupsa was further directed to give effect to the order of retrenchment from 17-10-92. The version of the second-party that he also worked as a Water Carrier during his incumbency as Sweeper is stoutly refuted by the District Manager, F.C.I. who is examined as M.W. No. 1 in this case. From the set of correspondences referred to above, it is clear that the second party was engaged on temporary basis as a part-time Sweeper on payment of Rs. 50/- per month. The workman has produced Ext. 1 series containing orders dated 6-2-91, 10-2-91 and 14-2-91 in support of his plea that his services were being utilised as a Watchman in addition to his duty as a Sweeper and that such engagement was for twelve hours. These three orders pertain to the provision of additional security staff in the railway siding at Rupsa during night hours. These sporadic engagement over a small span of time under exigencies of service would not clothe the second party with a right to claim the status of a regular employee, on the other hand, the fact that the second party was paid a sum of Rs. 50/- towards his remuneration probablis the case of the management that

his engagement was on part-time basis. In the facts and circumstances, despite absence of any order of appointment describing the second party as a Sweeper, I am inclined to accept the version of the management that the second party was a part-time Sweeper in the establishment of the first party appointed on temporary basis on a monthly remuneration of Rs. 50.

Issue No. 1 is thus answered in favour of the first party-management.

#### ISSUE NOS. 2 & 3 :

6. The second party has raised a claim for his regularisation in service. He has proved two of his representations as Exts. 2 and 3. Ext. 2 which is a representation dtd. 14-4-89 addressed to the Sr. Regional Manager F.C.I. reveals that his services were utilised in sweeping the office rooms and four verandahs of the two sheds. In the subsequent representation dtd. 27-6-90 (Ext. 3) he mentioned about the regularisation of some of the Watchmen and other staff and prayed for his regularisation in service. It is in the evidence of the District Manager examined as M.W. No. 1 that there is no post of Sweeper in the establishment in which the second party was engaged on casual basis, his remuneration being drawn in vouchers. Having in view the nature of job performed by the second party which extended for an hour a day, the claim of regularisation in Class-IV posts appears absurd. Though the second party has produced a set of documents, marked Ext. 1 series pertaining to three dates, i.e., 6-2-91, 10-2-91 and 14-2-91 wherein his services were utilised as Watchman, there is no whisper in the pleadings as to the circumstances under which such engagement took place. While in the oral evidence the second party claimed to be working as a Water Carrier in addition to his duty as Sweeper he produced Ext. 1 series which reveals that on three occasions his services were taken alongwith others for doing watch and ward duty in the Rupsa railway siding. These sporadic engagements in a short span of time, it is needless to reiterate, do not clothe the second party with any right to regularisation as Watchman or as an employee of Class-IV cadre of the Corporation. The second party-workman has referred to a list of daily rated workers as Ext. 6, wherein he was shown in the records to be working as a Sweeper under the signature of the District Manager of the F.C.I. Enlisting the second party as a daily rated worker does not in any way support his claim of regularisation in service as he was a part-time employee predominantly doing the work of sweeping. It transpires in the evidence adduced by the workman that after disengagement of the second party persons were engaged as Sweeper who were paid Rs. 25 per day. Surprisingly the workman has not taken such a plea in his statement of claims nor has he cross-examined M.W. No. 1 on this score. No parity is sought to be established by the workman as to how the work of sweeping in other branches and depots of the Corporation is being managed and what is the remuneration paid to such Sweepers. Even assuming for the sake of argument that the job of the second party was part-time, the remuneration of Rs. 50 being paid by a public sector organisation to a workman for the odd job of sweeping

ment brings about a relationship between the management and the workman and a string is attached to the relationship which obliges the second party to be dutiful. Keeping in view the present day cost of living, the nature of job and the expectations of the employer, the paltry sum of Rs. 50 as monthly wage seems wholly unreasonable. The second party seems to have made a grievance with regard to the paltry sum of remuneration as early as on 14-4-89 as per Ext. 2 which is reiterated in his subsequent representation, Ext. D dtd. 27-6-91 addressed to the Senior Regional Manager. As may be evident in the minutes of conciliation, the District Manager, Balasore who represented the management pleaded his helplessness to rationalise the wages of the Sweeper on the ground of want of provision. The management relied on a decision of the Central Government Industrial Tribunal No. 11 in a reference case No. 25 of 1992 which was a reference of the dispute between the Food Corporation of India on the one hand and the workman on the other who was a casual workman engaged in the job of cleaning and sweeping of the floors of the office of the management of Hazaribag. It is revealed in the judgment of the case that the workman who was appointed on 2-1-88 in the job was initially paid a consolidated wage of Rs. 150 with effect from 2-1-88 and within three months his wage was revised to Rs. 250 per month. If a revision could take effect at Hazaribag, it is not understood why the management during conciliation proceedings pleaded absence of provision for revision of wages of the second party. Hazaribag of the neighbouring State of Bihar hardly presents any divergence in socio-economic conditions to justify such low rate of wages for a similar class of employee at Rupsa. Adopting the industry-cum-region principles, I therefore, hold that the second party is entitled to Rs. 250 as wages per month which is a bare subsistence wage. Despite the fact that the job performed by the second party as a Sweeper is part-time a remuneration of Rs. 250 per month seems just and fair and I am inclined to hold that the second party is entitled to such rate of remuneration with effect from 14-4-89, the date when he made the grievance in writing.

The industrial dispute was raised by the union for regularisation of the second party-workman on the basis of a representation dtd. 18-9-92. The copy of the representation is however not forthcoming on record. It is transparent in the copy of the minutes of the conciliation proceedings pertaining to the industrial dispute raised by the union for regularisation of the service of the second party that the management did not agree to the regularisation of the service as second party had joined the organisation after 1-5-86. The demand for increase of wages to Rs. 25 per day could also not be conceded for want of provision resulting in failure of conciliation. Though it is admitted that a set of casual employees numbering six were regularised to the exclusion of the second party there seems good reasons for non-regularisation of the second party as he had joined the organisation much beyond the cut off date. The persons who were regularised are not similarly circumstances with the second party and no discrimination can be imputed to the management for non-regularisation of the service of the second party.

seems wholly unconscionable. The fact of engagement—The management cited a decision of the Supreme Court reported in AIR 1992 SC 2130 (State of Haryana & others Vrs. Piara Singh), wherein it is held that it is the domain of the executive to decide all matters of regularisation and it is the duty of the Court only to ensure that the Rule of law is maintained and the executive acts fairly and gives a fair deal to its employees consistent with the requirements of Articles 14 and 16 of the Constitution. In view of the cut-off date imposed by the management for regularisation and the belated appointment of the second party on temporary basis, the inability of the management to regularise the second party does not seem to be actuated by malafides. In such circumstances a direction for regularisation of the second party does not seem to be permissible in law. In this connection, reliance is also placed on a decision of the Supreme Court reported in AIR 1996 SC 1188 (State of U.P. Vrs. Ramashraya Yadav).

#### ISSUE NO. 4 :

7. The first party-management has come-up with a case that the second party suffered a termination of his service w.e.f. 17-10-92. In support of the pleaded retrenchment of the second party the management relied on a letter of the District Manager, addressed to the Assistant Manager, F.S.D., Rupsa wherein a specific direction was given to the Asst. Manager to effect termination of service of the second party from 17-10-92. The said retrenchment is said to have been carried out in accordance with the Circular No. 28 of 1986 dtd. 2-5-86 of the Head Office, F.C.I., New Delhi, Ext. C. It is revealed in a copy of the correspondence dtd. 30-10-92 that as the second party was not available at the depot no action could be taken in pursuance of the letter. Copy of which is marked Ext. D. In the letter Ext. C it is made clear to the District Manager that the documents regarding engagement of the second party were not traceable and as the Asst. Manager to whom Ext. D was addressed was on leave until 30-10-92, the order could not be given effect to. The version of the workman seems consistent and plausible that as the second party caused an industrial dispute being raised for improving his service conditions, the management abruptly tried to bring an end to his tenure.

It is revealed in the minutes of conciliation, Ext. 7 that the representative of the union in course of conciliation approached the Conciliation Officer on 21-10-92 apprehending retrenchment of the second party which resulted in a notice fixing the date of conciliation to 3-11-92 advising the management to maintain status quo ante. The representative of the management appeared on 3-11-92 and on that date the workman claimed before the Conciliation Officer that he was working in the F.S.D., Rupsa as usual and the representative of the management confirmed the same. The fact that the conciliation was fixed before the A.L.C. on 3-11-92 is supported in the copy of a notice marked Ext. 4. The version of the management that the services of the second party were terminated on 17-10-92 is not believable in view of the assertion made before the Statutory authority by both the parties on 3-11-92.

that the second party was in employment by that date. Ext. C, the letter addressed to the District Manager in response to the direction contained in Ext. D to retrench the second party also clearly shows that such order could not be given effect to. The plea of the management that the second party had absented himself from the job is belied in the proceedings of the enquiry where the second party admitted to be in active employment of the first party as on 3-11-92. Thus, Ext. D which contains a direction to the subordinate to terminate the services of the second party was not given effect to. Thus the second party cannot be said to have been terminated from service as deposed to by M.W. No. 1 on 17-10-92. Having regard to the contemporaneous conduct of the parties to the dispute, I am inclined to hold that the story of retrenchment as on 17-10-92 is a myth. It is unfortunate to note that a public sector undertaking resorted to falsehood and exhibited indecent haste in seeking to do away with the services of the workman when the industrial dispute was pending conciliation. The termination having been affected during pendency of conciliation of an industrial dispute where the second party was a concerned workman must be held to be void in view of the provisions of Section 33 of the Industrial Dispute Act. The termination of service by way of retrenchment is lawfully effective only on service of retrenchment notice or payment of notice pay in lieu thereof and retrenchment compensation. There is nothing on record that these statutory provisions contained in Section 25-F of the Industrial Disputes Act were complied with while dispensing with the services of the second party who had served the organisation for more than 5 years. Therefore, I hold that there has been no termination of service of the second party as claimed and the purported termination is vitiated for non-compliance of the provision of Section 25-F & 33 of the Industrial Disputes Act.

The issue No. 4 is thus answered accordingly in favour of the workman and against the management.

8. To sum-up, the termination of service of the second party-workman with effect from 17-10-92 is non est, illegal and unjustified. The second party-workman is entitled to payment of wages @ Rs. 250 (Rupees two hundred fifty only) per month with effect from 14-4-89. As such, he is entitled to the differential wages from that date and back wages from the alleged date of termination i.e., 17-10-92 until reinstatement. He is further held entitled to reinstatement.

The reference is thus answered accordingly.

Dictated & corrected by me.

H. MOHAPATRA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1999

क्रा. आ. 895.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-99 को प्राप्त हुआ था।

करण, विशाखापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-29011/23/97-आई.आर. (विविध)]

के.वी.बी. उन्नी, अवर सचिव

New Delhi, the 4th March, 1999

S.O. 895.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ms. FACOR and their workman, which was received by the Central Government on 4-3-1999.

[No. 1-29011/23/97-IR(Misc.)]

K. V. B. UNNY, Under Secy.

#### ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Sri K. Satyanand, B.Sc., LL.M., Chairman, Industrial Tribunal and Presiding Officer, Labour Court, Visakhapatnam.

I.T.I.D. (C) 23/98

Dated, 20th day of November, 1998

BETWEEN

The General Secretary,  
FACOR Worker's Union,  
C/o M/s. FACOR  
PO Sreeramnagar, Vizienegorem,  
Vizanagaram-535101

.. Workman.

AND

The General Manager,  
M/s. FACOR  
PO Sreeramnagar,  
Vizanagaram-535101

.. Management.

This dispute coming on for hearing before me in the presence of Sri T. Kemelekere Rao, Dy. Manager (Admn.) representation in person for Management. Workmen absent on perusig the material papers on record the court passed the following :

#### AWARD

Workmen absent. No representation for workmen. Reference closed passing a nil award on account of the default on the part of the workmen.

Given under my hand and seal of the court this the 20th day of November, 1998.

K. SATYANAND, Chairman

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1999

क्रा. आ. 896.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार डोक लेबर बोर्ड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-3-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-34012/9/97-आई.आर. (विविध)]

के.वी.बी. उन्नी, अवर सचिव

New Delhi, the 4th March, 1999

S.O. 896.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dock Labour Board and their workman, which was received by the Central Government on 4-3-1999.

[No. L-34012/9/97-IR(Misc.)]

K.V.B. UNNY, Under Secy

#### ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-  
LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Sri K. Satyanand, B.Sc., LL.M., Chairman, Industrial Tribunal and Presiding Officer, Labour Court, Visakhapatnam.

I.T.D. (C) 18/98

Dated : 25th day of November, 1998

#### BETWEEN

Ch. Sri Rajulu,  
C/o The Hon'ble President,  
Visakhapatnam Dock Labour Board,  
and Dock Worker's Union,  
26-15-204  
Charmakki Bhavan,  
Visakhapatnam-530001. ... Workmen.

AND

The Deputy Chairman,  
Dock Labour Board,  
Visakhapatnam-530001. ... Management.

This dispute coming for appearance, both parties called absent on perusing the material papers on record the court proceed the following :

#### AWARD

No representation for both sides today also. Reference closed passing Nil Award.

Given under my hand and seal of the court this the 25th day of November, 1998

K. SATYANAND, Chairman.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

का. घा. 897.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कोएक्सीटल मेटेनेस, बेलगाम के प्रबंधन के संबंध में निोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/6/97-आई.आर. (डीयू)]  
के. वी. बी. उन्नी, अवर सचिव

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 897.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the

industrial dispute between the employers in relation to the management of Coaxial Maintenance, Belgaum and their workman, which was received by the Central Government on 5-3-99.

[No. L-40012/6/97-IR(DU)]

K.V.B. UNNY, Under Secy.

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR  
COURT, BANGALORE

DATED 1st FEBRUARY, 1999

PRESENT :

JUSTICE R. RAMAKRISHNA,

PRESIDING OFFICER.

C. R. No. 22/98

#### I PARTY

Sri. N. K. Thandar,  
C/o. Convenor,  
Karnataka State  
Government,

#### II PARTY

Divisional Engineer  
Coaxial Maintenance  
Belgaum-590001.

Daily wage Employee Federation.  
F-11, Gajanan Complex.  
Dajibanpath.  
Hubli-580029.

#### AWARD

1. The Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2A of the section 19 of the Industrial Dispute Act, 1947 ha referred this dispute vide Order No. L-40012/6/97-IR(DU) dated 9-3-98 for adjudication on the following schedule.

#### SCHEDULE

"Whether the management of Coaxial Maintenance, Belgaum is justified in terminating the services of Shri N. K. Thandar? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. This reference is repetition of earlier reference which was registered by this tribunal in C.R. No. 251/1997.

3. In view of this fact no adjudication can be made in this case and therefore the case is closed.

(Dictated to the stenographer, transcribed by her, corrected and signed by me on 1st February, 1999.)

JUSTICE R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

Order No. L-40011/6/96-IR (DU) dated 28-1-1998.

का.आ. 898.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, त्रिवेन्द्रम के प्रबंधन के संबंधित नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोलाम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40011/6/96-आई आर (डीयू)]  
के. बी. बी. उन्नी, अवर सचिव

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 898.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kollam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chief Post Master General, Trivandrum and their workman, which was received by the Central Government on 5-3-99.

[No. L-40011/6/96-IR(DU)]  
K.V.B. UNNY, Under Secy.

## ANNEXURE

In the Court of the Industrial Tribunal, Kollam  
(Dated, this the 4th day of February, 1999)

Present :—

SRI. C. N. SASIDHARAN

INDUSTRIAL TRIBUNAL

IN

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 3/98

BETWEEN

The Chief Post Master General, Kerala Circle,  
PMG Junction, Trivandrum

(By Sri. G. S. Prakash, Advocate, Trivandrum)

AND

The Circle Secretary, National Federation of Post  
& Telegraph Employees, P&T House, Pulimood,  
Trivandrum-695001.

(By Sri. M. S. Vijaya Chandra Babu, Advocate, Trivandrum)

The Divisional President, Federation of National  
Postal Organisations, Postal Store Dept., Fort,  
Trivandrum Ex-parte.

The Vice President, Bhartiya Postal Employees  
Union, P.S. Depot, Fort, Trivandrum. Ex-parte

## AWARD

This industrial dispute has been referred for  
adjudication by the Government of India as per

787 GI/99-17.

The issue for adjudication is the following :

“Whether the action of the management of Chief Post Master General (Kerala), Trivandrum in unilaterally implementing a new scheme in place of Batch delivery system of Postal articles w.e.f. 4-4-1996 is justified? And whether the demands of the unions to defer the new scheme for atleast a month and to restore status-quo-ante as on 3-4-1996 are reasonable? If not, to what remedy the workmen are entitled?”

2. In answer to notice issued from this Tribunal union No. 1 alone appeared. Union Nos. 2 and 3 did not appear and hence set ex-parte. Union No. 1 has filed a claim statement. While the case was pending for reply statement of management, the management and counsel remained absent on 5-1-1999. Hence the case was adjourned for disposal to 25-1-1999. On that day also the management and counsel remained absent without any reason whatsoever. Hence the management was set ex-parte. The union has subsequently filed an affidavit in support of their case.

3. In the affidavit filed by the circle secretary of the contesting union, he has averred that there are three delivery systems of articles in five centres in Kerala viz; Trivandrum General Post Office, Kottayam, Ernakulam, Trissur and Kozhikode and there are two batches of Postmen, one batch carries the first and third deliveries that in this system both deliveries contain only unregistered articles that the other batch carrying the second delivery containing only accountable articles that the Director of Postal Service, New Delhi issued an order restructuring of deliveries of accountable article by introducing two delivery system and that this new scheme was formulated in 1990 and directions were issued to review the position in Post Offices in which restructuring scheme has been made in respect of deliveries. The further averment is that the Post Master General, Kerala decided to implementing the order issued in 1990 w.e.f. 4-4-96 without considering the order issued in 1991 modifying the 1990 order and directed all Postmen to sign in order book in token of having noted the order to implementing the two delivery system in five centres in Kerala and that the action of management in unilaterally implementing a new scheme in place of batch delivery system w.e.f. 4-4-1996 is illegal and unjustified.

4. In the absence of contest I accept the averment mentioned above and hold that the action of management is illegal and unjustified and the

management is directed to continue the batch delivery system of three deliveries in a day in the aforesaid five centres in Kerala.

An award is passed accordingly.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

का.आ. 899.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार महर्गांव डॉक लिमिटेड के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-3-1999 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14011/9/97-आई.आर. (डीयू.)]

के. वी. बी. उन्नी, अवसर सचिव

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 899.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mazagon Dock Limited and their workman, which was received by the Central Government on 5-3-99.

[No. L-14011/9/97-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Under Secy.

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BANGALORE

Bangalore, the 15th February, 1999

#### PRESENT :

JUSTICE R. RAMAKRISHNA,

Presiding Officer

C. R. No. 49/98

#### I PARTY :

The General Secretary,  
Mazagon Dock Limited,  
Employees Association,  
Panambur, Mangalore.

#### II PARTY :

The Deputy General Manager,  
Mazagon Dock Limited,  
Mangalore Yard, Panabur.

#### AWARD

1. The Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2A of Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 has referred this dispute vide Order No. L-14011/9/97/IR(DU) dated 28-5-1998 for adjudication on the following schedule.

#### SCHEDULE

"Whether the management of Mazagon Dock Limited is justified in denying promotion to Sri Suresh Chandra and Smt. Shantha w.e.f. 1-1-1992 ? If not, to what relief they are entitled for ?"

2. This reference is received on 28-5-98. A notice under ordinary post served to both parties. The second party represented through an advocate on 18-1-99. Due to the absence of the first party a notice under RPAD was issued. This notice duly served. The first party union who have espoused the cause of the workmen have not appeared and filed any claim statement. They have also conveniently flouted the mandatory provisions contained under Rule 10(B) of the Rules.

3. In view of the above circumstances this reference is rejected.

(Dicted to the stenographer, transcribed by her, corrected and signed by me on 15th February, 1999.)

JUSTICE R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1999

का.आ. 900.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सी एस डी कैंटीन के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-3-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14012/26/96-आई.आर. (डीयू.)]

के. वी. बी. उन्नी, अवसर सचिव

New Delhi, the 5th March, 1999

S.O. 900.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.S.D. Canteen and their workmen, which was received by the Central Government on 5-3-99.

[No. L-14012/26/96-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Under Secy.

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT  
DHANBAD.

## PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under  
Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

Reference No. 145 of 1997

## PARTIES :

Employers in relation to the management of  
Commandant, Bihar Regimental Centre,  
Danapur, Patna and their workman.

## APPEARANCES :

On behalf of the workman : Shri D. Mukherjee,  
Advocate.

On behalf of the employers : Shri C. S. Prasad  
Sinha, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Canteen.

Dated, Dhanbad, the 23rd February, 1999

## AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in  
exercise of the powers conferred on them under  
Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has re-  
ferred the following dispute to this Tribunal for  
adjudication vide their Order No. L-14012/  
26/96-IR(DU), dated, the 4th December, 1997.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of  
C.S.D. Canteen in terminating the ser-  
vices of Sh. Ajay Kumar is legal and  
justified ? If not, to what relief the  
workman is entitled to ?"

2. The record is put up today for order on the  
application filed by the management on 21-4-98  
challenging the maintainability of the reference and  
the written objection filed against the application  
on the side of the workman and heard on 21-12-98.

3. The management by the above mentioned  
petition has challenged the maintainability on the  
ground that as the concerned workman is not at  
all a workman within the definition of Section  
2(s) of the I.D. Act, 1947 and at the same  
time the Bihar Regimental Centre, Danapur does  
not come under the definition of "Industry" within  
the meaning of Section 2(j) of the said Act and as  
such the present reference is not maintainable. In  
addition the management side has also claimed  
that as the workman agitated the point mentioned  
787 GI/99—18.

in the W.S. before Hon'ble High Court of Judica-  
ture at Patna by filing a Writ Petition challenging  
the order of termination of his service which was  
numbered as C.W.J.C. No. 4573 of 1994 and de-  
cided by the Hon'ble High Court by order dated  
7.3.95 on merit rejecting the said application, the  
present reference is hopelessly barred by res judi-  
cata and on that ground also the present reference  
is liable to be disposed of as being not maintain-  
able.

4. The workman side by filing a written objec-  
tion has disputed the contention on the side of the  
management by challenging the contents of para-1  
and 2 of the application as false, frivolous and  
motivated and in respect of para 3 to 5 of the  
application it has been submitted that due to wrong  
advice of Advocate the Writ Petition was presented  
before the Hon'ble High Court challenging the  
legality, etc., of the order of termination of service  
of the concerned workman although the Hon'ble  
High Court rightly rejected the Writ Petition for  
want of jurisdiction to decide the question of facts  
and in respect of contents of para-6 of the appli-  
cation the workman side has claimed that in view  
of the decisions of Hon'ble Supreme Court and  
Hon'ble High Court of Patna that any move for  
hearing preliminary point shall be rejected and as  
it is a nasty affairs on the part of the management  
with a view of cause delay. In support of the con-  
tention learned Advocate on the side of the work-  
man has placed reliance upon a decision of Hon'ble  
Supreme Court reported in 1983 Lab I. C. page  
1629, 1983 Supreme Court cases page 510 and  
decision of Hon'ble Patna High Court reported in  
Bihar Revenue and Labour Journal October, 1981  
page 219 between Indian Oil Corporaion Vrs.  
State of Bihar & others and by relying those deci-  
sions the workman side has prayed for rejecting  
the application filed on the side of the management  
challenging the maintainability of the present re-  
ference.

5. Learned Advocate on the side of the manage-  
ment by drawing my attention to the Hon'ble Court  
order passed in above mentioned Civil Writ Juris-  
diction No. has submitted that in fact as admitted  
on the side of the workman in their written objec-  
tion moved the Hon'ble High Court by challenging  
the order of termination of services wherein the  
Hon'ble Court was pleased to hold that as the ap-  
pointment of the concerned workman was not by  
way of following any particular procedure for ap-  
pointment but by virtue of an agreement and since  
in the agreement there was no clause of hearing  
the petitioners i.e. the concerned workman and  
thereby giving him opportunity of being heard  
before termination of his service the writ appli-  
cation was devoid of any merit and the same was  
rejected. On the other hand learned Advocate on  
the side of the workman simply by relying in the

decisions noted in the written objection prays for disposal of the reference on merit without deciding the same on preliminary point of maintainability. It is in the written objection that the concerned workman moved the Hon'ble High Court in the Writ Jurisdiction challenging the legality etc. of the order of termination but under the wrong advice of certain Advocate the same to my mind cannot give any rise to the concerned workman to move another forum for decision similar points already adjudicated by the Hon'ble High Court. The question in issue in the present reference was also in issue before the Hon'ble High Court in the above mentioned C.W.J.C. and when the same issue has already been decided by the Hon'ble High Court by an order against the concerned workman, I am unable to hold that the concerned workman is entitled to agitate the same question in issue in another forum i.e. the present Tribunal by raising the dispute under the provision of Industrial Disputes Act, 1947. It has no where been mentioned if at the time of raising the dispute the fact of filing the writ application before the Hon'ble High Court, the decision of the Hon'ble High Court etc. were brought to the notice of the authority and if the Central Govt. in the Ministry of Labour after giving due consideration to all those factor formed an opinion about the existence of an Industrial Dispute for which the Ministry has referred the same to this Tribunal for adjudication. In the absence of any such materials and where the question has already been decided by the Hon'ble High Court I cannot but hold that the present reference is in fact hopelessly barred by the principles of res judicata even in case I ignore the definition of workman and consider the question if the management of C.S.D. canteen an "Industry". It is therefore ordered that the present reference is not at all maintainable and the same is disposed of accordingly.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999

का. घा. 901.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुवर्ण में, केन्द्रीय सरकार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मुम्बई के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवर्ण में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. II, मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11-3-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.—40012/31/98—आई आर ( डी यू )]  
के. बी. बी. उन्नी, अवर सचिव

New Delhi, the 11th March, 1999

S.O. 901.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the

Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. II, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd., Mumbai and their workman, which was received by the Central Government on the 11-3-99.

[No. L-40012/31/98-IR(DU)]  
K. V. B. UNNY, Under Secy.

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-2/152 of 1998

Employers in relation to the management of The  
Chief General Manager, Mahanagar Telephone Nigam Ltd.,

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer : No Appearance.

For the Workmen : No Appearance.  
Mumbai, dated 18th February, 1999

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-40012/31/98]IR(DU), dated 13-11-98, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Mahanagar Telephone Nigam Ltd., Mumbai by illegally terminating the services of workman, Shri Ramesh R. Gaikwad is legal and justified ? If not, what relief the workman is entitled to ?"

2. The order of reference was send to the workman by the Desk Officer when it send the order of reference to this Tribunal. After receipt of the reference the Tribunal had also issued notices to the concerned parties. So far as the management is concerned it was duly served. But, so far as the workman is concerned the envelope came back with an postal endorsement not claimed. The address on the envelope and the address mentioned in the reference is one and the same. From the conduct it appears that the workman is no more interested in prosecuting the matter. In the result I pass the following order :

#### ORDER

The reference is disposed of for want of prosecution.

S. B. PANSE, Presiding Officer



नई दिल्ली, 11 मार्च, 1999

## II PARTY

Superintendent of Post  
Offices, Bidar Division,  
BIDAR-585 401.

## AWARD

1. The Central Government by exercising the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2A of the section 10 of the Industrial disputes Act, 1947 has referred the dispute vide Order No. L-40012/82/96-IR(DU) dated 2-3-98 for adjudication on the following schedule.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Supdt. of post offices, Bidar Division, Bidar in terminating the services of Sri Abdul Hameed w.c.f. 3-2-94 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. This dispute was registered and notices are issued to the parties. Notice was duly served and the first party appeared on 20-11-98. The second party is now represented by a learned advocate.

3. From 20-11-98 this dispute is adjourned on six occasions to file the claim statement, but the first party has not filed the claim statement and he started absents himself from the court. The learned advocate has filed vakalatnama to the first party on 17-12-98. He has also expressed his inability to file the claim statement due to non-approach of the first party.

4. Since we have given sufficient opportunity to the first party who has failed to file the claim statement the case can not be adjudicated on its merits. Though the burden of proof is on the second party unless and until the first party files his claim statement the adjudication can not take place.

5. In view of these circumstances this reference is rejected.

(Dictated to the stenographer, transcribed by her, corrected and signed by me on 26th February, 1999.)

JUSTICE R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

का. आ. 902:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिदर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलूर के पंचाट से प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 11-3-99 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन.—40012/82/96—आई आर (डी यू)]

के. वी. बी. उन्नी, अवसर सचिव

New Delhi, the 11th March, 1999

S.O. 902.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Supdt. of Post Offices, Bidar and their workman, which was received by the Central Government on 11-3-99.

[No. L-40012/82/96-IR(DU)]  
K. V. B. UNNY, Under Secy.

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR  
COURT BANGALORE

Dated 26th February, 1999

## PRESENT :

Justice R. Ramakrishna, Presiding Officer.

C. R. NO. 17/1998

## I PARTY

Shri Abdul Hameed,  
S/o Md. Jalaluddin,  
C/o Abdul Rafeeq,  
Alibagh, H. No. 1-3-66,  
BIDAR-585 401.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1999

का. आ. 903:—उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 430 दिनांक 13 फरवरी, 1989 का अधिष्ठापन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित विनिदिष्ट अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उनके सामने तस्थानी प्रबिष्टियों में विनिदिष्ट क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र के लिए तथा ऐसे सभी स्थापनाओं के संबंध में, जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। नियंत्रक प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है।

## अनुसूची

क्र. सं.	अधिकारी	क्षेत्र
1	2	3
1.	अजमेर, जयपुर और कोटा के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	राजस्थान राज्य
2.	आसनसोल और रानीगंज के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	पश्चिम बंगाल राज्य में वर्दमान, वीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के जिले।
3.	अहमदाबाद, आदिपुर तथा बड़ोदरा ( बड़ौदा ) के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय )	गुजरात राज्य और दादर, नागर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र।
4.	बंगलौर, मंगलूर, बैल्लरी तथा हुबली के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	कर्नाटक राज्य।
5.	भुवनेश्वर और राउरकेला के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय )	उड़ीसा राज्य।
6.	मुम्बई, वास्को डी गामा और पुणे के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	(i) महाराष्ट्र राज्य ( नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वरधा, बुलधाना, जलगांव, चन्द्रापुर, गढ़चिरोली, नानदेड, परमानी, यवतमाल, ओसमानाबाद, लातूर तथा शिव सिविल जिलों को छोड़कर )। (ii) गोवा राज्य।
7.	कलकत्ता के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय )	पश्चिम बंगाल, ( वर्दमान, वीरभूम, बांकुरा और पुरुलिया के सिविल जिलों को छोड़कर ), सिक्किम और अरुणाचल एवं निकोबार द्वीप संघ राज्य।
8.	कर्नाकुलम, कोचीन और त्रिवेन्द्रम के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय )	केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र।
9.	चण्डीगढ़, जम्मू और फरीदाबाद के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्य और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
10.	धनबाद, हजारीबाग, खाईवासा व रांची के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय )	बिहार राज्य ( पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, वैशाली, सारण, सिवान, भाँजपुर, रोहतास, पटना, नालन्दा, पलामू और श्रीरंगबाद सिविल जिलों को छोड़कर )।
11.	गुवाहाटी, डिब्रुगढ़ और सिलचर के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय )	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य।
12.	हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और मन्चेरियल के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय )	आन्ध्र प्रदेश राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में यानम का क्षेत्र
13.	जबलपुर, जगदलपुर, भोपाल, रायपुर, शहडोल, बिलासपुर और छिंदवाड़ा के सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय )	मध्य प्रदेश राज्य।
14.	कानपुर, लखनऊ, देहरादून और इलाहाबाद के सहायक श्रमायुक्त ( के. )	उत्तर प्रदेश राज्य।

1	2	3
15. चेन्नई व मदुरई के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी का संघ राज्य क्षेत्र (यानम को छोड़कर)।	
16. नागपुर और चन्द्रापुर के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वरधा, बुलढाना, जलगांव, चन्द्रापुर, गवचिरोली, नानडेड परमानी योगतमाल, ओसमानाबाद, लातूर, और बिड के सिविल जिले।	
17. नई दिल्ली के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।	
18. पटना के सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	बिहार राज्य के पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगुसराय, वैशाली, सारण, सिवान, भोजपुर, रोहतास, पटना, नालन्दा, पलामू और श्रीरंगबाद के सिविल जिले।	
19. नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के अधीन सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय)	सम्पूर्ण भारत	

[संख्या एस-42011/3/97-एम. एस.-II]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 17th March, 1999

S.O.903.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Payment of Gratuity Act, 1972, (39 of 1972) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 430 dated 13th Feb. 1989. Central Government hereby appoints the officers mentioned in Column (2) of the Schedule specified hereunder to be the Controlling Authorities for the area/Jurisdiction as specified in column (3) of the said schedule in relation to all establishments for which the Central Government is the appropriate Government under clause (a) of section 2 of the said Act.

## SCHEDULE

Sl. No.	Officers	Area
1	2	3
1.	Assistant Labour Commissioners (Central) Ajmer, Jaipur and Kota.	The State of Rajasthan.
2.	Assistant Labour Commissioners (Central) Asansol and Raniganj.	The districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the state of West Bengal.
3.	Assistant Labour Commissioners (Central) Ahmedabad, Adipur and Vadodra (Baroda)	The State of Gujarat and Union Territories of Dadra, Nagar Haveli, Daman & Diu.
4.	Assistant Labour Commissioners (Central) Bangalore, Mangalore, Bellary and Hubli.	The State of Karnataka.
5.	Assistant Labour Commissioners (Central) Bhubaneswar and Rourkela.	The State of Orissa.

1	2	3
6. Assistant Labour Commissioners (Central) Mumbai, Vasco-De-Gama and Pune.		(i) The State of Maharashtra excluding the following Civil Districts : — Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, and Bid. (ii) State of Goa.
Assistant Labour Commissioners (Central) Calcutta.		The State of West Bengal (excluding the Civil districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia) Sikkim and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands.
8. Assistant Labour Commissioners (Central) Ernakulam, Cochin and Trivandrum.		The State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep.
9. Assistant Labour Commissioners (Central) Chandigarh, Jammu and Faridabad.		The State of Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, and Jammu & Kashmir and the Union Territory of Chandigarh.
10. Assistant Labour Commissioners (Central) Dhanbad, Hazaribagh, Chaibasa and Ranchi		State of Bihar excluding the following Civil Districts East Champaran, West Champaran, Sitamari, Madhubhani, Saharsa, Purnia, Katihar, Dharbhanga, Samastipur, Muzaffarpur, Gopalganj, Begusarai, Vaishali, Saran, Siwan, Bhojpur, Rohtas, Patna, Nalanda, Palamu, Aurangabad.
11. Assistant Labour Commissioner (Central) Guwahati, Dibrugarh and Silchar.		The State of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh and Mizoram.
12. Assistant Labour Commissioner (Central) Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada and Mancheri.		The State of Andhra Pradesh and the area of Yanam in Union Territory of Pondicherry.
13. Assistant Labour Commissioners (Central) Jabalpur, Jagdalpur, Bhopal, Raipur, Shahdol, Bilaspur and Chhindwara.		The State of Madhya Pradesh.
14. Assistant Labour Commissioners (Central) Kanpur, Lucknow, Dehradun and Allahabad		The State of Uttar Pradesh.
15. Assistant Labour Commissioners (Central) Chennai and Madurai		The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry (except Yanam)
16. Assistant Labour Commissioners (Central) Nagpur and Chandrapur.		The Civil district of Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur and Bid of the State Maharashtra.
17. Assistant Labour Commissioners (Central) New Delhi.		NCT of Delhi.
18. Assistant Labour Commissioners (Central) Patna		The Civil Districts of West Champaran, East Champaran, Sitamari, Madhubani, Saharsa, Purnia, Katihar, Dharbhanga, Samastipur, Muzaffarpur, Gopalganj, Begusarai, Vaishali, Saran, Siwan, Bhojpur, Rohtas, Nalanda, Patna, Palamu and Aurangabad of the State of Bihar.
19. Assistant Labour Commissioners (Central) Under Chief Labour Commissioner (Central) at the Headquarter in New Delhi.		Whole of India.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1999

का.आ. 904.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 अप्रैल, 1999 को उक्त अधिनियम के रूप में निम्न करती है, जिसको उक्त अधिनियम के प्रत्यय-4 (धारा 14 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्या-5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (i) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध अथवा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“कामरूप जिले में मौजा तथा तालुक पंडूरी में तुलसीबाड़ी तथा रंगिया टाउन के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ” ।

[संख्या एस-38013/7/99-एस.एस.-1]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

New Delhi, the 19th March, 1999

S.O. 904.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st April, 1999 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (i) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Assam namely :

“Areas comprising the revenue village of Tulsibari and Rangia Town in Mouza & Taluk Panduri in Kamrup District”.

[No. S-38012/7/99-SS-I]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1999

का.आ. 905.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि कोयला उद्योग में सेवाओं को जिन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 04 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल

तत्काल से उक्त माम की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एन-11017/2/97-आई.आर. (पी. एल.)]

एच. सी. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 16th March, 1999

S.O. 905.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Coal Industry which is covered by item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/2/97-I.R. (PL)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1999

का.आ. 906.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के अर्थ मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2142 दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 द्वारा दिल्ली दूध योजना को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अक्टूबर, 1998 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था:

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 अप्रैल, 1999 में छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[का. सं. एस-11017/07/97-आई.आर. (पी. एल.)]

एच. सी. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 17th March, 1999

S.O. 906.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2142 dated 22nd October, 1998 the industry for the supply of milk under the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 24th October, 1998;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 24th April, 1999.

[No. S-11017/7/97-I.R.(PL)]

H. C. GUPTA, Under Secy.